सम्पादकीय

बांग्लादेश मामले में कूटनीति व राजनीति पर एक कदम आगे निकली ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर केंद्र की भाजपा नीत सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों को लेकर तुष्टीकरण से लेकर बंगाल में बांग्लादेशियों को शरण देने का आरोप लगाया जाता रहा है। लेकिन इन दिनों बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और मीडिया में उक्त खबरें हर रोज आ रही है। ऐसे में भले ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी का उक्त मुद्दे पर कोई बयान नहीं आया है लेकिन ममता बनर्जी ने सशक्त तौर पर इस अंतरराष्ट्रीय मुद्दे को उठाया है और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार को नाकाम तक करार दिया है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश से उपजे एक बयान का जवाब देते हुए साफ कहा कि, अगर वह लोग बिहार, बंगाल ओडिशा जैसे हमारे देश के राज्यों पर कब्जे की बात करेंगे तो वह बैठकर लॉलीपॉप नहीं चूसेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेहद गंभीर और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कही। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राज्य विधानसभा में कहा कि, बांग्लादेश के हालात पर यूएन हस्तक्षेप करे और वहां विशेष शांति सेना भेजे। भारत हमेशा से विश्व में शांति का प्रतीक रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस समय बांग्लादेश में टकराव का माहौल बन गया है। इसे निपटाने के लिए अंतरिम यूनुस सरकार नाकाम नजर आती है। ऐसे में शांति सेना भेजकर वहां पर शांति स्थापित की जाए। ममता बनर्जी ने उक्त अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़े होने की बात करते हुए यह साबित कर दिया है कि वह राजनीति से लेकर कूटनीति के मामलों में एक सफल नेता हैं और उन्हें पता है कि कब क्या करना चाहिए। साथ ही तृणमूल प्रमुख ने समाज को यह भी संदेश दिया कि, कुछ लोग आपसी सद्भावना को खराब कर सकते हैं ऐसे में शांति और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। देखा जाए तो बांग्लादेश के मामले पर मोदी सरकार से हिंदू समाज जिस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था वह नहीं दिखा। यह अलग बात है कि पीएम भले ही सामने नहीं आए हों लेकिन केन्द्र ने बंग्लादेश को संकेत में बता दिया है कि मामले पर भारत की आंखें बंद नहीं है। जबकि आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ केंद्र सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। कांग्रेस ने भी मुद्दे पर अपना पक्ष सामने रख दिया है। लेकिन देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी राजनीति से लेकर कूटनीति के मामलों में एक कदम आगे निकल गई है। ममता बनर्जी जब सांसद थी तब भी बंगाल में वामपोंथों के शासन के दौरान बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठा चुकी है। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद भी बंगाल में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठता रहा है। वैसे देखा जाए तो भाजपा के केन्द्रीय नेताओं के मुकाबले में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार अत्याचार के मामले पर बंगाल भाजपा के नेता भी लगभग मौन ही है। लेकिन बंगाल में नेता प्रतिपक्ष व भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी जोरदार तौर पर उक्त मामले पर विरोध व्यक्त कर रहें हैं।

आम जनता संविधान संशोधनों का इतिहास आरोप प्रत्यारोप पर नहीं बल्कि विजन 2047 के संविधान का रोडमैप जानने में रुचिकर है?

अगर हम संविधान पर चर्चा में विपक्ष के नेता के संबोधन की करें तो,शनिवार को संसद में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने सावरकर का ज़िर किया और कहा, सावरकर ने लिखा है कि भारत के संविधान के बारे में सबसे खराब चीज़ ये है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है।वेदों के बाद मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पूजनीय है और ये प्राचीन समय से हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है, आज जो मनुस्मृति क़ानून है उन्होंने जो कहा वो सावरकर के शब्द हैं।उन्होंने कहा, सावरकर ने अपने लेखन में साफ कर दिया है कि हमारे संविधान में भारतीयता का कोई अंश नहीं है।

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के निचले सदन संसद लोकसभा में 13-14 दिसंबर 2024 को संविधान पर चर्चा को पूरी दुनियाँ ने देखा जो अब 16-17 दिसंबर 2024 को उपरी सदनराज्यसभा में भी होगी। लोकसभा की चर्चा पर मैंने दोनों दिन बारीकी से पैनी नज़र रखी व 14 दिसंबर 2024 को माननीय पीएम के जवाब के बाद सोशल इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया प्लेटफार्मस पर लगातार डिबेट मुलाकातें वदर्शकों द्वारा कमेंट्स का जोरदार दौर चल पड़ा जिसमें मैंने देखा कि बहुतेक विश्लेषकों कमेंट्स कर्ताओं को चर्चा का मकसद समझ नहीं आया, क्योंकि इसमें हर राजनीतिक दल, संविधान संशोधन के इतिहास की बातकर एक दूसरे दल की टांग खिंचाई एक दूसरे के संशोधनों को गैरवाजबी व मतलबी संशोधन की संज्ञा देते रहे, तो किसी ने इसको इतिहास की क्लास की संज्ञा दी। मैंने विशेषण किया तो मुझे भी इस पर सार्थक चर्चा नज़र नहीं आई क्योंकि सभी दल एक दूसरे के द्वारा किए गए संशोधनों पर उंगली उठा रहे थे, इस पार्टी या व्यक्ति ने इतने, तो उस पार्टी या व्यक्ति ने उतने संशोधन किया। विशेष रूप से विपक्षी नेता के 25 मिनट के संबोधन में बहुत समय पीएम उपस्थित नहीं थे, तो वही 1 घंटा 50 मिनट के पीएम के संबोधन में कुछ समय विपक्षी नेता उपस्थित नहीं दिखे, परंतु इन सब से हटकर किसी ने भी ऐसा विचार व्यक्त नहीं किया कि आओ विज़न 2047 को रेखांकित कर हम संविधान में इस तरह का संशोधन करें कि विज़न को शीघ्रअपनी डेट लाइन से पहले सार्थक सफल बनाने के लिएसंविधान में संभावित संशोधन कर रणनीति बनाएं ताकि हम इस लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकें। मुझे उम्मीद है कि 16-17 दिसंबर 2024 को उच्चसदन राज्यसभा में इसपर सार्थक चर्चा जरूर होगी।क्यूँकि लोकसभा में 13-14 दिसंबर 2024 को संविधान, पर चर्चा इतिहास की क्लास लगी अब राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को चर्चा पर दुनियाँ की नज़रें लगी है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,चर्चा-ए-संविधान, एट द रेटऑफ़ सांसद...जनता समझ नहीं पाई मकसद..।

भारत को इस किताब (संविधान) से नहीं बल्कि इस किताब (मनुस्मृति) से चलाया जाना चाहिए।उन्होंने कहा,आज इसी की लड़ाई है, मैं सत्ता पक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप सावरकर के शब्दों का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब आप संविधान के पक्ष में संसद में बोलते हैं तो आप सावरकर का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उनको बदनाम कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में इसके अलावा अग्निवीर , पेपर लीक, किसानों और उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहा।उन्होंने कहा,आप महात्मा गांधी, पेरियार और दूसरे महान नेताओं की तारीफ़ करते हैं लेकिन हियकिघाते हुए, सच तो ये है कि आप भारत को उसी तरह से चलाना चाहते हैं जैसे पहले चलाया जाता था।उन्होंने महाभारत के पात्र एकलव्य का ज़िक्र किया और कहा,जैसे एकलव्य ने तैयारी की थी, वैसे ही हिंदुस्तान के युवा सुबह उठकर अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जब आपने अग्निवीर लागू किया, तब आपने उन युवाओं की उंगली काटी,जब पेपर लीक होता है, तब आप युवाओं काअंगूठा काटते हैं।उन्होंने दिल्ली की सरहदों के पास किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में कहा आज आपने किसानों पर आंसू गैस चलाया है,किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करते हैं, लेकिन आप अडानी-अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं।ये करीब 25 मिनट बोले।उनके बयान पर युवा मामलों के मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा-आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं। आपको सरकार में तो सिखों के गले काटे गए, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। साथियों बात अगर हम माननीय पीएम द्वारा 14 दिसंबर 2024 को जवाबी संबोधन की करें तो, इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की, उन्होंने कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही,सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाईं और अनुच्छेद 370 पर भी बात की, उन्होंने परिवार का नाम नहीं लिया,लेकिन कहा कि कांग्रेस के एक परिवार ने हर स्तरपर देश को चुनौती दी है,उन्होंने कहा,इसलिए 75 साल में 55 साल एक परिवार ने राज किया,इसलिए देश में क्या-क्या हुआ ये जानने का सबको अधिकार है।उन्होंने कहा,1947 से 1952 तक इस देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी।चुनाव नहीं हुए थे, एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में खाका खड़ा किया गया था।1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था,राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश भी नहीं था उसके बावजूद 1951 में जब चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने संविधान को बदला और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला किया गया ये संविधान निर्माताओं का अपमान था।उन्होंने अपने संबोधन में जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लिया और कहा कि करीब छह दशक में 75 बार संविधान बदला गया।जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था,उस बीज को खाद-पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया।1971 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया थाउस फैसले को संविधान बदलकर पलट दिया गया और1971 में संविधान संशोधन किया गया था।उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे।पीएम ने पूर्व पीएम का नाम लेते हुए कहा, इंदिरा जी के चुनाव को गैर नीति के कारण अदालत ने खारिज कर दिया और उनको एमपी पदछोड़ने की नौबत आईतो उन्होंने देशपर इमरजेंसी थोप दी,अपनी कुर्सी बचाने के लिए,इतना ही नहीं 1975 में 39वां संशोधन किया, उसमें राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के खिलाफ़ कोर्ट कोर्ट में नहीं जा सकता।उन्होंने शाह बानो मामले का ज़िक्र किया और कहा,यहां बैठे कई दलों के मुखिया को भी जेलों में ठूंस दिया गया था। राजीव गांधी जी ने संविधान को एक और गंभीर झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो का जजमेंट दिया था। कोर्ट से एक वृद्ध महिला को उसका हक़ मिला था, राजीव गांधी ने शाह बानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को, नकार दिया।उन्होंने वोट बैंक की राजनीति की खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया।न्याय के लिए तड़प रही एक महिला की बजाय उन्होंने कट्टर पंथियोंका साथ दिया,संसद में क़ानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को एक बार फिर पलट दिया गया उनकी सरकार देश में समान नागरिक संहिता लाने को कोशिश कर रही है।देश में समान नागरिक संहिता के विषय पर भी संविधान सभा में चर्चा हुई थी बहस के बाद निर्णय लिया गया कि जो भी सरकार चुनकर आएगी वो इस पर निर्णय लेगी और इसे लागू करेगी।धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की वकालत की गई उसके संविधान सभा की बहस में के.एम. मुंशी जी ने कहा था कि समान नागरिक संहिता को लाना राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफार्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए,संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से समान नागरिक संहिता को लाने में लगे हुए हैं।पीएम ने लोकसभा में 11 संकल्प रखे थे संकल्प है। हम इसी के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं (1) सभी नागरिक और सरकार अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें।(2) हर क्षेत्र और समाज को विकास का समान लाभ मिले, सबका साथ, सबका विकास' की भावना बनी रहे।(3) भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और भ्रष्टाचारियों को सामाजिक स्वीकार्यता समाप्त हो। (4)देश के कानूनों और परंपराओं के पालन में गर्व का भाव जागृत हो।(5) गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिले और देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व किया जाए। (6) राजनीति को परिवारवाद से मुक्त कर लोकतंत्र को सशक्त बनाया जाए।(7) संविधान का सम्मानहो और राजनीतिकस्वार्थ के लिए उसे हथियार न बनाया जाए।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कार्य विधि तथा उसे पूरा करेंगे। आज आप पर व्यवसाय हावी है कि अपनी लीडर के ऐसे सौहार्द्र बना है, जहां आपको विदेशे कुशल होंगे और दुनी तरक्की, अपनी शिक्षा बढ़ाने वालेके, संबंधित लेखा पढ़ेंगा। तब न किसी हमारे उपाय में और उन्नति खुशी को सुनकर आज व्यवसायका उन्नत को समझना वालेके, संबंधित परिवारीय संबंधों में लो, जहां तक व्यवसायका हमें लाभ और कामीना से लाभ प्राप्त होगा

मेष
आज आपको तन-मन में किसी बात का डर बना रहेगा। सगे-सम्बंधियों के साथ संघर्ष आपको विचलित कर सकते हैं। माता का स्वास्थ्य खराब होने की आशंका है। आर्थिक हानि और समाज में अपयश मिलने की संभावना है।

वृष
मानसिक शांति और आनंद प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों के साथ आपके संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। आपके यहां मेहमान, मित्र तथा सगे-सम्बंधी आने से आनंद का अनुभव होगा। किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा।

मिथुन
आज आप समाज, मित्रों से सम्बंधित कार्यों में व्यस्त रहेंगे। उनके लिए पैसे भी खर्च हो सकते हैं। आज किसी खास व्यक्ति के साथ मिलना हो सकता है। विवाह योग्य जातकों के पास वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावना है।

कर्क
सोचे अनुसार काम नहीं हो सकेगा। आपके मन में चिंता रहेगी। ऑफिस में सहकर्मी आपको निराश करेंगे। उच्च अधिकारियों के साथ किसी भी विवाद को आज टालें अन्यथा नुकसान होगा। आज विरोधियों से भी बचकर रहें। पेट की तकलीफ हो सकती है।

सिंह
आज आप कल्पना और सृजनशीलता का अच्छा उपयोग कर सकेंगे। आप अपने बच्चों की अच्छी प्रगति से संतोष का अनुभव करेंगे। आपको गलत संघर्ष या विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। पेट की तकलीफ हो सकती है।

कन्या
आपके घर-परिवार में सुख-शांति रहेगी। इस कारण मानसिक प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आपके जीवन में कुछ सुखद प्रसंग बन सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सकेंगे। बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा।

तुला
आज आप नए काम की शुरुआत कर सकेंगे। भाग्य आपके साथ है। उनकी आय बढ़ेगी और नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। आप सरकार की तरफ से लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में मेल-जोल बना रहेगा।

वृश्चिक
वाणी पर संयम रखेंगे, तो बहुत सी कठिनाइयों से बच सकेंगे। परिजनों के साथ छोटे-मोटे मतभेद आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ करेंगे। शेयर या सट्टे में आप पूंजी निवेश कर सकेंगे। मानसिक भय और असंतोष का अनुभव होगा।

धनु
उग्रता और नकारात्मकता आपके मन को बेचैन कर देंगे। खान-पान में सावधानी रखना आवश्यक है। खर्च बढ़ने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। नए सम्बंध आपको कठिनाई में डाल सकते हैं।

मकर
उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा करके आपका उत्साह बढ़ाएंगे। जो कार्य विलंबित हैं, वे पूरा कर सकेंगे। पति-पत्नी के बीच रोमांस बना रहेगा। आज आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। थकान और सुस्ती अनुभव करेंगे।

कुंभ
वित्तीय लाभ होने की संभावना है। काम में सभी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। अपने विरोधियों का पूरी क्षमता के साथ सामना कर सकेंगे। भाग्य आपके साथ है। आज बौद्धिक काम और चर्चा आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।

मीन
आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा मतभेद होने से आप दुःख का अनुभव करेंगे। पति अथवा पत्नी की तबीयत खराब होने की आशंका बनी रहेगी। दोस्तों से मिलकर आप बहुत खुशी अनुभव करेंगे। आज परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी। मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

स्व: जय सिंह नाथावत (पुलिस अधिकारी)

नमस्कार मित्रों हमारी आज की शख्सियत कॉलम में हम एक ऐसी शख्सियत को बताने जा रहे है जोकि पुलिस के लिए ही समर्पित रहे। वैल पुलिसिंग क्या होती है,पुरानी पुलिसिंग क्या होती है ये नए पुलिस अधिकारियों को समझनी चाहिए खास कर उन पुराने पुलिसकर्मियों से जिन्होंने बिना संसाधन के अपराध पर अंकुश लगाकर अपराधियों को उनके असली ठिकाने पहुँचाया। एक ऐसा ही नाम है स्व. जयसिंह नाथावत साब का जीवन दर्शन। बेहद सुलझे और शानदार पुलिस अधिकारी के रूप में राजस्थान में उन्हें जाना जाता है। मुखबिर वाली पुलिससिंग के लिए नाथावत जी बेहद प्रसिद्ध रहे थे। अनके थानों में सब इंस्पेक्टर रहते हुए थानाधिकारी रहे उसके बाद सीआई बने और बड़े पुलिस थानों में पोस्टेड़ रहे लम्बे समय डिप्टी एसपी रहे और पदौन्नत होकर एडिशनल एसपी बने और कोविड़ के दौरान ईश्वर को प्यारे हो गए। इनकी शानदार पुलिसिंग के किस्से आजकल के पुलिस कर्मियों व पुलिस अधिकारियों को सुनने चाहिए ताकि वे पुलिसिंग समझ सकें। जयसिंह भिवाड़ी के नए थानाधिकारी बने तो एक नामी बदमाश था जिसे पुलिस द्वारा अरेस्ट करना था। जयसिंह जी ने उस बदमाश युवक के बारे में काफी सुना हुआ था। पुलिस की स्पेशल सेल के सिपाहियों द्वारा उस युवक के बारे में जयसिंह जी ने पूरी जानकारी ली तो पता चला कि बदमाश पुलिस से नहीं डरता। तो जयसिंह जी ने उसके पास रहने वाले बदमाश किस्म के युवकों को पकड़ लिया और उन्हे थाने ले आए उसकी पूछताछ के लिए और उनसे कहा कि उसे तो ढूंढ ही लूंगा चाहे किसी भी कोने में दुबक जाए मेरा नाम जयसिंह है उससे कहना पता कर ले मेरे बारे में और ये कह कर उन युवकों को छोड़ दिया ताकि वे मैसेज कर सकें वहां जाकर। मुखबिर की सूचना से पता चल गया कि अमुक बदमाश अपने घर पर ही है तो जाते के साथ उसके घर पहुँच गए और गेट बजाकर उसे पुकारा ,पुलिस को देखकर घर वाले बोले वो तो बाहर गया है यहां नहीं है। जयसिंह जी को पता था कि बदमाश भीतर ही छिपा हुआ है तो बोले कि आए तो सीधे थाने भेज देना नहीं तो उल्टा पटक कर ले जाऊंगा उसे। उसके बाद ऐसे ही तीन चार बार कर ड़ाला बदमाश अब डरने लग गया जिसे पुलिस से डर नहीं लगता था वो अब पुलिस से डरने लगा। इनके ओढर में ट्रेनिग लेने वाले आईपीएस अधिकारियों ने जब पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो वे बोले कि यदि इसे पकड़ लिया तो कोर्ट में पेश करेंगे वहां से जेल होगी तो पुलिस का खौफ नहीं बनेगा। ऐसे करने पर बदमाश की हिम्मत टूटेगी और वो तौबा करेगा बदमाशी से। कुछ दिन बाद बदमाश पुलिस की गाड़ी की आवाज और वर्दी वाली पुलिस से खौफ खाने लगा। काफी दिन ऐसे ही ड्रामा चलता रहा और एक दिन उसे जयसिंह जी उठा लाए। उसे पकड़ा और कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया लेकिन पुलिस के प्रति उसका खौफ बरकरार रहा। ऐसे अनेकों किस्से हैं दोस्तों जहां ये पता चलता है कि पुरानी पुलिसिंग क्यों कारगर थी अपराध को रोकने में। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम का ये आलेख उनके लिए समर्पित है।

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

16 दिसंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- जापान के माउंट फुजी पर्वत में 1707 में अंतिम बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ।
- ग्रेट नॉर्थ हॉलैंड नहर 1824 में खोली गयी।
- ब्रिटिश संसद की अधिकार घोषणा को राजा विलियम तथा रानी मेरी ने 1889 में स्वीकार कर शासन में जनता के अधिकार को मान्यता दी।
- चीन में 1920 में आए भूकंप के कारण से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई यह भूकंप चीन के कान्सू प्रांत में आया था।
- आस्ट्रेलिया के महान् बल्लेबाज सर डान ब्रैडमैन ने 1927 में न्यूसाउथ वेल्स और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच से अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की।
- कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम ने 1929 में हुगली नदी के भीतर नहर की खुदाई आरंभ की।
- जर्मन रसायनशास्त्री ओटो हान ने 1938 में यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन की खोज की।
- जापान के दो बार प्रधानमंत्री फुमिमारो कनोए ने 1945 में युद्ध अपराधों का सामना करने की बजाए आत्महत्या कर लिया।
- हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय की 1951 में स्थापना की गयी।
- कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में 1958 में एक गोदाम में लगी भीषण आग में 82 लोगों की मौत।
- पश्चिमी पाकिस्तान के लोयारय दर्रे में 1959 में भारी बर्फबारी से 48 लोगों की मौत।
- अमेरिका के न्यूयार्क शहर में 1960 में हुए दो विमानों की टक्कर के कारण 136 लोग मारे गए।
- भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में संघर्ष विराम पर सहमति के बाद बंगलादेश पाकिस्तान से पृथक् होकर स्वतंत्र राष्ट्र बना।
- तमिलनाडु के कलपक्कम में 1985 में पहले फास्ट ब्रीडर रेक्टर रिएक्टर (एफबीटीआर) की स्थापना।
- नयी दिल्ली में 1993 में 'सभी के लिए शिक्षा' सम्मेलन प्रारम्भ।
- गोलन पहाड़ी के मुद्दे पर 1999 में सीरिया-इस्रायल वार्ता विफल।
- नेपाल में अंतरिम संविधान को 2006 में अंतिम रूप दिया गया। इसके तहत राजा ज्ञानेन्द्र को देश के प्रमुख के पद से हटा दिया गया।
- बांग्लादेश ने 2007 में पाकिस्तान से मुक्ति दिवस का 36वाँ विजय दिवस मनाया।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण को 2008 में गठित चङ्का समिति की संस्तुतियों को केन्द्र सरकार ने मंजूर किया।

विशेष आलेख

दहेज प्रताड़ना के कानून से भी ज्यादा खतरनाक है एससी एसटी का कानून

यतेन्द्र पाण्डेय

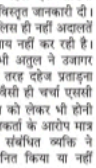

दहेज प्रताड़ना कानून के अंतर्गत हुई कार्यवाहियों से परेशान होकर बेंगलुरू के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड कर लेने के बाद अब देशभर में दहेज प्रताड़ना कानून के नाम पर हो रही ज्यादतियों को लेकर चर्चा हो रही है। न्यूज़ चैनलों पर इस कानून के प्रावधानों को लेकर बहस हो रही है। अधिकांश लोगों का मानना है कि इस कानून की आड़ में निर्दोष लोगों को परेशान किया जाता है। पीड़ित महिला के बयान के आधार पर ही पति के साथ-साथ सास ससुर, ननद देवरानी आदि रिश्तेदारों को भी मुजरिम बना दिया जाता है। भले ही पीड़ित महिला अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती हो, लेकिन फिर भी ससुराल वालों पर आरोप लगाए जाते हैं। इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया और अपने केस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अतुल सुभाष का कहना रहा कि पुलिस ही नहीं अदालतें भी दहेज प्रताड़ना के मामले में न्याय नहीं कर रही है। पुलिस में चल रहे भ्रष्टाचार को भी अतुल ने उजागर किया है। आज देश भर में जिस तरह दहेज प्रताड़ना कानून को लेकर चर्चा हो रही है, वैसी ही चर्चा एससी एसटी (अत्याचार निवारण) कानून को लेकर भी होनी चाहिए। इस कानून में भी शिकायतकर्ता के आरोप मात्र पर ही गिरफ्तारी हो जाती है। संबंधित व्यक्ति ने जातिसूचक शब्द बोलकर अपमानित किया या नहीं इसकी जांच बाद में होती है। प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति ने जो बात कही है, वह सही है। गंभीर बात तो यह है कि बिना जांच के गिरफ्तारी होने पर अधीनस्थ अदालतें भी जमानत नहीं देती है। जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि अधीनस्थ अदालतों को जमानत देने से घबराना नहीं चाहिए। यदि न्यायाधीश को यह लगता है कि आरोपी व्यक्ति निर्दोष है तो जमानत दी जानी चाहिए। आज जिस प्रकार दहेज प्रताड़ना कानून के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं उसी प्रकार एससी एसटी कानून के दुरुपयोग की भी खबरें आ रही है। रिकॉर्ड बताता है कि एससी एसटी के आधे से ज्यादा मामलों में अदालतों में आरोप लगाने वाला व्यक्ति बयान बदला देता है। कई मामलों में समझौता भी हो जाता है। यह सही है कि समाज में सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए एससी एसटी (अत्याचार निवारण) कानून बनाया गया है।

कई मामलों में यह कानून जरूरी भी है, लेकिन देखने में आया है कि व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए भी ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं। यदि किसी श्रमिक को मन मर्जी का मेहनताना नहीं मिला तो वह भी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एससी एसटी कानून में मुकदमा दर्ज करवा देता है। कई बार अधीनस्थ कर्मचारी उच्च अधिकारी के खिलाफ भी ऐसा मुकदमा दर्ज करवा देता है। जब रिपोर्ट लिखाई जाती है तो सबसे ज्यादा मौज पुलिस की होती है। बिना जांच के गिरफ्तारी का डर दिखाकर पुलिस अपना स्वार्थ पूरा कर लेती है। ऐसे मामलों में भारी लेनदेन होता है। जो व्यक्ति मोटी राशि देने में असमर्थक है उसे जेल जाना ही पड़ता है। इस कानून के कारण ही आज हजारों लोग बेवजह जेलों में पड़े हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब एससी एसटी वर्ग के लोग प्रशासन के साथ-साथ राजनीति में भी उच्च पदों पर बैठे हैं, तब इस कानून के सख्त प्रावधानों पर विचार होना ही चाहिए।

आध्यात्मिक प्रसंग : हम सभी दुर्योधन.....

भगवान श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को विराट रूप दिखाकर उसे यह बताना चाहा था कि वह व्यर्थ प्रयास कर रहा है और अधर्म के रास्ते पर है। दुर्योधन ने जब भगवान श्रीकृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की थी, तब उन्होंने भरी सभा में अपना विराट रूप धारण किया था। इस रूप को देखकर दुर्योधन और उसका दूष मामा शकुनि भयभीत हो गए थे। श्रीकृष्ण के इस विराट रूप में विद्युत के समान कांति वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्ष स्थल में रुद्र देव विद्यमान थे। धृतराष्ट्र की सभा में धारण किया विराट रूप जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास पांडवों के शांति दूत बनकर गए थे, तब दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया। इसपर भगवान भरी सभा में अपने विराट रूप में आ गए थे। हम सभी सही मायने में दुर्योधन ही हैं मित्रों,आसमान में 500 लोगों को लेकर उड़ने वाला हवाई जहाज गांव के बालक को चिड़िया लगता है, ठीक ऐसे ही प्लेन में बैठे व्यक्ति को अनन्य व अनन्त प्रवाह से बहती पवित्र नदी माँ गंगा एक नाला सा प्रतीत होती है। बस यही हाल हमारा है. हम काम,क्रोध,लोभ,मोह अहंकार व कपट रूपी जहाज में सवार है इसलिए ईश्वर उतने ही नजर आते हैं जितना अज्ञानी को खुदा व विस्तार को अपने में समाए अनन्त-योगिनी,पवित्र ,पावन गंगा एक तुछ सा नाला नजर आता है। ठीक ऐसे ही हम उस धरती पर खड़े होकर अपने अभिमान और अहंकार में भरे रहते हैं इसलिए 500 यात्रियों को ले जाने वाला हवाई जहाज एक चिड़िया सी नजर आता है।

रूपक शर्मा
संपादकीय प्रभारी,
अलवर संस्करण बढ़ता राजस्थान

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हर्षोदयपुरा रोड़ खण्डवा,निवाई रोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिष्ठा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राव बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 रोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, रोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-खेतावत सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड़,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

दैनिक जागरण
गतिशीलता ही जीवन है

सार्थक चर्चा का अभाव

संविधान पर लोकसभा में बहस तो हो गई, लेकिन इसमें संदेह है कि इस बहस से जनता को कोई सही दिशा मिली होगी। संदेह इसलिए है, क्योंकि सत्तापक्ष और विपक्ष ने संविधान पर चर्चा के बहाने एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने का काम किया। इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से अतीत के प्रसंगों और विषयों को अधिक रेखांकित किया गया। इनमें से अनेक प्रसंग और विषय ऐसे थे, जिन पर पहले भी किसी न किसी बहाने संसद के भीतर या बाहर चर्चा हो चुकी है। यह पहले से दिख रहा था कि विपक्ष संविधान पर चर्चा के बहाने यह बताने की कोशिश करेगा कि संविधान खतरे में है। यह समझाने के लिए विपक्षी नेताओं ने जोर तो खूब लगाया, लेकिन वे यह स्पष्ट करने में विफल रहे कि आखिर संविधान को खतरा कैसे है? लगता है कि विपक्षी नेता यह समझने को तैयार नहीं कि लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने संविधान के खतरे में होने का जो हौव्वा खड़ा किया था, वह अब असरकारी नहीं रह गया है। विपक्ष के रवैये से यही लगा कि उसे यह बुनियादी बात समझने में मुश्किल हो रही है कि जाति जनगणना कराने-न कराने से संविधान की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? यदि जाति जनगणना इतनी ही आवश्यक है तो नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में क्यों नहीं कराई गई? अच्छा होता कि कांग्रेस नेता पहले इस प्रश्न का जवाब देते और फिर जाति जनगणना की आवश्यकता रेखांकित करते।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह भी बताना चाहिए कि संविधान पर बहस करते समय सावरकर का नाम लेना और मनुस्मृति दिखाना क्यों आवश्यक हो गया था? कांग्रेस को यह समझ आ जाए तो बेहतर कि सावरकर, मनुस्मृति और अदाणी का उल्लेख करते रहने से उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। कांग्रेस संविधान पर चर्चा करते समय यह भी भूल गई कि वह यदि मोदी सरकार के एक दशक के कार्यकाल का हिसाब मांगेगी तो उसे भी अपने चार दशकों के कार्यकाल का हिसाब देना होगा। संविधान पर चर्चा के दौरान जैसे विपक्ष ने सत्तापक्ष पर आरोपों की झड़ी लगाई, वैसे ही सत्तापक्ष ने भी विपक्ष पर आरोपों की बौछार की। इसकी आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता तो इसकी थी कि उन कारणों पर चर्चा की जाती, जिनके चलते संविधान निर्माताओं के सपने अभी तक पूरे नहीं हो सके हैं और नियम-कानूनों पर संविधान की मूल भावना के अनुरूप पालन नहीं हो पा रहा है। उचित यह होगा कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बहस के स्तर को ऊंचा उठाया जाए और आरोप-प्रत्यारोप से बचते हुए संविधान को प्रभावी तरीके से लागू करने में सहायक बनने वाले बिंदुओं पर सहमति कायम की जाए और फिर उन पर कोई सार्थक चर्चा की जाए। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री ने जो 11 संकल्प गिनाए हैं, उन पर ध्यान दिया जा सकता है।

जनता की परेशानी

पंजाब में किसानों की ओर से दिल्ली कूच के तीसरे प्रयास के दौरान भी लगभग 17 किसानों का घायल होना और एक किसान द्वारा आत्महत्या की कोशिश करना चिंता की बात है। किसान नेताओं को एक बार फिर अपनी रणनीति को लेकर पुनर्विचार करना चाहिए। हरियाणा पुलिस के अधिकारियों की ओर से जिस तरह की किलेबंदी की गई है उसे देखते हुए किसानों का बार्डर पार कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी स्थिति में इस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए कि इस तरह के प्रयास से क्या हासिल हो रहा है। कुछ किसान नेताओं द्वारा अब पंजाब में भी 18 दिसंबर को ट्रेनें रोकने की घोषणा कर दी गई है। इससे जनता की परेशानी में वृद्धि होना तय है। किसानों के दिल्ली कूच के बार-बार प्रयास के कारण शंभू में हरियाणा बार्डर से लगते क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट की सेवा बार-बार बंद करने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आजकल कई आवश्यक काम के लिए मोबाइल इंटरनेट जरूरी हो गया है। अब यदि पंजाब भर में ट्रेनें रोकी जाएंगी तो यात्रियों को तो परेशानी होगी ही, राज्य की छवि भी इससे प्रभावित होगी। हाईवे एवं रेल ट्रैक पर धरनों से राज्य का नुकसान ही होता है। किसान संगठनों में आम सहमति न होने से भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। कदाचित यही कारण है कि पहले की तरह इस बार आंदोलन को समर्थन नहीं मिल रहा है। कोई भी आंदोलन सफल तभी हो सकता है जब उसे आम जनता का भी सहयोग मिले। मांगें मनवाने के लिए ऐसा तरीका अपनाना ठीक नहीं है जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े।

> किसान नेताओं को यह समझना होगा कि ऐसा कोई तरीका अपनाना ठीक नहीं है जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े

वास्तविकता पर पर्दा डालने का प्रयास

हृदयनारायण दीक्षित

उपासना स्थल अधिनियम 1947 के पहले के पूजा स्थलों की समूची जानकारी वर्जित करता है, जबकि इतिहास जानना हमारा अधिकार है

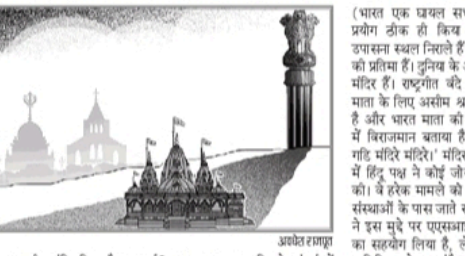

अवधेश राजपूत

भारत के मन में मंदिरों के प्रति प्राचीन काल से ही श्रद्धा भाव है, लेकिन ऐसे सैकड़ों मंदिर मध्यकाल में ध्वस्त किए गए। ध्वस्त मंदिरों की सामग्री से मस्जिदें बनाई गईं। ऐसे ध्वस्त मंदिर भारत के मन में घाव की तरह रिसते हैं। मूलभूत प्रश्न है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों पर मस्जिदें बनाईं, क्या उनके सामने जगह का अभाव था? यह एक तथ्य है कि भारत में अनेक मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर ही बनाई गई हैं। राम मंदिर के लिए छिड़ा अयोध्या आंदोलन यूरोप के पुनर्जागरण जैसा था। इसी दौरान कांग्रेस को तत्कालीन सरकार ने देश के सभी उपासना स्थलों के लिए 'प्लेसेज आफ वरशिप एक्ट 1991' पारित किया। इस अधिनियम में व्यवस्था है कि अयोध्या को छोड़कर देश के सारे उपासना स्थल 1947 की यथास्थिति में रहेंगे।

हिंदुओं से तत्कालीन सरकार की अपेक्षा थी कि वे मंदिर तोड़कर बनाए गए उपासना स्थलों को देखकर भी शांत रहें, मंदिर तोड़कर बनी मस्जिदों को भी स्वीकार करें और मंदिर ध्वंस के राष्ट्रीय अपमान को भी भूल जाएं। वे उपासना गृह, उपासना स्थल देखकर भी चुप रहें। राष्ट्रीय स्वाभिमान त्याग दें और मौलिक अधिकारों को भी अतिक्रमित करने वाला उपासना स्थल कानून स्वीकार कर लें। अधिनियम का भाव है कि हिंदू ध्वंस मंदिरों और अत्याचारों को भूल जाएं। मंदिर और उपासना का इतिहास 1947 से शुरू करें। अधिनियम की संवैधानिकता सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

हिंदू उपासना स्थलों को ध्वंस करने और उन्हीं स्थानों पर इस्लामी उपासना स्थल बनाने का लक्ष्य दरअसल बहुसंख्यकों को नीचा दिखाना था। तैमूर का कहना था कि हमलों का मकसद हिंदुस्तान को झूठी आस्था और बहुदेववाद से मुक्त कराना है और इसके लिए मंदिरों को नष्ट करना जरूरी है। ऐसा कृत्य किसी एक जगह नहीं हुआ। अयोध्या, काशी, मथुरा और सोमनाथ राष्ट्रीय चर्चा में रहते हैं, लेकिन ऐसे अपमानजनक कृत्य सैकड़ों मंदिरों में हुए। हिंदू अस्मिता एवं आस्था को नष्ट करने के कारण बहुत गंभीर हैं। वे हिंदुओं को बहुदेववादी कहते हैं। वे बहुदेववाद और मूर्ति पूजा समाप्त करने के लिए मंदिर ध्वस्तीकरण करते हैं। दिल्ली में कई हिंदू उपासना स्थलों को तोड़कर बनी 'कुव्वत उल इस्लाम' मस्जिद के नाम में वे इस्लाम की ताकत का उल्लेख है। ऐसी सारी घटनाएं हिंदू मन में अपमान का भाव पैदा करती हैं। मंदिर ध्वंस के अत्याचारों को हिंदू भूल नहीं सकते। उत्तर प्रदेश के संभल दंगे की जांच कर रही वरिष्ठ अधिकारियों की टीम को वर्षों पुराना बंद पड़ा प्राचीन मंदिर मिला है। ऐसी घटनाएं हिंदू मन को आहत करती हैं। देश की राष्ट्रीय अस्मिता को अपमानित करने वाले चिह्नित होने चाहिए। बेशक मंदिर ध्वस्त करने वाले लोग और शासक अब जीवित नहीं और हम उन्हें उनके कृत्यों के लिए दंडित नहीं कर सकते, मगर आखिर इसका क्या औचित्य कि हिंदू अपनी मांग के लिए उचित संस्थाओं की प्रार्थना पत्र भी नहीं दे सकते? राष्ट्रीय अपमान के कारणों एवं गुन्हगारों को जानना हर नागरिक का अधिकार है। यह अधिनियम 1947 से पूर्व उपासना स्थलों की जानकारी वर्जित करता है, जबकि इतिहास जानना हमारा अधिकार है। इतिहासबोध से राष्ट्र शक्तिशाली रहते हैं। जीवंत राष्ट्र इतिहास से सीखते हैं, मगर यह अधिनियम 1947 से पूर्व सांस्कृतिक राष्ट्रभाव की चर्चा सीमित करता है। यह इतिहास के प्रवाह की उपेक्षा है।

अधिनियम पारण की हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार विधेयक सदन में रखने के साथ उसके उद्देश्य का विवरण भी दिया जाता है कि सरकार विधेयक क्यों लाई? उपासना स्थल अधि. के संदर्भ में भी सरकार की ओर से उद्देश्य एवं कारण बताए गए। कहा गया था कि पूजा स्थलों के परिवर्तन के संबंध में अक्सर उत्पन्न होने वाले विवादों को देखते हुए यह अनुभव किया गया है कि ऐसे परिवर्तनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अधिनियम में किसी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने की बात महत्वपूर्ण है। अपना धार्मिक क्षेत्र बनाए रखना प्रत्येक मजहब, पंथ का अधिकार है। उपासना स्थलों का धार्मिक चरित्र बदलने का काम हिंदुओं ने कभी नहीं किया।

मंदिर भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की अभिव्यक्ति हैं। मंदिरों की अपनी उपयोगिता रही है। मंदिरों में चिकित्सा और शिक्षा के लिए चिकित्सालय और पाठशालाएं भी थीं। हिंदुओं ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और न ही मतांतरण कराया, मगर मध्यकाल के विदेशी हमलावरों ने पूरी सभ्यता को उखाड़ फेंकने का अभियान चलाया। नोबेल पुरस्कृत वीएस नायपाल ने भारत के लिए 'इंडिया द वुंडेड सिविलाइजेशन (भारत एक घायल सभ्यता)' शब्द का प्रयोग ठीक ही किया था। हिंदुओं के उपासना स्थल निराले हैं। मंदिर हिंदू दर्शन की प्रतिमा हैं। दुनिया के अनेक देशों में हिंदू मंदिर हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम् में भारत माता के लिए असीम श्रद्धा व्यक्त की गई है और भारत माता की प्रतिमा को मंदिर में विराजमान बताया है- 'तोमारेई प्रतिमा गढि मंदिरे मंदिरे।' मंदिर ध्वंस के मामलों में हिंदू पक्ष ने कोई जोर-जबरदस्ती नहीं की। वे हरेक मामले को लेकर संवैधानिक संस्थाओं के पास जाते रहे हैं। न्यायमूर्तियों ने इस मुद्दे पर एएसआइ आदि संस्थाओं का सहयोग लिया है, लेकिन पूजा स्थल अधिनियम ने यह संवैधानिक मार्ग भी बंद कर दिया है। हिंदुओं की भावना को गहराई से समझना चाहिए। मंदिर ध्वस्तीकरण राष्ट्रीय स्वाभिमान को रौंदने की दुभिग्यपूर्ण घटना है। कोई भी सजग राष्ट्र ऐसे राष्ट्रीय अपमान को कैसे भूल सकता है। रामधारी सिंह दिनकर ने 'संस्कृति के चार अध्याय' में लिखा है, 'देश की सुरक्षा और खुशहाली किसी भी शासन के लिए गौरव का कार्य है, किंतु मुस्लिम इतिहासकारों ने अधिक प्रशंसा उन सुल्तानों और गाजियों की लिखी है, जिन्होंने कांधार से अधिक मंदिर तोड़े।' कई इतिहास लेखक भी मंदिर ध्वंस की घटनाओं का उल्लेख नहीं करते।

कथित सेक्युलर मध्यकाल की हिंदू उत्पीड़न एवं मंदिर ध्वंस की कार्यवाही को भूल जाने का उपदेश देते हैं। राष्ट्र को यह जानने का अधिकार है कि उस बर्बर कालखंड में भारतीय राष्ट्रभाव के साथ क्या हुआ? आखिर देश को नीचा दिखाने के आपराधिक कृत्य का प्रतिकार क्या है?

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

बदला लेने का जरिया बने कानून

दीपिका नारायण भारद्वाज

महिला संरक्षण कानूनों के सहारे अब यह आम होता जा रहा है कि झूठे केस लगाओ और पैसे उगाहो

अतुल सुभाष के ससुराल पहुंची बेंगलुरु पुलिस। प्रेट्र

कुछ वर्ष पहले सैयद अहमद मख्दूम ने अपनी जान देने के पहले सात मिनट के अपने वीडियो में कहा था, 'मेरी जिंदगी का मकसद मेरा बेटा है। मैं उससे मिलने के लिए तिल-तिल मरता हूं। मैं आधा तो उसी दिन मर गया था, जिस दिन मुझे दहेज के झूठे मुकदमे में जेल जाना पड़ा था।' मख्दूम मास्टर्स इन सोशल वर्क थे। उन पर पत्नी द्वारा दहेज का झूठा आरोप लगाया गया। उन्हें जेल जाना पड़ा और अपने बेटे से दूर होना पड़ा। उन्होंने न्यायालय में लड़ाई लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब समझ आया कि कानून बिल्कुल एकतरफा है तो उम्मीद छोड़ दी।

इस समय देश ऐसी ही एक और आत्महत्या देखकर रो रहा है। पत्नी से प्रताड़ित होकर बेंगलुरु में आत्महत्या करने वाले अतुल सुभाष के सुसइड वीडियो और 24 पन्नों के नोट ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर महिलाओं के संरक्षण के उपाय पुरुषों की जान क्यों ले रहे हैं? न्याय प्रणाली इतनी एकतरफा कैसे हो गई कि आदमी जान दे दे रहा है? उन कानूनों का धड़ल्ले से मजाक क्यों उड़ाया जा रहा, जो महिलाओं के संरक्षण के लिए लाए गए और कैसे महिलाओं ने ही इन कानूनों को उगाही का जरिया बना लिया है?

यह किसी से छिपा नहीं रह सका है कि झूठे मुकदमों की सूची अंतहीन रूप से लंबी होती जा रही है। पूरे के पूरे परिवार को दहेज के झूठे केस में फंसा देना, आपसी विवाद में दुष्कर्म का आरोप लग देना, ब्यायफ्रेंड से ब्रेकअप पर शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप लगना, लड़ाई हो जाए तो छेड़छाड़ बता देना, बास नौकरी से निकाल दे तो सेक्सुअल हैरेसमेंट बताना, बच्चे की कस्टडी हथियाने के लिए पिता पर ही पोक्सो लगाना अब आम हो गया है। अनगिनत उदाहरण हैं, जो लोग अपने आसपास देख रहे हैं। विडंबना यह है कि पुलिस सब कुछ जानते हुए भी झूठे मामलों को रद नहीं करती। लंबे ट्रायल के बाद जब कभी न्यायालय पुरुष को निर्दोष करार कर देते हैं तो भी महिलाओं को हर्जाना भरने को नहीं कहते। यह कैसा न्याय है?

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल में एक पति के खिलाफ पत्नी द्वारा लगाए गए मुकदमे को रद कर दिया। प्रेम विवाह के बाद एक साल चली इस शादी में पति तलाक की अर्जी लगाता है। इससे पत्नी इतनी आक्रोशित हो जाती है कि न केवल 498 ए और दहेज का झूठा आरोप लगाती है, बल्कि ससुर पर दुष्कर्म और देवर पर छेड़छाड़ का झूठा मामला भी दर्ज कराती है। परिवार के सभी लोगों को लपेटते हुए 11 धाराएं लगाई जाती हैं। न्यायालय इन सबको सिरे से झूठा कहकर केस रद कर देता है, लेकिन महिला की हजार रुपये तक का भी हर्जाना भरने को नहीं कहा जाता। सोचिए अगर कोई पुरुष ऐसा झूठा मामला बनाता तो उसे कितनी घृणा और सजा मिलती। उक्त मामले में महिला को कोई सजा नहीं मिली।

अब यह आम बात हो गई है कि झूठे केस लगाओ और पैसे उगाहो। यही बात अतुल ने भी अपने अंतिम शब्दों में कही। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अपनी ही कमाई अपनी बर्बादी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। ऐसा नहीं है कि यह पहली दफा है कि किसी पुरुष ने आत्महत्या कर ली और कोहराम मच गया। न जाने कितने अतुल सुभाष मर चुके हैं। लाखों परिवार तबाह हो चुके हैं, लेकिन समाज दशकों से यह देखते हुए भी चुप रहा, क्योंकि पुरुषों के हित की बात भी महिलाओं के खिलाफ समझी जाती है और फेमिनिज्म और नारीवाद के जमाने में कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। अब अतुल सुभाष की आत्महत्या ने लोगों को प्रश्न पूछने पर मजबूर कर दिया है। उनकी आत्महत्या ने देश में वैसी लौ जला दी है, जैसी निर्भया के समय महिलाओं के न्याय और सम्मान के लिए जली थी। लोग कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बहुत आसर नहीं कि झूठे मुकदमों के सिलसिले को थामने के कोई ठोस जतन होंगे। क्या एक पुरुष की जिंदगी की हमारे देश में कोई कीमत नहीं? जितना उबाल अतुल सुभाष के केस को लेकर है, उतना अगर किसी महिला की मृत्यु पर होता तो संसद में महिला सुरक्षा पर सौ सवाल उठ रहे होते और कानून की कमियों पर चर्चा हो रही होती।

मुद्दे पुरुषों के ऊपर होते अन्याय को उजागर करते हुए एक दशक से अधिक समय हो चुका है। मुझे बहुत उम्मीद नहीं है हमारे सिस्टम से, लेकिन मैं आम लोगों से यह कहना चाहूंगी कि वे अतुल की मृत्यु व्यर्थ न होने दें। हर किसी को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री को संदेश देना चाहिए कि अब बदलाव की जरूरत है। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं, बल्कि सिर्फ एक पहल। मेरे हिसाब से पहल एक कमेटी बनाने से की जा सकती है। जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी निर्भया कांड के समय बनी थी, वैसी ही अब महिला संरक्षण कानूनों के दुरुपयोग और पुरुषों के ऊपर बढ़ती ज्यादतियों को देखने और समझने के लिए बननी चाहिए। कमेटी पूरे देश से सुझाव मांग सकती है। उसे महिला संरक्षण के कानूनों के दुरुपयोग के आंकड़े गहनता से देखने चाहिए। इसके बाद जरूरी बदलाव के कदम उठाए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में 498 ए के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद कहा था। दो दशक बीत चुके हैं, लेकिन कानूनी आतंकवाद अब भी कायम है। इससे पहले और कोई अतुल सुभाष अपनी जान दें, इस आतंकवाद को रोका जाए। अतुल के जान देने के बाद से लगभग आठ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें पत्नी या बहू की प्रताड़ना से त्रस्त लोगों ने जान दी है। इन लोगों की मौतों को सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि ये भी देश के ही नागरिक थे।

(लेखिका डाक्यूमेंट्री फिल्ममेकर और एकम न्याय फाउंडेशन की निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

विचार प्रबंध

इस दौर में अस्थिति और अनियंत्रित विचारों का प्रभाव सामान्य हो गया है। हमारा मन बार-बार अस्थिर हो जाता है और इस अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण हमारे विचारों की अनियंत्रित धारा ही है। इन विचारों को शांत करने और मन को स्थिर बनाए रखने के लिए कुछ लोग प्रायः स्वयं को अत्यधिक व्यस्त रखने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया कई बार प्रभावी होती है, परंतु इसके अपने सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू हैं। जब मन किसी समस्या, आकांक्षा या दुख में फंसा होता है, तो वह बार-बार उसे पर विचार करता है। इसे 'ओवरथिंकिंग' कहा जा सकता है। यह स्थिति न केवल मानसिक तनाव को बढ़ाती है, बल्कि व्यक्ति की रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऐसे में, व्यक्ति स्वयं को व्यस्त रखते हुए अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। महात्मा गांधी ने कहा है, 'आपके विचार ही आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कर्म बनते हैं और आपके कर्म आपका भविष्य। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और शांत रखें।'

स्वयं को किसी उपक्रम में व्यस्त रखना सीमित रूप में कारगर उपाय हो सकता है। यह हमें हमारे नकारात्मक विचारों से दूर ले जाता है और हमारे समय और ऊर्जा को सकारात्मक गतिविधियों में लगाता है। यदि हम केवल काम में डूबे रहकर अपनी भावनाओं को अनदेखा करते हैं, तो यह समस्या को स्थायी रूप से हल नहीं करता। वस्तुतः, विचारों का सामना करना और उनके पीछे के कारणों को समझना भी उतना ही आवश्यक है। अत्यधिक विचारों से बचने के लिए स्वयं को व्यस्त रखना एक व्यावहारिक उपाय है, परंतु यह तभी प्रभावी है जब इसे संतुलित रूप से अपनाया जाए। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

बदलती जीवनशैली के दुष्प्रभाव

डा. महेश परिमल

> आज यदि आप डाक्टर, वकील के पीछे नहीं भाग रहे हैं और पुलिस आपके पीछे नहीं भाग रही है, तो आप दुनिया के सबसे सुखी मानव हैं

कहते हैं जहां त्याग है, वास्तव में सुख वहीं है। वैसे आजकल सुख की परिभाषा में भी कुछ बदलाव आ गया है। आज यदि आप डाक्टर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वकील के पीछे नहीं भाग रहे हैं और पुलिस आपके पीछे नहीं भाग रही है, तो आप दुनिया के सबसे सुखी मानव हैं। आज यह सुख हर किसी के पास नहीं है। उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर गहराई से विचार किया जाए, तो पहला यही है कि आप स्वस्थ हैं। यानी आपकी दिनचर्या और जीवनशैली बिल्कुल निर्धारित है। आप संयमित जीवन जी रहे हैं। आप सक्रिय हैं। आपका भोजन सात्विक है। आप खुशमिजाज हैं। आप सदैव किसी की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी कारक हैं, वह इसी में शामिल हैं कि आप डाक्टर के पीछे नहीं भाग रहे हैं।

दूसरा कारक है आप वकील के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो इसका सफ मतलब है कि आप अपनी संपत्तियों को लेकर किसी तरह के विवाद में नहीं हैं। आप किसी से बेवजह उलझना पसंद नहीं करते। आप वाद-विवाद से दूर रहते हैं। कोर्ट-कचहरी से आप कोसों दूर हैं। आप संतोषी जीव हैं। आपके दुश्मन नहीं के बराबर हैं। आपने किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये सभी कारक हैं, जिसने आपको वकीलों से दूर रखा है। तीसरा कारक पुलिस आपके पीछे नहीं भाग रही है। इसका आशय यही हुआ कि आप अपराधी नहीं हैं, आपने किसी अपराधी की सहायता भी नहीं की है। न आप चोरी करते हैं न ही चोरी का सामान खरीदते हैं। आप आपराधिक मनोवृत्ति से काफी दूर हैं। आप जो भी बोलते हैं, सोच-समझकर बोलते हैं। किसी से दुर्व्यवहार नहीं करते। इसलिए पुलिस आपके पीछे नहीं भागती।

उपरोक्त तीनों कारक हैं, जो हमें सुखमय जीवन की ओर ले जाते हैं। हमारे सामने दुविधाओं के चक्रव्यूह नहीं होते। भले ही जीवन में उलझनें हों, पर उन्हीं उलझनों के बीच आप सुलझाने का मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे में आप हर पल सुखमय जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं।

वैसे देखा जाए, तो जीवन उतना कठिन नहीं है, जितना हमने उसे बना दिया है। जीवन तो बहुत ही सरल है। हम ही हैं, जो उसे लगातार जटिल बना रहे हैं। अब भला सुबह जल्दी उठने के लिए मना किसने किया है आपको, लेकिन आप ही हैं, जो देर से उठकर अपनी जीवनचर्या प्रारंभ करते हैं और परेशानी में पड़ते हैं। प्रकृति ने हमें कई अनमोल उपहार दिए हैं, जिसे अस्वीकार कर हम अपने जीवन को उलझाते रहते हैं। जिस दिन हमने प्रकृति के साथ रहना सीख लिया, उसके साथ कदम मिलाना सीख लिया, बस...हमने सुखमय जीवन की ओर पहला कदम रख दिया समझो।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

शिक्षा की गुणवत्ता पर दिया जाए ध्यान

'विदेश में पढ़ाई' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में उल्लेख है कि विदेश में पढ़ाई पर खर्च होने वाले धन और वहां नौकरी करने वाले भारतीय छात्रों की ओर से भेजी जाने वाली राशि का अंतर कम होता जा रहा है। इस आंकड़े से यह पुष्टि हो रही है कि पढ़ाई के लिए विदेश जाने का आकर्षण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2022 से 2024 के बीच ऐसे छात्रों की संख्या 4.5 लाख बढ़ गई। इसी दौरान देश में निजी शिक्षण संस्थान भी बढ़े हैं, मगर प्रतीत होता है कि संख्या के अनुपात में उन्में शिक्षा का स्तर गुणवत्तापूर्ण नहीं है। शिक्षा मंत्रालय का इस संबंध में संज्ञान लेना स्वागतयोग्य है। ऐसे में, सरकारी के साथ-साथ निजी शिक्षण संस्थानों में विविधतापूर्ण विषयों में शिक्षा के प्रबंध करने होंगे। साथ ही ऐसी शिक्षा किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण भी होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा का बजट बढ़ाना होगा, जिससे इस राह में भौतिक एवं मानव संसाधनों की पूर्ति की जा सके। सिर्फ थोक भाव में उच्च शिक्षा के लिए निजी शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति देने से लक्ष्य का प्राप्त करना कठिन है। शिक्षा की गुणवत्ता को विश्वस्तरीय बनाए रखने के लिए संस्थानों की सतत निगरानी भी जरूरी है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

संयमित व्यवहार करें

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मांगलिक उत्सव, लग्न-समारोह, बरात आदि में वैध/अवैध हथियारों से हवाई फायर करना प्रतिबंधित होने के बावजूद चंद लोगों के लिए मौज-मस्ती का घटिया प्रदर्शन बनता जा रहा है। हवाई फायर करने से आयोजन में आए लोगों में डर एवं तनाव उत्पन्न होता है। इसे किसी भी तरह से खुशी प्रदर्शित करने का माध्यम नहीं कहा जाना चाहिए। आतिशबाजी, धुआं फैलाने एवं तीव्र गति से बजने वाले संगीत से ध्वनि एवं वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। इससे लाभ कम अपितु नुकसान ज्यादा होता है। नाचने-गाने से विवाह में आए मेहमान आनंदित हों, परंतु कानून विरोधी गतिविधियों, हवाई फायरिंग और शराब के सेवन से समाज का वातावरण खराब न करें।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

न हो एकतरफा कार्रवाई

इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरण में उनका 24 पन्नों का आत्महत्या पूर्व लिखा गया नोट एवं डेढ़ घंटे का वीडियो वर्तमान न्यायपालिका पर एक कटु प्रहार है। कई बार दहेज एवं महिला उत्पीड़न के मुकदमे झूठे, निराधार और दूसरे पक्ष को प्रताड़ित करने की मंशा से आर्थिक तथा मानसिक शोषण करने के लिए साबित हो रहे हैं। एकतरफा कानूनी कार्रवाई की आड़ में बहुधा दूसरा पक्ष मजबूरन केस समाप्त करने के लिए अनर्गल मांगें मानने के लिए बाध्य हो जाता है। छेड़छाड़, दहेज एवं महिला उत्पीड़न के केस झूठे साबित होने पर महिला पर भी कठोर कार्रवाई का प्रविधान होना चाहिए, जिससे कोई दूसरा सुभाष आत्महत्या न करे।

जयप्रकाश अग्रवाल, दिल्ली

आरोप-प्रत्यारोप का खेल

संविधान के 75 साल होने पर लोकसभा में चर्चा के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की झड़ी लगी। कांग्रेस और एनडीए की सरकारों पर बात हुई। लोकसभा में यह देखने को मिल रहा है कि राजनीति देश हित में नहीं होकर दल हित की हो रही है। कांग्रेस शासनकाल में अनेक बार संविधान संशोधन किए गए। वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस करती आ रही है। अदाणी को मोहरा बनाकर कांग्रेस ने कई बार आरोप लगाकर अपनी राजनीति चमकाने के प्रयास किए हैं। एनडीए के कार्यकाल में विकास हुआ है तो उसके नेता विकास को गिनाते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता उपलब्धि गिनाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दे नहीं हैं, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने में सफलता हासिल कर सके। कांग्रेस ने कभी भी डा. भीमराव आंबेडकर को महत्व नहीं दिया। संविधान सभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस का आपातकाल याद दिलाया।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

आपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 258

संविधान ने दी देश को दिशा

भारतीय संविधान को अंगीकृत करने की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष चर्चा में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सभा में यह उचित ही कहा कि संविधान ने आजादी के बाद भारत के लिए सभी पूर्वानुमानित संभावनाओं को हासिल किया है। एक युवा गणतंत्र के जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन भारतीय संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा है और उसने भारत की अच्छी सेवा की है। इसकी सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण सत्ता का निरंतर शांतिपूर्ण हस्तांतरण है, जो जनाकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है। यहां यह बताना जरूरी है कि भारत में हर स्तर पर राजनीति बेहद प्रतिस्पर्धी है।

पिछले दशकों में देश में कई तरह के राजनीतिक दलों और गठबंधनों ने शासन किया है। कुछ विफलताओं को छोड़ दें तो वे ज्यादातर समय देश को आगे ले गए हैं। साल 1975 में आपातकाल लागू करना ऐसा ही एक स्पष्ट उदाहरण है। भारत के संविधान को एक गतिशील और जीवंत दस्तावेज के रूप में पेश किया गया था जिसमें एक युवा राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुकूल लचीलापन निहित था। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारे संविधान में 100 से ज्यादा बार संशोधन किए गए। उदाहरण के लिए सबसे हाल का संशोधन संसद और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने का था, हालांकि यह प्रावधान अगले परिसीमन के बाद ही लागू हो सकेगा। अगर आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों ने कराधान की अपनी साझा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वस्तु एवं सेवा कर को लागू करना संभव बनाया और इसके लिए संविधान में प्रासंगिक बदलाव किए गए। इस तरह संविधान ने पिछले वर्षों में भारत को सामाजिक और आर्थिक, दोनों तरह के हितों को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। वैसे तो पिछले हफ्ते संसद में आयोजित दो दिवसीय चर्चा में विभिन्न पहलुओं को छुआ गया, लेकिन कई स्तरों पर यह एकतरफा रही। हालांकि, यह पूरी तरह से अप्रत्याशित भी नहीं था, लेकिन सदस्य इस अवसर का इस्तेमाल इस पर चर्चा के लिए कर सकते थे कि संविधान में अंगीकृत किए गए विचारों पर आगे किस तरह से अमल हो। भारत साल 2047 यानी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए यह उचित ही है कि इसका उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन में परिवर्तन लाना और उन्हें सशक्त बनाना हो। इस संबंध में मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले कुछ प्रावधानों की चर्चा करना मुनासिब होगा। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14 भारतीय क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या सभी को कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान किसी भी तरह के भेदभाव को खारिज करता है।

हालांकि भारतीय राज्य सभी नागरिकों को यह गारंटी उपलब्ध कराने में अक्षम साबित हुआ है। उदाहरण के लिए हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने तक, कई राज्यों में 'बुलडोजर न्याय' चल रहा था जो कि संविधान के शब्दों और भावनाओं, दोनों के खिलाफ था। देश को संस्थाओं, खास तौर पर न्यायपालिका को मजबूत करने की जरूरत है। बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों की वजह से फैसले होने में काफी देरी होती है जिससे आम नागरिकों के हित और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञों में इसे लेकर आमराय है कि भारत को अगर विकसित देश बनाना है तो उसे बेहतर गुणवत्ता वाली मानव संपदा की जरूरत होगी। इस संदर्भ में संसद ने अनुच्छेद 21ए (86वां संशोधन) को अपनाकर अच्छा कदम उठाया है जिसके जरिये राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगा। इसका नतीजा यह है कि पिछले वर्षों में स्कूलों में नामांकन बढ़ गया है जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही श्रेय की हकदार हैं। हालांकि हाल के कई सर्वेक्षणों, खासकर वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (असर) में यह साफ हुआ है कि शिक्षा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है।

अगर इस पहलू पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया गया तो भारत अपेक्षित गति से आगे बढ़ने और विकास करने में सक्षम नहीं हो पाएगा। यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि देश में सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिणाम संविधान की मूल भावना के अनुरूप हों। लेकिन निष्पक्ष रूप से कहें तो पिछले 75 वर्षों में भारत ने जो कुछ भी हासिल किया है वह वाकई शानदार है। मूल संवैधानिक मूल्यों को कायम रखने से ही भारत अपने नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होगा।

केवल डीप स्टेट नहीं अमेरिकी विदेश विभाग पर भी है हमला

भाजपा का हमला केवल अमेरिकी 'डीप स्टेट' पर नहीं था। विचारधारा के स्तर पर भी यह विचार पिछले काफी समय से मजबूत हो रहा था और डॉनल्ड ट्रंप ने भी इसे वैधता प्रदान की है।

हमारे राजनीतिक रणनीतिक इतिहास की एक अहम घटना अपेक्षाकृत कम बहस के साथ गुजर गई। वह घटना थी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा अमेरिकी डीप स्टेट पर ही नहीं बल्कि अमेरिकी विदेश विभाग पर भी हमला।

जब भाजपा के आधिकारिक एक्स हैंडल ने 16 भागों में बंटे एक संदेश के जरिये अमेरिकी डीप स्टेट पर हमला किया और कहा कि वह भारत और मोदी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। ऐसे हमले पर आपकी सामान्य प्रतिक्रिया यह होती कि ठीक है अब तो ट्रंप नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वह इस शत्रु पर हमलावर हैं तो भाजपा भी इसमें शामिल हो गई है और वह विजेता का साथ देती हुई नजर आना चाहती है। परंतु इन 16 पोस्ट में से 13वीं पोस्ट डीप स्टेट से परे जाकर अमेरिकी विदेश विभाग पर आरोप लगाती है कि वह इस षडयंत्रकारी नेटवर्क का नेतृत्व कर रहा है।

इसकी अहम पंक्तियों में कहा गया है, 'इस एजेंडा के पीछे हमेशा अमेरिकी विदेश विभाग रहा है। डीप स्टेट का स्पष्ट लक्ष्य रहा है प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर भारत को अस्थिर करना। फ्रांस के खोजी मीडिया समूह मीडियापार्ट ने बताया कि ओसीसीआरपी की फंडिंग अमेरिकी विदेश विभाग के यूएसएड से होती है। बल्कि ओसीसीआरपी की 50 फीसदी फंडिंग अमेरिकी विदेश विभाग से होती है।'

पेगासस विवाद का विशेष उल्लेख किया गया, अदाणी समूह को लेकर खुलासों की बात हुई और जॉर्ज सोरोस जैसे अन्य 'डीप स्टेट' फिगर्स का भी उल्लेख किया गया। यहां अहम और नई बात थी भाजपा द्वारा अमेरिकी विदेश विभाग पर सीधा हमला। मीडियापार्ट फ्रांस का धुर वामपंथी मंच है जिसने राफेल सौदे की जांच की थी और कांग्रेस तथा मोदी के आलोचकों को उन पर हमले करने का अवसर दिया। अब तक भाजपा के लिए यह फ्रांस के वामपंथी डीप स्टेट का षडयंत्र था ताकि भारत और मोदी सरकार को कमजोर किया जा सके। अब वह एक विश्वसनीय सहयोगी है। राजनीति में विरोधाभास खुदबखुद खत्म नहीं होते।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

अपने नवीनतम अवतार में बेताल मीडियापार्ट की कहानी अमेरिकी प्रतिष्ठान के लिए बहुत अधिक नुकसानदेह थी। उसने खुलासा किया कि अमेरिकी विदेश विभाग दुनिया भर में खोजी पत्रकारिता को फंड करता है लेकिन वह अहम नियुक्तियों और मुद्दों पर वीटो शक्ति भी रखता है। अगर किसी राजनीतिक दल को लगता है कि अमेरिकी सरकार द्वारा फंड की गई गतिविधियों के कारण उसकी सरकार को नुकसान पहुंच रहा है तो उसे सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। परंतु दिक्कतें कहीं और आरंभ हुईं। यह पहली बार नहीं है जब भारत के सत्ताधारी दल ने विदेशी ताकतों पर हमला किया या कहें अमेरिका पर हमला किया। इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस ऐसा अक्सर करती थी।

वर्ष1970 के दशक के आरंभ में इंदिरा गांधी जब विपक्ष के दबाव में थीं तब वह और उनकी पार्टी अक्सर विरोधियों पर सीआईए एजेंट होने का आरोप लगाते थे। उस समय राज्य सभा के सदस्य पीलू मोदी जो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे, वह एक दिन सदन में एक बैज पहनकर आए जिस पर लिखा था- 'मैं सीआईए एजेंट हूं।' बाद में राजीव गांधी और यहां तक कि पी.वी. नरसिंह राव ने भी दबाव में आने पर बार-बार अमेरिका पर हमला किया। राजीव ने तो यहां तक कहा था कि 'नानी याद करा देंगे।' नरसिंह राव ने भी संसदीय बहस में ऐसा ही कुछ कहा था। बाद में विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दूतावास के समक्ष इस बारे में कहा था कि यह जुबान फिसलने का मामला था। तत्कालीन अमेरिकी राजदूत विलियम क्लार्क जूनियर ने नाराजगी में हमें में कुछ संपादकों से कहा था, 'क्या उनकी जुबान 15 मिनट तक फिसलती रही?' वह भारत का अमेरिका विरोधी शीतयुद्ध का समय था। अब हम एक अलग दौर में जी रहे हैं जहां लगातार तीन भारतीय प्रधानमंत्रियों और पांच अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने हमारे रिश्तों को 21वीं सदी के सर्वाधिक अहम द्विपक्षीय रिश्ते करार दिया है। भारत और अमेरिका एक दूसरे को रणनीतिक साझेदार के रूप में देखते हैं। वर्ष 2023 में मोदी की आधिकारिक अमेरिका यात्रा के दौरान कही गई कुछ बातें प्रासंगिक हैं। मोदी ने कहा था, 'हमने जो अहम निर्णय लिया है और उन्होंने हमारी व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय जोड़ा है।' जो बाइडन ने इसे 'दुनिया की सबसे महत्त्वपूर्ण साझेदारियों' में शामिल बताया था जो मजबूत है, करीबी है और हालिया इतिहास की सबसे जीवंत साझेदारी है। 6,500 शब्दों के संयुक्त वक्तव्य का यह हिस्सा भी बहुत खूब है: 'मानवीय उपक्रम का कोई भी कोना इन दो महान देशों की साझेदारी से अछूता नहीं है, जो सागर से सितारों तक विस्तारित है।'

इससे अमेरिकी विदेश विभाग पर भाजपा के हमले को समझा जा सकता है। यकीनन कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों पक्षों से उच्चतम स्तर पर इस रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं है।

तो दो महान ताकतें जिन्होंने एक दूसरे को बार-बार अहम रणनीतिक साझेदार के रूप में सराहा है, उन्हें इस विरोधाभास को कैसे दूर किया जाए? कांग्रेस पार्टी भी अब इसमें शामिल हो गई है और उसने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वह अपने 'दोस्त अदाणी को बचाने के लिए' एक अहम रणनीतिक रिश्ते को नष्ट कर रहे हैं। यह आरोप भी इस समय के विरोधाभासों में एक और विडंबना है। क्योंकि मनमोहन सिंह के परमाणु समझौते वाले दौर को छोड़ दिया जाए तो वह अमेरिका विरोधी रही है।

यह विपक्ष का काम है कि वह सरकार के विरोधाभासों का लाभ उठाए। परंतु सरकार इस रिश्ते को जिसे वह मूल्यवान मानती है उसे दांव पर लगाए बिना संतुलन कैसे कायम करेगी? इसे यह कहकर नहीं टाला जा सकता है कि पार्टी का अपना नजरिया है और सरकार अपना काम करती रहेगी। भारत और अमेरिका भले ही दोस्त बन गए हों लेकिन अमेरिका विरोध को हमेशा आम जनता का साथ मिला है। हाल के समय में ट्रंप अपने डीप स्टेट और उसके अनेक 'षडयंत्रों' की जिस तरह आलोचना की है उससे यह मुद्दा और तेजी से उभरा है। साथ ही वैश्विक व्यापार को डॉलर से मुक्त करने के विचार ने भी जोर पकड़ा है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर चुके हैं।

हमारा अमेरिका विरोध इतना मजबूत है कि कई समझदार और प्रभावशाली लोग ब्रिक्स करेंसी के विचार को लेकर बहुत उत्साहित हैं, भले ही यह चीन की मुद्रा युआन का ही एक और नाम हो। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका विरोध शायद सबसे सुरक्षित विचारधारा है जिसे प्रदर्शित किया जाए। करीबी साझेदारियों में भी संदेह और विवाद की स्थिति बनती है। बाइडन की विदाई करीब है और दोनों पक्ष एक दूसरे को दोषी मान रहे हैं। पन्नून मुद्दे पर अमेरिका ने जोर लगाया और ओसीसीआरपी मुद्दे पर भारत ने जवाब दिया। आप एक मित्र के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यह सवाल दोनों एक दूसरे से पूछ रहे हैं।

क्या मोदी सरकार या भाजपा इससे अलग ढंग से निपट सकती थी? अगर कमला हैरिस चुनाव जीततीं तो अलग ढंग से बात होती? इस बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है। मेरा कहना है कि क्या अमेरिका ने इस मामले को बेहतर संभाला?

अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी के कुछ वक्तव्यों को देखिए। जिस समय भारत पहले ही निज्जर-कनाडा मामले की तुलना में पन्नून मामले पर अलग तरह से उत्तर दे रहा था तब क्या गार्सेटी का लक्ष्मण रेखा का उल्लेख करना कूटनीतिक या वास्तविक तौर पर आवश्यक था? या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया उनका वक्तव्य कि अमेरिका आतंकवाद के मसले पर कथनी और करनी में अंतर करता है। हमारी तरह उनका मुल्क भी जानता है कि कैसे आतंकवाद की कथनी करनी में बदल सकती है। तीन दशकों में पहली बार किसी अमेरिकी राजदूत ने भारत में ऐसी बातें कीं।

हम कह सकते हैं कि गार्सेटी मुंबइया गानों पर जस्टिन ट्रूडो से बेहतर डांस कर सकते हैं, भले ही दोनों के वस्त्र पालिका बाजार के एक ही दर्जी के सिले क्यों न नजर आते हों। इक्कीसवीं सदी में आप फिल्मी संगीत या ढोल पर नाचकर भारतीयों का दिल नहीं जीत सकते। खासकर तब जबकि आप उनको आतंकवाद के मसले पर कथनी-करनी का भेद बता रहे हों।

इसके लिए किसी एक व्यक्ति, संस्था या कार्रवाई को दोष नहीं दिया जा सकता है। हकीकत यह है कि बाइडन के शासन के आखिरी महीनों में रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो गया। मेरा मानना है कि भाजपा भी जैसे को तैसा जवाब दे रही है लेकिन यकीनन वह अपनी सरकार के साथ मशविरा नहीं कर रही है। वे ट्रंप के सत्ता संभालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हरित क्रांति की अनचाही विरासत

हरित क्रांति ने देश की किस्मत बदलने में महती भूमिका निभाई, लेकिन अब इसका चक्र उल्टा घूम रहा है। इसके दुष्परिणाम उस समय नीति निर्माताओं ने सोचे भी नहीं होंगे। आज जब किसान आए दिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सीमाओं पर डेरा डाल रहे हैं तो1960 के दशक की हरित क्रांति के परिणाम अपर्याप्त बिजली आपूर्ति, पानी का संकट, लगातार गिरती मिट्टी की गुणवत्ता, वायु प्रदूषण और तेजी से बढ़ती मुफ्त योजनाओं की संस्कृति जैसे बड़े संकट के रूप में सामने आ रहे हैं।

हरित क्रांति ने भारत को जहां अकाल के जबड़े से बाहर निकाला वहीं, सार्वजनिक कानून अथवा अमेरिका से आयातित पीएल 480 गेहूं पर निर्भरता जैसे अपमान से बचाया और हमेशा तंगदस्ती में जीवन गुजारने वाले हालात से बाहर निकाला। दुर्भाग्य से जिन नीतियों ने हरित क्रांति को सफलता के शिखर पर पहुंचाया, वे ही आज न चाहते हुए भी नुकसानदेह साबित हो रही हैं और केंद्रीय सत्ता उनसे बचाव के उपाय ढूंढने के लिए संघर्ष कर रही है। ये संकट सरकार द्वारा किसानों को अधिक से अधिक गेहूं एवं चावल की फसलें उगाने के लिए शुरू की गई मुफ्त बिजली, सब्सिडी पर उर्वरक और एमएसपी की गारंटी अथवा आ धिकारिक मंडियों में उपज बेचने का प्रावधान जैसी प्रोत्साहन योजनाएं हैं, जो आज असहनीय बोझ बन रहे हैं। एमएसपी को ही ले लें। उपज को बाजार दर पर खरीदने की यह व्यवस्था किसानों को व्यापारियों के उत्पीड़न या शोषण का शिकार होने से बचाने के लिए लायी गई थी। लेकिन, शक्तिशाली किसान लॉबी के दबाव में लगातार इसे आगे बढ़ाया गया और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अब अधिकतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का रूप ले चुकी है। आज सरकार देश में वार्षिक स्तर पर पैदा होने वाले कुल गेहूं और चावल का 30 से 40 प्रतिशत तक एमएसपी पर खरीद रही है। देश में 22 अन्य फसलें भी एमएसपी के दायरे में आती हैं, लेकिन सरकार उन्हें न के बराबर ही खरीदती है। कभी-कभी राज्य सरकारें एमएसपी पर भी प्रीमियम देती हैं। मध्य प्रदेश इसका एक उदाहरण है। इस व्यवस्था से सरकारों की परेशानी और बढ़ जाती है। फसलों की बिक्री के लिए एमएसपी जैसी नीतियों का बढ़े किसानों ने खूब फायदा उठाया और सीमांत या छोटे किसान इससे वंचित ही रहे। देश में ऐसे सीमांत किसानों की संख्या 80 प्रतिशत है। वर्ष 2020 में मोदी सरकार द्वारा कृ षि क्षेत्र को नियंत्रण से मुक्त करने के प्रयासों के तहत लाए गए तीन कानूनों से देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। इन कानूनों के माध्यम से सरकार ने किसानों को अपनी उपज मंडियों के नेटवर्क से बाहर भी बेचने की इजाजत दी थी। फसलों को सीधे निजी व्यापारियों को बेचने की व्यवस्था भी इन कानूनों में की गई थी। अनुबंध पर खेती के रास्ते खोले गए थे और कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया था। कृषि उपज की भंडारण सीमा को भी नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था।

जिंदगीनामा
कनिका दत्ता

उपरोक्त व्यवस्था करने वाले कानून संसद में पर्याप्त चर्चा के बिना और कृषि लॉबी के सलाह-मशविरे के बिना ही पारित कर दिए गए थे, जिनके विरोध में किसानों, मंडी बिचौलियों और किसान संगठनों ने दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं पर तंबू गाड़ कर डेरा डाल दिया और एक साल से अधिक समय तक विरोध प्रदर्शन किया। सरकार को पीछे हटने को मजबूर करने का अंजाम यह हुआ कि कृषि लॉबी एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग करने लगी। यदि सरकार यह मांग मान लेती है तो इससे सरकार के खजाने पर असहनीय बोझ पड़ेगा। एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए खड़ा हुआ बवाल हरित क्रांति के अनचाहे नतीजों का केवल एक पहलू है। मुफ्त अथवा भारी सब्सिडी पर पानी, बिजली और उर्वरक जैसी चीजें उपलब्ध कराने से एक और बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। इन चीजों पर लगातार प्रोत्साहन पैकेज बढ़ते जाने के कारण हरियाणा और पंजाब में किसान अधिक से अधिक धान उगाने के लालच में पड़ गए। जबकि सब जानते हैं कि बहुत अधिक पानी की खपत वाली यह फसल प्राकृतिक रूप से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए उपयुक्त नहीं है। दशकों से इस फसल के उत्पादन के कारण यहां पराली जलाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। प्रत्येक वर्ष फसल कटाई के बाद जब किसान पराली जलाते हैं तो उसका धुआं दिल्ली-एनसीआर के लिए मुसीबत खड़ी करता है और वायु प्रदूषण के कारण यहां लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है।

गिरते भूजल स्तर को संभालने के लिए वर्ष 2009 से धान की रोपाई को मॉनसून सीजन के साथ शुरू किया गया, ताकि वर्षा जल से सिंचाई और कम से कम भूगर्भीय जल की जरूरत पड़े। लेकिन, इसका परिणाम यह हुआ कि फसल देर से कटने लगी और आगे रबी की फसल बोने को खेत खाली करने के लिए किसानों के पास समय ही नहीं बचता। इसके लिए उन्होंने सस्ता और जल्दी वाला समाधान ढूंढ निकाला और वे धान की पराली को खेतों में ही जलाने लगे, लेकिन इससे वायु प्रदूषण के रूप में गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया। इसी प्रकार उर्वरकों का मामला है, जिसने खेती पर और गंभीर दुष्प्रभाव डाले हैं। वार्षिक स्तर पर कुल उर्वरकों पर दी जाने वाली 1.88 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी का दो-तिहाई केवल यूरिया पर खर्च होती है। इसने इस मूल्य नियंत्रित उर्वरक के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे मिट्टी की पोषकता में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। लगभग एक दशक से यूरिया की कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि किसान पोटेशियम और फॉस्फेट के बजाय यूरिया का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि पंजाब खेती में अपनी आवश्यकता से 61 प्रतिशत अधिक यूरिया उपयोग कर रहा है। इस लेख में कहा गया है, 'यह बहुत ही हास्यास्पद है कि यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी अनाज की उपज बढ़ाने से ज्यादा वातावरण में जहर घोल रही है।'

आजादी के फौरन बाद कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों ने किसानों को मुफ्त या उदार सब्सिडी पर बिजली उपलब्ध करानी शुरू की थी। इसका सीधा प्रभाव दिवालिया होतीं राज्य स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) पर देखा जा सकता है और जिन्होंने अपने वित्तीय संकट से निपटने के लिए काफी संघर्ष किया। पैसे की कमी के कारण वे अपने आधारभूत ढांचे को उन्नत नहीं कर सकीं। नतीजतन जब बिजली की मांग चरम पर होती है तो वे हाथ खड़े कर देती हैं। लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण उद्योग वैक ल्पिक स्रोतों पर निर्भर हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा तैयार तथा करदाताओं की ओर से वित्तपोषित पांच बेलआउट पैकेज भी नाकाफी साबित हुए और विद्युत व्यवस्था की तस्वीर नहीं बदली। तमाम वित्तीय समर्थन के बावजूद आज खेती हजारों छोटे किसानों के लिए घाटे का सौदा बन गई है। सरकार द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं के हितों के लिए व्यापारियों पर आवधिक नियंत्रण और किसानों को वित्तीय सहयोग की योजनाओं ने हालात को और खराब बना दिया है। मोदी सरकार ने इसका हल प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी के तौर पर निकाला था, जो सीधे उनके खाते में जाती है। हरित क्रांति से संबंधित मुफ्त योजनाओं की तरह ही इस वित्तीय सहायता वाली सब्सिडी योजना को वापस लेना भी असंभव होगा, जो मुसीबत को और बढ़ाएगा ही।

आपका पक्ष

न्यायिक तंत्र की क्षमता व दक्षता बढ़ाने की जरूरत

त्वरित और किफायती न्याय का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बुनियादी शर्त है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यह बात सैद्धांतिक तौर पर भले ही बार-बार दोहराई जाती हो, लेकिन अफसोसजनक है कि लोगों को न्याय के लिए सबसे अधिक तारीख ही मिलती है। आज देश की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित हैं। इसके लिए न्यायिक तंत्र की क्षमता बढ़ाने तथा मुकदमों के निपटारे की समय-सीमा तय करने की जरूरत है। देश में कम से कम 10 हजार नई अदालतों का गठन जरूरी है, वहीं न्यायाधीशों के खाली पदों को भरना भी जरूरी है। न्यायिक सुधार के लिए पर्याप्त वित्तीय आवंटन के अलावा, न्यायतंत्र को आधुनिक तकनीक से लैस करने की जरूरत है, ताकि जरूरत के मुताबिक जजों की नियुक्ति और संसाधनों की व्यवस्था की जा सके। पारिवारिक और वैवाहिक विवादों के दीवानी

देश की अदालतों में लंबित मामलों के निपटान के लिए नई अदालतों के गठन के साथ न्यायधीशों की नियुक्ति आवश्यक है

मामले तो मध्यस्थता के जरिये अदालतों के बाहर ही बेहतर तरीके से सुलझाने पर जोर देना चाहिए। पूरे देश में लोक अदालतों व त्वरित अदालतों (फास्ट ट्रैक) की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए। अदालतों को मुकदमों के अंबार से निजात दिलाने के लिए एक 'राष्ट्रीय मुकदमा नीति' बनाई जाए व लंबित मुकदमों की औसत अवधि निर्धारित की जाए।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

भारत में अरबपतियों की तेजी से बढ़ती संख्या

भारत में अरबपतियों की तेजी से बढ़ती संख्या और उनकी संपत्ति में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार, पिछले वित्त वर्ष में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस आंकड़े ने भारत को अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर ला दिया है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था उद्यमियों के लिए अवसरों का खजाना साबित हो रही है। हालांकि यह वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र पर आधारित है जो इसे चीन जैसे मैन्युफैक्चरिंग-केंद्रित विकास मॉडल से अलग बनाता है। सेवा क्षेत्र में भारत की ताकत इसके उद्यमियों को अधिक रचनात्मकता और लचीलापन प्रदान करती है। तकनीक और ऊर्जा परिवर्तन के साथ यह क्षेत्र अरबपतियों के लिए नए अवसर पैदा कर रहा है। वैश्वीकरण के बदलते स्वरूप में भारत को भी लाभ पहुंचा रहा है। डिजिटल इंडस्ट्री और सामाजिक उद्यमिता के जरिये भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान भी बना सकता है। इस संपत्ति में वृद्धि के साथ कई चुनौतियां भी हैं। इनमें सबसे बड़ी चिंता है कि अत्यधिक धन का कुछ लोगों तक सीमित रह जाना। अगर मध्य वर्ग तेजी से नहीं बढ़ा तो यह असमानता आर्थिक विकास को बाधित कर सकता है। इसके अलावा, भारतीय कंपनियां अभी उस गति से वैश्विक स्तर पर विस्तार नहीं कर रही हैं, जिसकी आवश्यकता है। अंततः भारत में अरबपतियों की संख्या और संपत्ति में हो रही वृद्धि उसकी आर्थिक प्रगति का प्रमाण है। लेकिन इस प्रगति को समावेशी और टिकाऊ बनाना आवश्यक है।

अमरजीत कुमार, हजारीबाग

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

नई दिल्ली में रविवार को क्षय रोग के प्रति जागरूकता के लिए संसद के सदस्यों ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। इनमें दो टीमें लोक सभा अध्यक्ष 11 और राज्य सभा सभापति 11 में से लोक सभा की टीम विजयी हुई। टीम के कप्तान अनुराग ठाकुर तथा अन्य सदस्य विजयी ट्रॉफी के साथ।

चिंतन

ईवीएम की प्रमाणिकता पर रोना बंद करें पार्टियां

कांग्रेस को अपनी सियासत के एजेंडे की समीक्षा करनी चाहिए। सत्ता पाना ही राजनीति का ध्येय नहीं होना चाहिए। देश के लिए राजनीतिक प्रगतिशीलता आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि देश की राजनीति जितनी अधिक दूरदर्शी होगी, राष्ट्र उतनी ही उन्नति करेगा। दुर्भाग्य से कुछ वर्षों से कांग्रेस की राजनीति या तो ठहर सी गई है या फिजूल के मुद्दों पर केंद्रित हो गई है। कांग्रेस की राजनीति ईवीएम, जाति गणना, संविधान, अडाणी आदि ऐसे मुद्दों पर अटक गई है, जिससे आमजन का कोई सरोकार नहीं है। यही कारण है कि इन अनुत्पादक मुद्दों पर कांग्रेस नीत इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दल अलग राय रख रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के सहयोगी व जम्मू-कश्मीर में गठबंधन के घटक नेशनल कान्फ्रेंस के नेता व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस से दो टूक कहा है कि कांग्रेस चुनाव परिणाम को स्वीकार कर ईवीएम पर रोना बंद करे। हाल के चुनाव परिणामों में महाराष्ट्र व हरियाणा में कांग्रेस व उसके गठबंधन एमवीए को हार मिली, जबकि जम्मू-कश्मीर व झारखंड में जीत मिली। लेकिन कांग्रेस हरियाणा व महाराष्ट्र में हार के लिए ईवीएम को दोष दे रही है। ठीक उसी समय जम्मू-कश्मीर व झारखंड में जीत को गठबंधन की जीत न मानकर क्रमशः नेशनल कॉन्फ्रेंस व झारखंड मुक्ति मोर्चा की विजय मान रही है। हार व जीत को निरपेक्ष भाव से स्वीकार न कर पाने के चलते कांग्रेस खुद को पराजित ही मान रही है। ईवीएम राग पर कांग्रेस को अपने सहयोगी उमर अब्दुल्ला की बात सुननी चाहिए। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर तीखी आपत्ति को खारिज करते हुए कहा है कि 'ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप चुनाव जीतें तो परिणाम स्वीकार कर लें और जब हार जायें तो ईवीएम पर दोष मढ़ दें। जब इसी ईवीएम के इस्तेमाल से संसद में आपके सौ से अधिक सदस्य पहुंच जाते हैं और आप इसे अपनी पार्टी के लिए जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप कुछ महीने बाद पलटकर यह नहीं कह सकते कि हमें ये ईवीएम स्वीकार नहीं हैं।' इससे पहले उमर ने सेंट्रल विस्टा (नया संसद भवन) के मुद्दे पर भी कांग्रेस के विरोध को यह कर खारिज कर दिया था कि कांग्रेस केवल विरोध के लिए नए संसद भवन का विरोध कर रही थी। विरोध में इतना अतिरेक था कि कई कांग्रेस नेता नए संसद भवन में प्रवेश न करने की कसमें खा रहे थे। आज सब सेंट्रल विस्टा जा रहे हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भविष्य की संसदीय जरूरतों को ध्यान में रखकर प्लान किया गया है। परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी, पुराने संसद भवन की क्षमता कम है, इसलिए हमें नए संसद भवन की आवश्यकता थी ही। मोदी सरकार ने इससे पहले ही नया भवन तैयार कर दिया। कांग्रेस के हाय-तौबा का कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस खुद सरकार में रहती तो नया संसद भवन बनाती। आज अडाणी मुद्दे पर भी इंडिया ब्लॉक के कई सहयोगी कांग्रेस के साथ नहीं हैं। ऐसे ही आज के युथ को जाति-पाति से कोई मतलब नहीं है, ऐसे में जाति गणना के एजेंडे उन्हें नहीं लुभाते। राहुल गांधी जाति गणना पर अटके रहते हैं। अगर पार्टियों को मतदान तंत्र पर भरोसा नहीं है तो उन्हें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यदि कांग्रेस को ईवीएम से दिक्कत है, तो उसे लेकर उसका रुख एकसमान रहना चाहिए। जीत व हार दोनों में रुख एक हो। सुप्रीम कोर्ट व चुनाव आयोग ने ईवीएम की प्रमाणिकता को लेकर संदेह को निराधार पाया है। कांग्रेस को ईवीएम जैसे अटके मुद्दों से बाहर निकलकर जन सरोकार के मसलों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

दृष्टिकोण
ओमकार चौधरी

भारत क्या करेगा बांग्लादेश में?

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और दूसरे समुदायों के विरुद्ध जो हिंसा शुरू हुई थी, वह थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका का दौरा किया है। उनकी अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाक़ात हुई। माना जा रहा है कि वहां अल्पसंख्यकों पर निरंतर हो रहे हमलों पर भारत सरकार की चिंता से उन्होंने अवगत कराते हुए कहा कि यह हिंसा जल्दी से जल्दी रुकनी चाहिए। इस्कान से जुड़े हिंदू पुजारी चिन्मय प्रभु दास की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने बात की है, जिसे लेकर भारत चिंतित है। मिस्री के दौरे का फल यह निकला कि दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ता ही जा रहा था, उसमें कमी देखी जा रही है। सोलह दिसंबर को बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल कोलकाता के दौरे पर आ रहा है। 16 दिसंबर वह तारीख है, जब भारत ने 1971 में पाकिस्तानी सेना को हराया था, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यह प्रतिनिधिमंडल पूर्वी कमांड में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। बांग्लादेश न केवल भारत का एक अहम पड़ोसी देश है, बल्कि उसके हमारे साथ सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रिश्ते भी हैं। 1947 से पहले वह भारत का हिस्सा था। हमारे देश को अंग्रेजी शासन से आज़ादी विभाजन की बड़ी क़ीमत पर मिली थी। पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति संग्राम छिड़ा, उसमें भारत ने भी बेहद अहम भूमिका निभाई। यह अलग बात है कि नया बांग्लादेश अस्तित्व में आने के बावजूद वहां जमात से लेकर बहुत से कट्टरपंथी संगठन पनपते रहे, जो वहां भी अस्थिरता की वजह बनते रहे और जिसने वहां भारत विरोधी प्रोपेगैंडा जमकर चलाया। ख़ासकर हिंदू अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा। यही कारण है कि 1947 में पूर्वी पाकिस्तान में जो पच्चीस प्रतिशत हिंदू हुआ करते थे, उनकी संख्या लगातार घटती गई। आज यह आठ नौ प्रतिशत बची है। यही हाल पाकिस्तान में हुआ है। वहां तो यह संख्या बहुत कम हो चुकी है। अफ़ग़ानिस्तान में तो अब हिंदू-सिख नाम मात्र के ही बचे हैं। उनके धर्म स्थलों को या तो नष्ट कर दिया गया अथवा उन पर कब्ज़ा करके उनका रूप स्वरूप बदल दिया गया।

भारत की यह नीति रही है कि वह दूसरे देशों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। कोई देश हमारे अंदरूनी मामलों में दखलांदाजी करे, इसकी भी इजाजत नहीं देता है। बड़े अफ़सोस की बात यह है कि किसी

> बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और दूसरे समुदायों के विरुद्ध जो हिंसा शुरू हुई थी, वह थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ढाका का दौरा किया है। उनकी अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भी मुलाक़ात हुई। माना जा रहा है कि वहां अल्पसंख्यकों पर निरंतर हो रहे हमलों पर भारत सरकार की चिंता से उन्होंने अवगत कराते हुए कहा कि यह हिंसा जल्दी से जल्दी रुकनी चाहिए। इस्कान से जुड़े हिंदू पुजारी चिन्मय प्रभु दास की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने बात की है, जिसे लेकर भारत चिंतित है। मिस्री के दौरे का फल यह निकला कि दोनों देशों के बीच जो तनाव बढ़ता ही जा रहा था, उसमें कमी देखी जा रही है।

जमाने में अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो अधिकांश हिस्से कभी भारत वर्ष का हिस्सा थे, वहां रह रहे कट्टरपंथी अब भारतीयों-हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा और नफ़रत का सहारा ले रहे हैं। कट्टरपंथी तत्व यह जानते हैं कि भारत किसी देश में सीधे हस्तक्षेप की नीति पर नहीं चलता है जब तक कि उसकी संप्रभुता, एकता अखंडता और नागरिकों की जान-माल पर आंच नहीं आ रही हो। इसका अनुचित फायदा उठाकर ऐसी अवांछित हरकतें और हिंसा वहां की जाती रही है, जिससे भारत के अपने नागरिकों को पीड़ा पहुंचे और यहां की सरकारों को मुश्किलों में डाला जा सके। राजनीतिक कारणों से इस

तरह की हरकतों को वहां की सरकारें भी बढ़ावा देती रही हैं। ऐसे अनेक उदाहरण अतीत में ख़ासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखने को मिले हैं। यह सब इसके बावजूद किया जाता है कि भारत संकट के समय हमेशा मदद का हाथ बढ़ाता रहा है। जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से वहां के हालात बहुत पेचीदा हो गए हैं। जमात-ए-इस्लामी, बीएनपी और कुछ उग्रपंथी संगठनों ने जमकर हिंसा की है। जब भी अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध की जा रही हिंसा पर सवाल उठाए जाते हैं तब उनका तर्क होता है कि हिंसा शेख हसीना को सपोर्ट करने वालों के विरुद्ध हो रही है। यह पहली बार है, जब पश्चिमी जगत की भी बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो वहां हो रही हिंसा की चर्चा करते हुए यहां तक कहा है कि उनकी सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि हिंदुओं पर हमले होंगे तो वह सहन नहीं करेंगे। उन्हें हर हाल में सुरक्षा दी जाएगी। दरअसल, ट्रंप और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस एक-दूसरे को नापसंद करते हैं। ट्रंप जब हिलेरी क्लिंटन को परास्त कर अपने पहले कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए थे, तब यूनुस पेरिस में थे और उन्होंने उसे अमेरिका के लिए काला दिवस करार दिया था। इसलिए यह मानकर चला जा रहा है कि बीस जनवरी को जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कुछ जानकारों का मानना है कि शेख हसीना सरकार की देर-सवेर बहाली हो जाएगी। भारत ठंडे दिमाग़ से काम ले रहा है और ट्रंप के कार्यभार संभालने की प्रतीक्षा कर रहा है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफ़ग़ानिस्तान में घट रही घटनाएं हों, उनका भारत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वहां उन पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। मोदी सरकार इन देशों में होने वाली घटनाओं के मद्देनजर सीएए क़ानून भी लेकर आई थी, उसे लागू भी किया जा चुका है। धार्मिक आधार पर यदि हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के विरुद्ध वहां पक्षपात या अत्याचार होते हैं तो आज़ादी और विभाजन के पचहत्तर वर्ष बाद भी वह भारत लौट सकते हैं। वहां की नागरिकता हासिल करने के लिए जो शर्तें हैं, उनका पालन कर आवेदन कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा मानवीय पहलू वाला क़ानून शायद ही किसी देश में हो। हालांकि इस पर यहां जमकर राजनीति हो चुकी है। कुछ राजनीतिक दल झूठ फैलाकर समाज में तनाव पैदा कर हिंसा भड़काने की साजिशें भी रच चुके हैं। आश्चर्य का विषय है कि यही राजनीतिक जमात हमास के समर्थन में बयान जारी करता है परंतु जब बांग्लादेश पाकिस्तान अथवा अफ़ग़ानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमलों की सूचना आती हैं तो चुप्पी साध लेता है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने पर भी ये चुप्पी ही साधे हुए हैं। वहां कट्टरपंथी जमातें इस तथ्य से भली-भांति अवगत हैं कि भारत की अपनी राजनीतिक समस्याएं क्या हैं और यहां किस तरह राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल तुष्टिकरण की राजनीति में उलझे हुए हैं।

जैसे ही वहां कोई नई घटना घटती है और उसके विजुअल्स सोशल मीडिया में आते हैं, वैसे ही ख़ासकर मोदी और भाजपा समर्थक राष्ट्रवादी अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देते हैं। उनका सीधा एक ही सवाल होता है कि हमने क्या इसी दिन के लिए मोदी जी को वोट दिया था? वो बांग्लादेश के हिंदुओं को क्यों नहीं बचा रहे। हमला क्यों नहीं कर रहे। वहां जो दुष्ट हिंसा में लिप्त हैं, उन्हें सबक क्यों नहीं सिखा रहे। ऐसे अति उत्साही और चिंतित लोगों को संभवतः अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बारीकियों की उतनी समझ नहीं है। उन्हें नहीं पता कि भारत यदि कोई सीधी कार्रवाई करेगा तो उसके किस तरह के नतीजे हो सकते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

विजय दिवस
रमेश शर्मा

तेरह दिन में ही टूट गया था पाकिस्तान

पाकिस्तान कभी भारत का ही हिस्सा था। वहां रहने वाले लोग भी भारतीय पूर्वजों के वंशज हैं। फिर भी वे लोग दिन-रात भारत के विरुद्ध विष वमन और भारत को मिटाने का दंभ भरते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने जन्म के बाद से ही नहीं, अपितु अपने गर्भकाल से जन्मदाता भारत की धरती पर रक्तपात का षड्यंत्र कर रहा है। पाकिस्तान के इन्हीं षड्यंत्रों का परिणाम था 1971 का युद्ध, जो भारत पर थोपा था। इसी युद्ध में जन्म हुआ था संसार में एक नये देश बांग्लादेश का। लेकिन वह विचारणीय है जिस भारत के जवानों के बलिदान से बांग्लादेशका जन्म हुआ था वही बंगलादेश, पाकिस्तान से मिलकर भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है । 1971 का वह युद्ध कुल तेरह दिन तक चला था। दुनिया के इतिहास में यह सबसे छोटा निर्णायक युद्ध माना जाता है। इस युद्ध समापन के साथ एक नये देश का उदय हुआ जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की धरती भी कभी भारत भूभाग बंगाल प्रांत का अंग रही है। लेकिन 1947 में भारत की धरती के इस हिस्से ने भी भारत से अलग होकर पाकिस्तान का नाम स्वीकार कर लिया था और वह प्रक्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। लेकिन भाषा को लेकर मतभेद पहले दिन से था। सल्तनत काल में चले बलपूर्वक धर्मांतरण अभियान में बंगाल के निवासियों की पूजा उपासना पद्धति तो बदल गई थी पर भाषा के प्रति लगाव कम न हुआ। बंगाली समाज ने अपना धर्म और राष्ट्रीयता बदलकर पाकिस्तानी नाम तो स्वीकार कर लिया था लेकिन अपनी मातृभाषा से लगाव न छोड़ा। वे चाहते थे कि उनकी भाषा बंगाली ही रहे। जबकि पाकिस्तानी शासक उनकी यह बंगाली पहचान भी बदलना चाहते थे। पाकिस्तान की सरकार बलपूर्वक उर्दू और अरबी का दबाव बना रहे थे। संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। इसको लेकर 1948 से आंदोलन आरंभ हो गये थे, जिसका दमन पाकिस्तान की सरकार और सेना करती रही थी। 1970 आते-आते सैनिकों के जुर्म और बंगालियों का दमन और पलायन दोनों बढ़ गया। 25 मार्च 1971 को बंगला अभियान के नेता शेख मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका भारत ने विरोध जताया और मुक्ति वाहनी को नैतिक समर्थन देने की घोषणा भी कर दी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंदोलन को खुला समर्थन दिया और जो लोग भारत आ रहे थे उन्हें भी पर्याप्त संरक्षण दिया। पाकिस्तान ने अपनी समस्या का ठीकरा भारत के सिर फोड़ा और दुनिया में यह प्रचार किया कि भारत अशांति फैला रहा है। इन तमाम कारणों से आरंभ हुए युद्ध की तिथि भले तीन दिसम्बर 1971 मानी जाती हो पर पाकिस्तान ने अपनी ओर से यह युद्ध 25 नवम्बर 1971 को ही आरंभ कर दिया था जब लाहौर में ऐसी ही 'क्रश इंडिया' रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो ने बाकायदा युद्ध की घोषणा की थी और उसकी तीनों सेनाओं ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान ने जहां करांची बंदरगाह पर नौ सेना बेड़े तैनात किये वहीं सीमा पर फौज बढ़ा कर घुसपैठ शुरू कर दी थी। भारत युद्ध तो नहीं चाहता था पर युद्ध से निबटने के लिए पूरी तरह तैयार था। दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगा कि उसकी घुसपैठ सफल हो रही है। इससे उत्साहित होकर उसने दो और तीन दिसम्बर 1971 की रात भारत पर हवाई हमला बोल दिया । इस बमबारी से पूरा भारत सकते में आ गया। तीन दिसम्बर को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया कि वह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जबाब दे। 15 दिसम्बर को भारत ने ढाका पर आधिपत्य होने की अधिकृत घोषणा की। इसी के साथ वहां तैनात पाकिस्तान कमांडर ने फौज के आत्मसमर्पण का प्रस्ताव दिया जिसे 16 दिसम्बर को माना गया और भारत ने अपनी ओर से युद्ध विराम की घोषणा कर दी । पाकिस्तान का अंग बने बंगाल के निवासियों की सहायता करने में भारत ने अपने लगभग चार हजार सैनिकों का बलिदान दिया। दस हजार से अधिक घायल हुए। लगभग एक करोड़ शरणार्थी भारत आये। आधी शताब्दी से भी अधिक इस अवधि में ऐसा कोई वर्ष नहीं बीता जब भारत ने बांग्लादेश को सहायता न दी हो। बदले में क्या मिला? बांग्लादेश चीन की गोद में बैठ गया। पाकिस्तान के इशारे पर काम करने लगा। इन दिनों बांग्लादेश में केवल मंदिर ही नहीं तोड़े जा रहे बल्कि भारत विरोधी नारे भी लग रहे हैं। बांग्लादेश बनने के बाद से कट्टरपंथी जैसी भारत की डेमोग्राफी बदल रहे हैं वह चौंकाने वाली हैं। असम, बंगाल और झारखंड के अनेक गांव ऐसे हैं जहां से हिन्दू पलायन कर गये और बंगलादेशी आकर बस गये।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मंदिर जैसे उपासना स्थल क्यों बनाए जाते हैं?

संकलित
दर्शन

जब ईश्वर का वास हृदय में माना गया है, तो मंदिर जैसे उपासना स्थल क्यों बनाए जाते हैं? मंदिरों की स्थापना के पीछे उद्देश्य था कि पूजा, अर्चना और यज्ञ आदि द्वारा पवित्र तन्मात्रओं यानी पंचभूतों के सूक्ष्म रूप की सृष्टि की जाए। किसी साधु हृदय व्यक्ति को पूजा का कार्यभार सौंपा जाए। स्थान का मन पर अदृश्य प्रभाव पड़ता है। चिकित्सालय में व्यक्ति को हर तरफ रोग और रोगी ही दिखते हैं। स्वस्थ व्यक्ति भी वहां अशक्त महसूस करने लगता है। हमारे शरीर से प्रतिदिन शुभ या अशुभ अदृश्य सूक्ष्म शक्ति-राशि का उत्सर्जन होता रहता है। मंदिर जाने वाला व्यक्ति काम, क्रोध और आलस्य बाहर छोड़कर ईश्वर के प्रति भक्तिभाव से जाता है। यह सामूहिक भक्ति या उपासना शुभ तन्मात्रओं व तरंगों का सृजन करती है। अतः वहां आगमन दुर्बल मन वाले मनुष्यों में ऊर्जा का संचार करता है। सज्जनों से ही प्रार्थना स्थलों की पवित्रता बनी रहती है। यदि मंदिर में असाधु व्यक्तियों का आवागमन बढ़ जाए तो स्थान अपनी पवित्रता खोने लगता है। पवित्र श्रवण मास में शिवलिंग पर दुग्ध, बेलपत्र, फल-फूल आदि चढ़ाकर पुण्य अर्जित करने की होड़ लगी रहती है। यदि ईश्वर है और वह हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होता है तो वह एक बेलपत्र, अंजुली भर दूध या एक पुष्प से भी प्रसन्न हो जाएगा। सावन के महीने से इतर भी वे दूश्य आमतौर पर मंदिरों में आम होते हैं। यदि यह व्यवस्था सुचारु न हो तो अव्यवस्था स्वाभाविक है। इसी कारण कई मंदिरों में व्यक्तिगत रूप से भोग-अर्पण की मनाही है।

एक दिन का पुण्य ही क्यूं

संकलित
प्रेरणा

निर्जला एकादशी से अगले दिन एक भिखारी एक सज्जन की दुकान पर भीख मांगने पहुंचा। सज्जन व्यक्ति ने 1 रुपए का सिक्का निकाल कर उसे दें दिया। भिखारी को प्यास भी लगी थी, वो बोला बाबूजी एक गिलास पानी भी पिलवा दो, गला सूखा जा रहा है। सज्जन व्यक्ति ने गुस्से में कहाः तुम्हारे बाप के नौकर बैठे हैं क्या हम यहां, पहले पैसे, अब पानी, थोड़ी देर में रोटी मांगेगा, चल भाग यहां से। भिखारी बोलाः बाबूजी गुस्सा मत कीजिये मैं आगे कहीं पानी पी लूंगा। पर जहां तक मुझे याद है, कल आपने निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ किया था, तथा कल इसी दुकान के बाहर मीठे पानी की छबील लगी थी और आप स्वयं लोगों को रोक रोक कर जबरदस्ती अपने हाथों से गिलास पकड़ा रहे थे, मुझे भी कल आपके हाथों से दो गिलास शर्बत पीने को मिला था। मैंने तो यही सोचा था, आप बड़े धर्मात्मा आदमी है, पर आज मेरा भरम टूट गया। कल की छबील तो शायद आपने लोगों को दिखाने के लिये लगाई होगी? मुझे आज आपने कड़वे वचन बोलकर अपना कल का सारा पुण्य खो दिया। मुझे क्षमा करना अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो। सज्जन व्यक्ति को बात दिल पर लगी, उसकी नजरों के सामने बीते दिन का प्रत्येक दृश्य घूम गया। उसे अपनी गलती का अहसास हो रहा था। वह स्वयं अपनी गद्दी से उठा और अपने हाथों से गिलास में पानी भरकर उस बाबा को देते हुए उसे क्षमा प्रार्थना करने लगा।

अंतर्मन

आज की पाती

एक साथ सभी चुनावों का औचित्य

एक देश एक चुनाव का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव को मंजूरी दे दी। इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय, सभी चुनाव लगभग 100 दिनों में कराने का प्रावधान है। इससे पहले रामनाथ कोविंद समिति को भी मंजूरी मिल गई थी। केंद्र सरकार इस बिल को अब जल्द ही संसद में भी पेश कर सकती है। इसे तैयार करने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों और अन्य बुद्धिजीवी वर्ग की सलाह भी ली होगी। इस मुद्दे पर अब फिर से राजनीति शुरू हो जाएगी। हमारे देश की राजनीति अवसरवाद की शिकार हो चुकी है, इसलिए यहां बहुत से राजनेता ही एक साथ चुनाव के लिए रजामंद नहीं होंगे। बहरहाल, लोकतंत्र का आधार ही चुनाव होते हैं। चुनाव प्रक्रिया में अगर कुछ कमियां हों तो उन्हें दूर करना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत होता है।

- विनय कुमार साहू

ट्रेंड

लौह पुरुष को नमन

देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत-शत नमन। उनका व्यक्तित्व और कृतीत्व राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुत्व भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए देशवासियों की प्रेरणादायिका बना रहेगा।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

भाजपा ने वादा नहीं निभाया

हाथरस रेप पीड़िता के परिवार को घर से बंद रखना और आरोपियों का खुलेआम घूमना बाबा साहेब के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। भाजपा सरकार ने पीड़ित परिवार को पूरी जांच पर ठेकर शिकार करने का वादा भी पूरा नहीं किया है।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

मेरी किताब 'सेव अमेरिका'

क्रिसमस आ रहा है! सबसे आकर्षक उपहार मेरी नई किताब, "सेव अमेरिका" है। कोई अन्य पुस्तक हमारे आंदोलन, हमारे अभियान और हमारे भविष्य पर प्रकाश नहीं डालती।

-डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिकी राष्ट्रपति

युवाओं की ऊर्जा

जब हम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में सोचते हैं तो हमारा पहला विचार वर्षों के अनुभव वाले व्यक्ति को ढूंढना होता है। लेकिन हम स्टार्ट-अप युग में हैं जहां युवाओं की ऊर्जा, और नवीनता अनुभव के ज्ञान और ज्ञान के लिए एक योग्य चुनौती है।

-अनिल अग्रवाल, उद्योगपति

करंट अफेयर

पाक के कपूर हाउस में राज कपूर की जयंती मनाई गई

पाकिस्तानी सांस्कृतिक और फिल्म प्रेमी बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्माता एवं अभिनेता राज कपूर की 100वीं जयंती मनाने के लिए शनिवार को पेशावर के 'कपूर हाउस' में इकट्ठा हुए और इस दौरान उन्होंने केक काटकर उनकी जयंती मनाई। आयोजन में शामिल लोगों ने राज कपूर और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के पैतृक घरों के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित करने की शिश्व बैंक की घोषणा का भी स्वागत किया। प्रसिद्ध किस्सा खवानी बाजार के पास स्थित दोनों घरों को पेशावर के भारतीय सिनेमा से गहरे संबंधों के प्रतीक के रूप में माना जाता है। 'कल्चरल हेरिटेज काउंसिल' (सीएचसी) और पुरातत्व निदेशालय खैबर पख्तूनखवा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस समारोह में कपूर की विरासत को याद करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कपूर के पाकिस्तान से संबंधों पर बल दिया और सिनेमा पर उनकी अमिट छाप की प्रशंसा की। कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर के ढाकी नलबंदी में हुआ था और 1988 में उनका निधन हो गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर 'पाक-ईरान ट्रेड एंड इवेस्टमेंट काउंसिल' के सचिव मोहम्मद हुसैन हैदरी मौजूद रहे।

ऑफ बीट

मादक पदार्थ कैप्टागन क्या है, जर्मनी में बनाया गया था

कैप्टागन एक पुराने सिंथेटिक फार्मास्युटिकल उत्तेजक का मूल ब्रांड नाम है जिसे 1960 के दशक में जर्मनी में बनाया गया था। यह एम्फेटेमिन और मेथैम्फेटामाइन का एक विकल्प था। उस समय इन दोनों का इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता था। इस दवा में सक्रिय घटक फेनेथिलीन है और शुरुआत में एडीएचडी और नींद की बीमारी नार्कोलेप्सी जैसी स्थितियों के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इसका उपयोग कानूनी रूप से उपलब्ध कुछ उत्तेजक पदार्थों के समान था, जिनका हम आज भी उपयोग करते हैं जैसे कि डेक्सम्फेटामाइन। कैप्टागन का प्रभाव एम्फेटेमाइन जैसा ही होता है। यह मस्तिष्क में डोपामाइन को बढ़ाता है, जिससे स्वास्थ्य, आनंद और उल्लास की भावनाएं पैदा होती हैं। यह ध्यान, एकाग्रता और सहनशक्ति में भी सुधार करता है। लेकिन इसके कई अवांछित दुष्प्रभाव भी हैं जैसे कि थोड़ा बहुत मनोविकार। यह दवा मूल रूप से पश्चिम एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में बेची जाती थी। यह यूरोप में कुछ समय तक काउंटर पर (बिना डॉक्टर के पर्चे के) उपलब्ध थी, उसके बाद में यह केवल डॉक्टर के पर्चे पर लिखे जाने के बाद ही मिलना प्रारंभ हुई।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

एक देश एक चुनाव

परिवर्तनकारी कदम

'एक देश एक चुनाव' पहल से भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन आ सकता है। भारत के राजनीतिक विमर्श में 'एक देश एक चुनाव' काफी बहस का विषय है। 12 दिसंबर, 2024 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने इसके विधायी प्रारूप को मंजूरी दे दी जिससे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एकसाथ तथा उसके 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनावों की संभावना पैदा हो गई है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय चुनाव प्रक्रिया को सहज बनाना, बार-बार चुनाव के कारण प्रशासनिक और आर्थिक बोझ घटाना तथा प्रशासन में सुधार करना है। 'एक देश एक चुनाव' पहल से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा नगर निगमों व पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम में परिवर्तन होगा। प्रस्तावित विधायन को संसद के वर्तमान शीत सत्र में पेश करने की योजना है। इससे सरकार का परिवर्तनकारी सुधारों पर राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श का इरादा स्पष्ट होता है। इस विधायी प्रारूप में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की 11 संस्तुतियां शामिल हैं। इन संस्तुतियों का उद्देश्य वर्तमान बिखरे हुए चुनाव कार्यक्रम के कारण आने वाली बाधाओं को संबोधित करना है जिससे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। एक प्रमुख सुझाव में लोकसभा और विधानसभा चुनावों का पहले चरण में समेकन करना और बाद में इसके 100 दिन के भीतर नगरपालिकाओं व पंचायतों के चुनाव कराना

है। सहज क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतिबद्ध क्रियान्वयन समूह सुधारों की निगरानी करेगा।

प्रस्तावित एकसाथ चुनावों में सहायता के लिए एकीकृत मतदाता सूचियों की जरूरत होगी जिसके लिए अनुच्छेद 324ए व 325 में संशोधन करने होंगे। चुनावों में काफी वित्तीय संसाधन खर्च होते हैं और एकसाथ चुनाव कराने से सुरक्षा, लाजिस्टिक्स तथा प्रशासनिक खर्चों पर आने वाला खर्च कम होगा। बार-बार चुनावों के कारण लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू रहती है जिससे विकास गतिविधियों में बाधा आती है। एकसाथ चुनाव से इसे न्यूनतम किया जा सकता है। लेकिन इस महत्वाकांक्षी सुधार के क्रियान्वयन में काफी लाजिस्टिक व संवैधानिक चुनौतियां हैं। चुनावों को एकसाथ लाने के लिए संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा जिनमें अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 व 356 शामिल हैं। इनको राज्य विधानसभाओं से सहमति दिलानी होगी। विविधतापूर्ण क्षेत्रीय हितों को देखते हुए पार्टियों के बीच राजनीतिक सहमति तैयार करना एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग को संसाधनों को जुटाना होगा जिसमें अतिरिक्त ईवीएम व वीवीपैट तथा चुनावों की तैयारी के लिए कर्मचारी व राष्ट्रव्यापी ढांचागत संरचना शामिल है। इसके साथ ही एकसाथ चुनाव से राष्ट्रीय विमर्श पर स्थानीय मुद्दों का प्रभुत्व घट सकता है जिससे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। थोड़े ही समय में राष्ट्रव्यापी चुनावों का समन्वय अनेक लाजिस्टिक चुनौतियां सामने लाता है। इसके साथ ही विधायिकाओं के बीच में ही भंग होने पर प्रशासनिक कमी दूर करने के प्रयास करने होंगे जिससे नीतिगत विकलांगता पैदा हो सकती है। हालांकि, 'एक देश एक चुनाव' प्रस्ताव क्षमता एवं खर्च के दृष्टिकोण से प्रभावशाली है, पर इसके क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक, लाजिस्टिक व राजनीतिक जटिलताओं पर बहुत सतर्कता से ध्यान देना होगा।

बांग्लादेश में पंथनिरपेक्षता पर संकट

अतिवादी विचारधाराओं की बढ़ती आक्रामकता तथा विरोध को कुचलने के कारण बांग्लादेश के एक कट्टरपंथी इस्लामवादी देश बनने का खतरा पैदा हो गया है।

हिरण्यमय कालेंकर
(लेखक, दि पायनियर के सलाहकार संपादक हैं)

यह लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत तथा सभी पंथनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक लोगों और संगठनों की कट्टर दुश्मन शक्तियां, यानी कट्टरपंथी इस्लामवादी संगठन बांग्लादेश में हावी होते जा रहे हैं। अंतरिम सरकार के नेतृत्व में ऐसे तत्वों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसका एक स्पष्ट संकेत अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक, पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा लोकतंत्र व पंथनिरपेक्षता के अडिग समर्थक शहरयार कबीर का अथक उत्पीड़न है। उन्होंने अथक रूप से 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए युद्ध-अपराधों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया। वे भयानक स्थितियों में कासिमपुर जेल में बंद हैं, जबकि उनको एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा 'प्रिजनर आफ कांसेशनेस' घोषित किया गया है तथा एक मजिस्ट्रेट ने उनको प्रथम श्रेणी देने का आदेश दिया है जिसमें एक अलग कमरा तथा अन्य सुविधायें शामिल हैं।

इसका कारण यह है कि कासिमपुर जेल पर क्षेत्राधिकार वाले गाजीपुर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने इस आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जबकि उनके हस्ताक्षर के बाद ही यह आदेश प्रभावी होगा। खबरों के अनुसार उनके द्वारा इस पर जल्दी हस्ताक्षर की संभावनायें भी नहीं दिख रही हैं। इसके परिणामस्वरूप 74 वर्षीय कबीर एक साधारण जेल में बंद हैं जिसकी फर्श जाड़े में बहुत ठंडी होती है जिससे उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। इसके पहले 20 अक्टूबर को ढाका के चीफ मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में रिमांड सुनवाई के दौरान कबीर ने शिकायत की थी कि उनको जेल में उपयुक्त चिकित्सकीय सहायता नहीं मिल रही है।

2 नवंबर को उनको शहीद ताजुद्दीन अहमद मेडिकल कालेज अस्पताल जांच के लिए ले जाया गया था। उप-निदेशक के अनुसार वे वृद्धावस्था संबंधी अनेक विकृतियों के शिकार थे और उनकी स्थति गंभीर थी। कबीर को उच्च रक्तचाप व

मधुमेह है तथा उनकी किडनी में पथरियां हैं। उनके मल से रक्त निकल रहा है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर की भूमिका को देखते हुए यह समझना कठिन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार उनको प्रथम श्रेणी का दर्जा क्यों नहीं दे रही है। यह स्थिति इस तथ्य के बावजूद जारी है कि उनकी रिहाई के लिए व्यापक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मांग की गई है। स्पष्ट रूप से इसका कारण हिफाजते इस्लाम और बांग्लादेश जमाते इस्लामी जैसे संगठनों का दबाव है।

कबीर के अभियोजन में हिफाजत का हाथ इस तथ्य से स्पष्ट है कि उनको जेल में बंद करने के लिए लगे अनेक आरोपों में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय क्राइम ट्राइब्यूनल द्वारा 20 अगस्त, 2024 को हिफाजत के संयुक्त सचिव मुफ्ती हारून इजहार चौधरी द्वारा लगाया आरोप शामिल है। इसके अनुसार शेख हसीना तथा अन्य 23 आरोपियों के साथ उन पर मानवता के खिलाफ आरोप लगाया गया है जिसमें हिफाजत के समर्थकों और सुरक्षा बलों के सदस्यों तथा अवामी लीग एक्टिविस्टों के बीच ढाका रैली में 5 मई, 2013 को हिंसक झड़पों में संलिप्तता शामिल है। यह रैली 13 सूत्रीय मांग पत्र लागू कराने के लिए हुई थी जिसमें इस्लाम के अनुसार कठोर 'ड्रेस कोड' लागू करने तथा मूर्तियों, मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन करने एवं पुरुषों व महिलाओं के एकसाथ एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने की मांगे शामिल थीं। इसके साथ ही अवामी लीग सरकार की महिला विकास नीति समाप्त करने की पैरवी की गई थी। इसके अलावा अहमदियों को 'गैर-मुस्लिम' घोषित करने की मांग भी इनमें शामिल थी। हिफाजत के इस चार्टर में कट्टरपंथी विचारधारा शामिल थी जिसका गठन 2010 में अवामी लीग सरकार के महिला विकास कार्यक्रम का विरोध करने के लिए हुआ था। इसमें संपत्ति में महिलाओं को समान अधिकार देने का वादा किया गया था।

मुख्यत: सुन्नी धर्मगुरुओं तथा 19,199 कौमी मदरसों के नेटवर्क व उसके छात्रों पर नियंत्रण करने वाले इस बांग्लादेशी संगठन की सड़कों पर लोगों को उतारने की बहुत बड़ी क्षमता है। उसके गंभीर भारत-विरोधी दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ढाका यात्रा के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शनों से हुआ था। मोदी की यात्रा बांग्लादेश स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 मार्च, 2021 को हुई थी। इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 13 लोग मारे गए थे तथा सुरक्षा बलों और अवामी लीग समर्थकों से हुई झड़पों में अनेक लोग घायल हुए थे। हालांकि, अंतरिम सरकार के सारे निर्णय हिफाजत से संचालित नहीं हैं, पर निश्चित रूप से इसका व्यापक प्रभाव है और इसकी छोटी बड़ी सभी मांगे पूरी की जाती हैं। मुक्तिधाम आश्रम तथा लालोन अकादमी, काशीपुर द्वारा आयोजित 'महती साधुसंग एवं लालोन मेला' का आयोजन 22 नवंबर, 2024 को होना था। इस मेले का संबंध नृत्य, गान तथा भोजन से है।

पूरे बांग्लादेश के बाउल गायक और भक्त इस अवसर पर एकत्र होते हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने यह आयोजन रद्द कर दिया। 23 नवंबर, 2024 को 'द डेली स्टार' में प्रकाशित एक रिपोर्ट में आश्रम और अकादमी के संस्थापक फकीर शाह जलाल के हवाले से बताया गया था कि 'सभी व्यवस्थायें की गई थीं, लेकिन प्रशासन ने आयोजन की अनुमति नहीं दी। इसके पीछे मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों की आपत्ति बताई गई थी। हालांकि, हमने बिना लाउडस्पीकरों के भीतर आयोजन की अनुमति भी मांगी, पर इससे इनकार कर दिया गया।'

आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक, रहस्यवादी कवि तथा समाज सुधारक लालोन ने एक 'बेल्टनक्षुंग' की रचना की थी जिसमें भक्ति संप्रदाय व सूफीवाद का मिश्रण था। इसमें जाति, वर्ग, नस्ल के सभी भेदों को अस्वीकार कर वैचारिक टकरावों व नस्लवाद का विरोध किया गया था। आश्चर्य नहीं कि ऐसा व्यक्ति कट्टरपंथी इस्लामवादियों को सहन नहीं हो सकता है।

द डेली स्टार की उपरोक्त रिपोर्ट में कहा गया था कि हिफाजते इस्लाम नेता मौलाना अब्दुल औवाल ने एक भाषण में प्रशासन को चेतावनी दी थी कि वह यह आयोजन रोके नहीं तो प्रदर्शनकारी इसका विरोध करेंगे। बांग्लादेश में अन्य इस्लामवादी संगठन भी अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। ढाका में 25 नवंबर को जिला कौमी मदरसा परिषद के एक सम्मेलन में बोलते हुए बांग्लादेश खिलाफत मजलिस के महासचिव मामुनुल हक ने बांग्लादेश में इस्लामी क्रांति की दिशा में 5 अगस्त को महत्वपूर्ण कदम बताया। उसने कहा कि यह देश इस्लामवादी परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। आश्चर्य नहीं कि अहमदियों और सूफियों पर हमले हो रहे हैं। 6 अगस्त को अहमदियों की अनेक मस्जिदों पर हमले हुए।

29 अगस्त को शेरपुर जिले में बाबा पगला अली की सूफी दरगाह पर हिंसक हमला हुआ। इसी प्रकार हिंसक भीड़ ने 3 सितंबर को सिराजगंज जिले में इस्माइल पगला की दरगाह को लूट कर वहां तोड़फोड़ की। इस बीच इस्लामवादी आतंकी संगठन-अंसारुल इस्लाम व हिन्दुतहरीर लगातार सक्रिय हैं। तहरीर पर प्रतिबंध के बावजूद उसके समर्थकों ने 9 अगस्त को ढाका में रैली की तथा बांग्लादेश में इस्लामी खलीफत स्थापित करने की मांग की। इसके साथ ही जुलाई, 2026 में होली आर्टीसन बेकरी में आतंकवादियों के मुकाबले में शहीद हुए दो पुलिस अधिकारियों की मूर्तियां तोड़ डाली गई।

अंतरिम सरकार का अंसारुल इस्लाम व तहरीर के प्रति दृष्टिकोण बहुत नरम है। अंसार अल इस्लाम के मुखिया को 26 अगस्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप हिफाजत और जमात के हौसले बुलंद हैं तथा पंथनिरपेक्षता के पैरोकार शहरयार कबीर जैसे लोगों को जेल में बंद किया गया है। इसके साथ ही सांप्रदायिकता का विरोध करने वाले संगठन रक्षात्मक मुद्रा में हैं और खतरों का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बांग्लादेश धीरे-धीरे न केवल कट्टरपंथी इस्लामवादी देश, बल्कि आतंकवाद के निर्यातक देश की ओर आगे बढ़ रहा है।

परिवर्तन के साथ सामंजस्य

> जबकि परिवर्तन को अक्सर प्रगति के स्रोत के रूप में देखा जाता है, इसकी निरंतर गति कई लोगों को मानसिक रूप से थका सकती है।

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, हमें लगातार बदलते समय, बदलते विचारों और बदलते भविष्य के साथ तालमेल बिठाना होगा। आज, परिवर्तन इतना तेज हो गया है कि कुछ लोगों, विशेष रूप से पेशेवरों को उभरते रुझानों पर लगातार नजर रखनी पड़ती है और परिवर्तन के साथ तालमेल रखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। लंबे समय तक लगातार खुद को हाई गियर में रखने के परिणामस्वरूप, कई लोगों को लगता है कि तेजी बदलाव उनकी नसों को हिला देते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से इतने थकाऊ और बोझिल हो जाते हैं कि जीवन आनंद से ज्यादा एक समस्या बन जाता है। हालांकि, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हर बदलाव एक अभिशाप है।

नहीं! आम धारणा के विपरीत, परिवर्तन आम तौर पर जीवन की एक स्वागत योग्य विशेषता है, और स्थिरता को हमेशा उबाऊ माना जाता है। यह परिवर्तन की तेजी और उच्च आवृत्ति, या परिवर्तन की विशालता है, जो जिम्मेदार लोगों को आवश्यक शारीरिक और मानसिक आराम से वंचित करती है, उन्हें हमेशा चलते रहने और चिंता में रहने के लिए मजबूर करती है।

लेकिन सवाल यह उठता है कि तेज और लगातार बढ़ते बदलाव की इस स्थिति का कारण क्या है? अवलोकन और विश्लेषण हमें बताते हैं कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही है जो इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वे व्यक्तियों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दुनिया में तेजी से जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं।

वे लोगों को मशीनों की तरह चलने के लिए मजबूर करते हैं, जो दिन-प्रतिदिन तेजी से आगे बढ़ रही हैं और

डिजाइन और कार्यों में बहुत अधिक बदल रही हैं। लेकिन अगर हम समस्या की गहराई में जाएं, तो हम पाएंगे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी वास्तव में मानव जाति की सेवा में हैं; इसलिए, यह मनुष्य ही है जो तय करता है कि उसे किस तरह के गैजेट और सामान की आवश्यकता है और किस गति से - इसके विपरीत नहीं। विज्ञान का विकास मनुष्य की जरूरतों, इच्छाओं, मानसिकता, उद्देश्यों, भावनाओं, मूल्यों के सेट, विवेक और बाहरी प्रभावों पर आधारित है, जिसमें मीडिया के संपर्क और समाज की स्वीकृति, प्रशंसा या उसके कार्यों की आलोचना शामिल है। इसलिए, ये कारक प्रमुख प्रेरक शक्तियाँ हैं जो नए आविष्कारों या नए रूपों और डिजाइनों को जन्म देती हैं। ये कारक ही हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य और उपयोग किस लिए किया जाना चाहिए। ये ही नए रुझान निर्धारित करते हैं। ये ही पुराने को अस्वीकार करने और नए में बदलाव की ओर ले जाते हैं। इसलिए, परिवर्तन की तीव्रता, काफी हद तक, पुरानी व्यवस्था, मूल्यों के पुराने सेट, प्रचलित फैशन और रीति-रिवाजों और मौजूदा मानदंडों और विश्वासों की अस्वीकृति की तीव्रता पर निर्भर करती है। यह, बदले में, इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति वर्तमान वस्तुओं, सुविधाओं, सेवाओं, प्रथाओं, मानदंडों, स्थिति-प्रतीकों और सुरक्षा आवश्यकताओं से कितनी जल्दी असंतुष्ट या असंतुष्ट होता है।

यह असंतोष या असंतोष, कुछ मामलों में, उचित हो सकता है और ज्यादातर मामलों में, गलत मूल्यों और गलत दृष्टिकोणों से उत्पन्न मनुष्य की आंतरिक स्थिरता और आंतरिक खुशी की कमी के कारण हो सकता है। वर्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण हमें इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि वर्तमान स्थिति, जो हमें या तो तनाव या अवसाद या अल्पकालिक आनंद की ओर ले जा रही है, हमारे अपने उपभोक्तावादी रवैये के कारण है, जो मुख्य रूप से कामुक सुख या आराम में मनुष्य की लिप्तता को पूरा करने के लिए तैयार है।

इस कठोर रवैये और गलत जीवनशैली में बदलाव लाने के लिए, हमें आध्यात्मिक मूल्यों के माध्यम से आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाकर अपने मन को सुधारने की आवश्यकता है, या जिसे आध्यात्मिकता कहा जाता है, जो विचारों और जीवन जीने के तरीके का बदलाव है। आज, जो लोग आध्यात्मिकता के माध्यम से अपनी मानसिकता, मूल्य प्रणाली और जीवनशैली में बदलाव लाए बिना बदलाव का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं, वे वास्तव में बुद्धिमानों के संदेश से चूक गए हैं। इसलिए, यह सही समय है कि हम एक समाज के रूप में महसूस करें कि आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाकर जीवनशैली की सादगी ही वर्तमान अनिश्चित स्थिति का उपाय होगी जो हमें जोश और उत्साह के साथ तेजी से बदलाव का प्रबंधन करने में सक्षम बनाएगी।

आप की बात

विदेशों में शिक्षा

महोदय, विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ रही है, जो एक गंभीर समस्या है। यह प्रतिभा पलायन न केवल हमारे देश की प्रतिभा को खोने का कारण बनता है, बल्कि यह हमारे देश के विकास को भी प्रभावित करता है। प्रतिभा पलायन के कारणों में प्रमुख है उच्च शिक्षा में जातिगत आरक्षण, उसके बाद नौकरी में उनसे कम नंबर लाने वाले को प्राथमिकता! भारत में शिक्षा की गुणवत्ता विदेशों की तुलना में कम है। विदेशी विश्वविद्यालयों में बेहतर शिक्षा और अनुसंधान के अवसर होते हैं। वहां खर्च भी कम होता है। आरक्षण नहीं होने के कारण विदेशों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं और वेतन भी अधिक होता है। यह भारतीय छात्रों को विदेशों में पढ़ाई करने और वहीं रोजगार करने के लिए प्रेरित करता है। विदेशी देशों की वीजा नीतियाँ अक्सर भारतीय छात्रों के लिए आकर्षक होती हैं। कई देशों में छात्र वीजा पर पढ़ाई करने के बाद रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। विदेशों में पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कई छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति और अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं। प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र को एकसाथ मिलकर काम करना होगा।

- **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

ढाई साल के मंत्री

ढाई साल के मंत्री, दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत चरितार्थ करते हुए बरसों से मेहनत करके इस बार चुनाव जीतकर महाराष्ट्र की विधान सभा की शोभा बढ़ाने वाले महायुति के सदस्य केवल ढाई साल ही मंत्री बने रहेंगे. उसके बाद क्या होगा ये अभी किसी को भी नही मालूम. पर तय है कि वे ढाई साल तक अपने पद पर रहेंगे. ऐसा संकेत ही नहीं बल्कि साफ़-साफ़ कह दिया है एनसीपी (अजीत) के प्रमुख व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने मंत्रिमंडल गठन से पूर्व ही. शीने के ढैय्या सरीखा चलने वाला मंत्रिमंडल ढाई साल बाद फिर ढाई साल के लिए कैसा होगा ये तो पता नहीं किन्तु भारी फेरबदल भी हो सकता है. मुख्यमंत्री और दोनों उपमुख्यमंत्रियों मसलन (भाजपा (फडणवीस), एनसीपी(अजीत), शिवसेना (शिंदे) के बीच कुछ तो राज़ रहा होगा तभी ढाई साल का यक्ष प्रश्न उत्पन्न हुआ है. खैर जो भी हो ये उनकी अपनी राय, पार्टी व सरकार के बीच तैयार गाईडलाईन होगी तभी ढाई साल में कोई बड़े परिवर्तन के संकेत पहले से ही महाराष्ट्र की जनता के सामने ही नहीं बल्कि राष्ट्र के सामने भी आ गए हैं. वैसे ये ढाई साल वाला फार्मूला पूरा राष्ट्र 1977 की जनता पार्टी में भी देख चुका है जहां सरकार में शामिल अनेक घटकों में पूरे ढाई साल खींचतान बनी रही थी। वैसे वो बात अलग थी जिसमें अनेक घटक दल सरकार में थे।

- **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

अंगदान का महत्व

विगत वर्षों से देश दुनियां में अंगदान का चलन अग्रसर हो रहा है। और हमारे देश प्रदेश में भी अंगदान के लिए लोगों में जागरूकता और इसके महत्व की झलक कहीं न कहीं देखने को मिल जाती हैं। दान शब्द ही अपने आप में मानव जीवन को पुण्य लाभ और ईश्वर के सानिध्य का आभास कराता है। और यह पुण्य लाभ , पुण्य कार्य सेवाभाव जन जन तक स्थान बना रहा। अक्सर दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति दम तोड़ देते हैं , या फिर कोई दानदाता जीवित अवस्था में अंगदान के नेक कार्य से प्रेरित होकर अपना देहदान , नेत्र दान , लीवर और अन्य अंगों के दान की घोषणा करता है। फिर परिजन संबंधित व्यक्ति की भावनाओ को सार्थक रुप देते हैं। सुझाव के तौर पर अंगदानी के परिजनों को मंचो पर सुसौभित और सम्मानित करना चाहिए। अंगदानी के परिजन या नामिनी व्यक्ति किसी को भी सरकारी नौकरी या सकारात्मक सोच रखकर सहयोग करना चाहिए। पीड़ित और दुखी परिवार और परिजनों का मनोबल मजबूत बनाने के लिए समाज और कल्याण कारी योजनाओं का लाभ , इत्यादि मिलना चाहिए। क्योंकि इसने कोई दो राय नहीं अंगदान देना दिल वालो का ही काम होता है। और सेवाभाव का संकल्प और जब्बे जुनून वालो का ही काम होता है। इस तरह की कारगर पहल से समाज में नई जन जागृति आएगी।

- **योगेश जोशी**, बड़वाह

कब तक बंटेगी रेवड़ी?

देश 2 सालों से चुनाव का सामना कर रहा है। 2023 में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव के बाद 2024 लोकसभा के नाम रहा। पिछले महीने महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए हैं। आने वाले समय में दिल्ली में चुनावी महासमर होगा। इसके लिए राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अभी से दांव खेलना शुरू कर दिए हैं। आप ने महिलाओं के लिए नगदी योजना का ऐलान किया है सत्ता की होड़ में भाजपा के साथ ही कांग्रेस भी लगी हुई है। ऐसे में आगे क्या परिदृश्य नजर आएगा सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सब जानते है कि रेवड़ी सरेआम मतों की खरीद फरोख्त है और माननीय न्यायालय ने भी इसको लेकर नाराज़गी जाहिर की थी।ऐसे में राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग ही रोक सकता है। एक आदर्श चुनावी आचार संहिता बनाई जाए जो समान रूप से सभी दलों पर राज लागू हो। इसमें मतदाताओं को लालच, आश्वासन और सुविधा देने की मंशा चुनावी अपराध हो और जिसका उन्हें उचित दंड मिले। आयोग की सख्ती ही रेवड़ी बांटने की संस्कृति के विस्तार को रोक सकती है।

- **अमृतलाल मारू**, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

प्रतीकों के माध्यम से मनुष्य हमेशा उन विचारों को संप्रेषित करते रहे हैं, जो भाषा की सीमाओं से परे हैं। -मैनली हॉल

एसबीआई की शोध रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में फल-सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी बेशक एक उपलब्धि है, पर इनका एक बड़ा हिस्सा गलत रख-रखाव के चलते नष्ट हो जाता है। लिहाजा, खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है।

उपलब्धि और चुनौती

भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट का यह कहना कि पिछले एक दशक में देश में फलों व सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, कृषि क्षेत्र में आई प्रगति को तो रेखांकित करता ही है, वह खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य व पोषण के लिहाज से भी एक बड़ी उपलब्धि है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले दस वर्षों में देश में फलों व सब्जियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता क्रमशः सात और बारह किलोग्राम बढ़ी है, तो इसका श्रेय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और जम्मू-कश्मीर को मिलना चाहिए, जिनके योगदान से ही आज देश प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 227 किलोग्राम फल व सब्जियों का उत्पादन कर रहा है, जो प्रति व्यक्ति 146 किलोग्राम की अनुशंसित खपत से काफी अधिक है। दरअसल, आज का भारत परंपरागत कृषि से आगे बढ़कर नवाचार और तकनीकी उपायों को अपनाने में सफल हो रहा है। किसानों द्वारा ड्रिप सिंचाई, उच्च उपज वाली फसलों को प्राथमिकता देना और स्मार्ट खेती जैसी विधियों को अपनाना इसके मुख्य कारण हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि अवसंरचना कोष और किसान उत्पादक संगठन जैसी पहलों ने किसानों को बेहतर संसाधन तो दिए ही हैं, उनकी बाजारों तक पहुंच भी सुनिश्चित की है। लोगों में स्वास्थ्य व पोषण को लेकर बढ़ती जागरूकता ने भी फलों व सब्जियों की मांग को प्रोत्साहित किया है। लोगों के आहार पैटर्न में यह जो बदलाव दिख रहा है, वह कोरोना महामारी के दौर से ही दिखना शुरू हो गया था। हालांकि रिपोर्ट में असामान्य होती मौसम की स्थितियों से होने वाले नुकसानों पर भी प्रकाश डाला गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अनुसार, अनाज के उत्पादन के वक्त में तापमान में तीस डिग्री सेल्सियस से एक डिग्री भी ज्यादा वृद्धि होने पर गेहूं की पैदावार में तीन से चार फीसदी की कमी आ सकती है, जो बेहद चिंताजनक है। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक तथ्य यह है कि 30 से 35 फीसदी फसल

कटाई, भंडारण, परिवहन व पैकेजिंग के गलत तौर-तरीकों के चलते नष्ट हो जाती है। देश के 60 फीसदी कोल्ड स्टोरेज केवल चार राज्यों- गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में हैं। भारत फिलहाल फल व सब्जियों के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर अब आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ने का समय है। फल-सब्जियों की उपलब्धता बढ़ना सकारात्मक संकेत है, लेकिन खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है।

खाजा अहमद अब्बास-शैलेंद्र की समाजवादी चेतना और शंकर-जयकिशन के संगीत से फिल्मों में व्यावसायिक सफलता के प्रतीकों का सृजन अपने समय की बड़ी परिघटना थी।

जयप्रकाश चौकसे

आधी हकीकत आधा फसाना

राजकपूर की सृजन प्रक्रिया अजीब थी! उनके मन में ध्वनियों का जन्म पहले होता था और दृश्य संरचना बाद में। मन में उभरे टोनल पैटर्न का विजुअल अनुवाद उनकी तकनीक की आत्मा थी। एक तरह से फिल्म राजकपूर के लिए 'ओपेरा' की तरह थी। संगीत 'मोटिफ' की तरह पूरी चित्र का निर्माण होता था। मैंने कई बार देखा है कि दृश्यांकन के समय वे किसी पात्र के चलने जैसे साधारण क्रिया के समय 'बीट' गिनते रहते थे- उस ध्वनि की, जो उनके मन में गूंजती थी। ध्वनियों से प्रेरित दृश्य विधान के साथ ही राजकपूर संवाद का बिंब रूपांतर भी करते रहे हैं। *मेरा नाम जोकर* में अब्बास साहब ने मनुष्य की असहायता और सीमाओं पर एक संवाद लिखा था। इस विचार को राजकपूर ने अनोखे बिंब विधान द्वारा प्रस्तुत किया। नायक जोकर के पुतले पर जमे हुए जाले साफ करता है और उसे जमीन पर रखता है। चाबी भरे हुए खिलौने के मानिंद वह पुतला थिरकता है। पृष्ठभूमि में काले पत्थर की दीवारों पर मकड़ी का जाल बिछा हुआ है। समय की पृष्ठभूमि पर मनुष्य की लाचारी का मार्मिक चित्रण हुआ है। पुतला बदलकर नायक हो जाता है, जिसके फैले हुए हाथों के बीच से गुजरती हैं नायिकाओं की छवियां। राजकपूर को प्रतीकों का बहुत मोह था। वे पात्रों के नाम भी उनके स्वभाव के परिचायक के रूप में रखते थे। *श्री 420* में नर्गिस विद्या है, तो नादिरा माया और कहीं इस प्रतीक को लोग भूल नहीं जाएं या नजरअंदाज नहीं कर जाएं- इसीलिए सेठ सोनाचंद धर्मानंद भोलेराज को अपने गिरोह में लेने के बाद कहते हैं कि 'अब तुम्हें विद्या की नहीं, माया की जरूरत है।' जोकर के तीसरे भाग में स्वाथी नायिका *ट्राम* पत्रिका पढ़ती है, अमीर निर्माता *फॉर्चून* पढ़ रहा है, तो तमाशे की जान-जोकर *लाइफ* पढ़ रहा है।

राजकपूर/जन्मशती

एक नकली अंधा, जब गंगा को बेच देता है, तो गंगा का संवाद है-'अंधे बनकर ऐसा काम करोगे, तो लोग अंधों की मदद नहीं करेंगे।' इसी तरह कहावतों का प्रयोग दृश्यों और गीतों में करने की प्रेरणा उन्हें स्वर्गीय शैलेंद्र ने दी। राजकपूर दसवीं फेल थे, परंतु उनकी असली पाठशाला तो जिंदगी थी। उनकी सारी फिल्मों की प्रेरणा उन्हें जीवन के अपने अनुभवों से मिली। प्रथम प्रदर्शन में 'जोकर' के असफल होने का एक कारण यह भी था कि वह राजकपूर की आत्म-कथा न होकर, राजकपूर अभिनेता की 'होबो' छवि की कथा थी।

राजकपूर की फिल्मों के कथानक सामाजिक यथार्थ की भूमि में जन्म लेते थे, परंतु उनका ऊपरी स्वरूप फंतासी की तरह दिखता था। जीवन के दुःख से भागकर आए हुए दर्शक फंतासी के नयनाभिराम स्वरूप में मनोरंजन पाते और प्रबुद्ध दर्शक सामाजिक संदर्भ और पात्रों की मानवीयता से अभिभूत हो जाते। राजकपूर की जिन फिल्मों में फंतासी और सामाजिकता का संतुलन बिगड़ा, उन्हें जनता ने अस्वीकृत कर दिया जैसे *आह, जागते रहो* और *जोकर*। फंतासी और पात्र के अंतर्द्वंद्व के सामंजस्य का श्रेष्ठ उदाहरण है *आवारा* का स्वप्न दृश्य। राजकपूर का फिल्म दर्शन ही नहीं, वरन पूरा जीवन है आधी हकीकत, आधा फसाना। राजकपूर पर अब्बास और अन्य कम्युनिस्ट लेखकों का प्रभाव रहा, तो उनकी मनपसंद किताब एन रेंड की *फाउंटेन हेड* भी रही है। उन्होंने जिस कुशलता के साथ बीची की हकीकत के साथ प्रेयसी का फसाना मिलाया था- उसी विमुग्धता से अपनी फिल्मों में फंतासी और यथार्थ को भी मिलाया था। आज भी यकीन नहीं होता कि वह आदमी था या छलावा।

(नब्बे के दशक में श्रीराम तिवारी संपादित 'पटकथा' में प्रकाशित राजकपूर-प्रेमी फिल्म आलोचक स्व. जयप्रकाश चौकसे के आलेख के अंश)

बांग्लादेश को रोशनी की जरूरत है

जब पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश के पूर्वी हिस्से पर बर्बर हमले शुरू किए, तो वह भारत ही था, जिसने बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई। लेकिन आज बांग्लादेश में मौजूद कुछ तत्व मुक्ति युद्ध की यादों को मिटाने पर आमादा हैं। जो राष्ट्र अपने अतीत की रोशनी का सम्मान नहीं करते, वे मिट जाते हैं।

जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं, तो मुझे बांग्लादेश की धरती पर खड़े होने का रोमांच हो रहा है, जब 16 दिसंबर, 2023 को उसकी राजधानी ढाका में उसकी मुक्ति और विजय दिवस पर उत्सव मनाया जा रहा था। बांग्लादेश को क्रूर पाकिस्तानी शासन से मुक्ति दिलाने के अभियान में भारत के राष्ट्रीय प्रयासों का मैं भी एक छोटा-सा हिस्सा था।

लेकिन बीते पांच अगस्त को जब प्रधानमंत्री शेख हसीना वहां से भारत चली आईं, यह उत्साह खत्म होता नजर आ रहा है। पूरा बांग्लादेश इन दिनों व्यापक अशांति की चपेट में है। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें आई और सबसे दुखद बात कि बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान तक को नहीं बख्शा गया, जिन्हें बंगबंधु के नाम से भी जाना जाता है। उनकी प्रतिमा को तोड़ दिया गया है और उनके घर को भी जला दिया गया। मुक्ति युद्ध के दौरान उन्होंने जो *जॉय बांग्ला* का नारा गढ़ा था, उसे तथाकथित न्यायिक प्रक्रिया द्वारा रद्द किया जा रहा है। लग रहा है कि बांग्लादेश के समाज में ऐसे तत्व हैं, जो लोगों के मन से उनकी और मुक्ति युद्ध की यादों को मिटाना चाहते हैं। ये लोग जान-बूझकर मूर्तिभंजन का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि जो देश महान ऊंचाइयों पर पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं, उन्हें अपनी स्मृति और इतिहास में प्रतीक चिह्नों की जरूरत होती है। प्रेरणा लेने के लिए कई उदाहरण हैं। महात्मा गांधी की छवि को नष्ट करने के अनेक प्रयासों के बावजूद वे भारतीय लोगों के दिलों में आज भी जीवित हैं। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद का पोषण होता है। तमाम उथल-पथल के बावजूद अमेरिकी लोगों ने अपने इतिहास से जॉर्ज वाशिंगटन को नहीं हटाया और न ही तुर्किये में कमाल अतातुर्क, रूस में लेनिन और इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल को भुलाया गया।

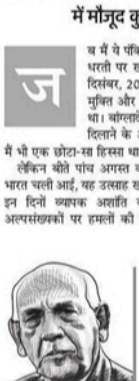

प्रशांत दीक्षित

बांग्लादेश के नेता के रूप में मुजीबुर रहमान ने अप्रैल 1971 से

अगस्त 1975 में अपनी हत्या तक लगातार बांग्लादेश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था। लेकिन उन्होंने ब्रिटिश राज और पाकिस्तानी शासन के दौरान 13 साल जेल में भी काटे। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की। बंगाली राष्ट्रवादियों ने उन्हें बांग्लादेश की प्रोविजनल सरकार का प्रमुख घोषित किया, जबकि वह पश्चिमी पाकिस्तान की एक जेल में बंद थे। बाद के वर्षों में, उन्होंने बांग्लादेश के पुनर्निर्माण, धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाने, पाकिस्तानी शासन के युग के तंत्र, नौकरशाही, सशस्त्र बलों और न्यायपालिका को बदलकर एक स्वतंत्र मुल्क के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हम यह नहीं भूल सकते कि 25 मार्च, 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश के पूर्वी हिस्से (अब बांग्लादेश) के नागरिकों पर लगातार बर्बर हमले शुरू कर दिए थे। अकेले ढाका में ही हजारों लोगों को गोली मार दी गई, कई लोगों को बम से उड़ा दिया गया, तो कई को जिंदा जलाकर मार दिया गया। जुलाई 1971 तक, इस नरसंहार से भागकर पैंसठ लाख शरणार्थी पड़ोसी देश भारत पहुंच चुके थे। उनमें से पचास लाख से ज्यादा पश्चिम बंगाल में शरण लिए हुए थे। भारत के लगभग 600 शिविरों में से 400 से ज्यादा शरणार्थी शिविर पश्चिम बंगाल में ही थे। मानवीय क्रूरता के काले इतिहास में पूर्वी पाकिस्तान में हुई हत्याएं शायद बोस्निया से भी ज्यादा खूनी थीं और रवांडा जैसी ही वीभत्स मानी जाती हैं। जाहिर है, एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत इस नरसंहार को और अधिक अनदेखा नहीं कर सकता था। विशुद्ध मानवीय कारणों से भारत को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। आर्थिक बोझ के चंगुल से खुद को बचाना भी भारत के लिए बेहद जरूरी था। भारत सरकार के सामने खड़ी इस भीषण मानवीय आपदा के लिए सैन्य अभियान ही एकमात्र संभव समाधान था।

इतिहास गवाह है कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ (बाद में फील्ड मार्शल) के साथ बैठक की थी और उसके बाद सैन्य योजनाकारों ने अपनी योजना तैयार की थी। जब याह्या खान का शासन पूर्वी पाकिस्तान में अपने ही लोगों को कुचल रहा था, तब वह वाशिंगटन और बीजिंग के बीच संदेशों का आदान-प्रदान कर रहा था। इन बैठकों के दौरान किसिंजर ने चीनी प्रधानमंत्री चाउ-एन-लाई से पाकिस्तान की रक्षा के लिए भारत को धमकाने की खातिर गुप्त रूप से सेना जुटाने के लिए कहा था। और यह भारतीय सैनिकों के पूर्वी पाकिस्तान में सक्रिय रूप से घुसने से बहुत पहले की बात है। यह निक्सन का अमेरिका था, जो मानता था कि भारत सोवियत रूस का रणनीतिक सहयोगी है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारतीय सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने इसे पहले ही भांप लिया था और अपने कमांडरों को ऐसी स्थिति के लिए तैयार कर लिया था।

पाकिस्तान ने तीन दिसंबर, 1971 को ही पश्चिम भारत में भारतीय सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले शुरू कर दिए और भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध 16 दिसंबर, 1971 तक चला, जब पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के समक्ष अपने हथियार डाल कर आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार भारत की मदद से एक कठिन मुक्ति संघर्ष के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया। लेकिन 2001 में ही भारत को पता चला कि इस मुक्ति युद्ध में 3,843 भारतीय रक्षाकर्मी मारे गए और 9,851 घायल हुए। ये स्वतंत्र भारत द्वारा लड़े गए सभी युद्धों में सबसे बड़ी संख्या थी।

कहा जाता है कि सुरंग के अंत में रोशनी है। बांग्लादेश में चल रही मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता और अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों के बीच मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार ने पुष्टि की है कि मुक्ति वाहिनी के दिगज 16 दिसंबर, 2024 को भारत के विजय दिवस समारोह में भाग लेंगे। यह कदम बांग्लादेश की मुक्ति में भाग लेने वाले युद्ध के दिग्गजों के दिलों में व्याप्त पीड़ा को काफी हद तक कम करेगा। आज बांग्लादेश को विकास की पटरी पर वापस लाने की जरूरत है और उसे गहरी धार्मिक कट्टरता से बचाने की जरूरत है।

-लेखक को मुक्ति युद्ध में भागीदारी के लिए वीरता पुरस्कार मिला है।

edit@amarujala.com

दूसरा पहलू

मधुबनी से करीब 30 किलोमीटर दूर राजनगर में बना नौलखा पैलेस आज खंडहर बन गया है, जिसे जीर्णोद्धार की जरूरत है।

अब नौलखा पैलेस का खंडहर ही बचा है

कभी बेहद शानदार और भव्य रहीं इन राजसी अट्टालिकाओं के खंडहर देखकर यही लगता है कि कभी यहां की रौनक राजधानियों को भी मात देती होगी। मधुबनी से लगभग 30 किलोमीटर दूर राजनगर में बना नौलखा पैलेस आज भले ही खंडहर हो, पर इसके विशाल परिसर में महल, मंदिर, अदालत सब कुछ है, कहीं पत्थर के विशाल हाथी स्थापत करते मिलेंगे, तो कहीं सात मंजिला मीनार। इसे बने कुछ ही समय हुआ था कि नेपाल, बिहार और बंगाल में 1934 में भीषण भूकंप आया, जिसने मजबूत इमारतों को भी जमींदोज कर दिया। इस नायाब विरासत को ऐसा नुकसान पहुंचा, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकी। बताते हैं कि यह चांदी के नौ लाख सिक्कों से बना था, इसलिए इसका नाम नौलखा पैलेस है।

भूपेंद्र कुमार

पैलेस में घुसते ही सात मंजिला मीनार दिखती है। दुर्गा भवन इसके बगल में है। परिसर में सफेद संगमरमर से बना काली मंदिर है, तो एक इमारत के पेंटिंगों में पत्थर के दो हाथियों पर टिकी चार मेहराबें हैं। भवन की छत ढह चुकी है, लेकिन खंभों की बनावट ऐसी है कि हैरी पॉटर फिल्मों के दृश्य याद आ जाते हैं। परिसर से बाहर के मंदिर की दीवारें दरक गई हैं, गर्भगृह खाली है, और विशाल घंटा जमीन पर पड़ा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पास की इमारत में मूर्तियां रख दी गई हैं। वर्ष 1920 के आसपास इसका निर्माण दरभंगा एस्टेट की प्रशासनिक राजधानी के तौर पर कराया गया था। 1,500 एकड़ में फैले इस परिसर में कभी 11 मंदिर थे। महाराज रामेश्वर सिंह ने इसे बनवाया, पर यहां कभी रहे नहीं। अपने बड़े भाई के निधन के बाद उन्हें दरभंगा जाकर शासन संभालना पड़ा। और यह राजधानी बसने से पहले ही उजड़ गई। परिसर में संगमरमर की खास बना देती है। बताते हैं कि महल के एक कमरे में सबसे पुरानी ज्ञात मधुबनी पेंटिंग भी है, जो 1919 में राजपरिवार की शादी के लिए बनी थी। पैलेस के एक हिस्से में संग्रहालय है, जो अक्सर बंद रहता है। महाराज रामेश्वर सिंह ने इन इमारतों को डिजाइन करने के लिए फ्रांसीसी वास्तुकार कुलाए थे। इसलिए इन पर फ्रेंच और यूरोपीय वास्तुकला का असर दिखता है। अब यहां जगह-जगह कचरे के ढेर हैं, चारदीवारी टूट चुकी है, इमारतों में झाड़-झंखाड़ उग आए हैं। ...गौरवशाली अतीत के गवाह रहे नौलखा पैलेस को जीर्णोद्धार की दरकार है।

इसे बने कुछ ही समय हुआ था कि नेपाल, बिहार और बंगाल में 1934 में भीषण भूकंप आया, जिसने इन इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया।

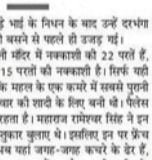

परिसर में बने काली मंदिर में नक्काशी की 22 परतें हैं, जबकि आगरा के विश्व विख्यात ताजमहल में 15 परतों की नक्काशी है। सिर्फ यही बात इस पैलेस को खास बना देती है।

आंकड़े

विदेशी जेलों में मछुआरे

हमारे देश के बहुत से मछुआरे दुनिया के विभिन्न देशों की जेलों में बंद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बंद हैं।

पाकिस्तान	211
श्रीलंका	141
बांग्लादेश	95
बहरीन	37
सऊदी अरब	25

आंकड़े एक जुलाई, 2024 तक के | स्रोत : विदेश मंत्रालय

योगमाया के भीतर तीनों गुण हैं-सत्व, रज और तम। परंतु राधिका के भीतर शुद्ध सत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। राधिका कृष्ण का ही अंश थीं।

राधा का कृष्ण-प्रेम

एक बार रामकृष्ण परमहंस 'भागवत' के विद्वान पंडित के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। अन्य भक्तगण भी समीप ही बैठे थे।

श्रीरामकृष्ण परमहंस ने पंडित जी से पूछा, योगमाया क्या है? पंडित जी ने योगमाया की अपनी तरह से व्याख्या की। फिर रामकृष्ण ने पूछा, क्या राधिका योगमाया थीं? पंडित जी इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके।

तब रामकृष्ण ने ही बताया, योगमाया के भीतर तीनों गुण हैं-सत्व, रज और तम। परंतु राधिका के भीतर शुद्ध सत्व के सिवा कुछ है ही नहीं। राधिका कृष्ण का ही अंश थीं। कृष्ण ने प्रेम का रसास्वादन करने के लिए ही राधिका की सृष्टि की थी।

उन्होंने राधा-कृष्ण के जन्म के समय का एक दृष्टांत सुनाया, वैष्णव ग्रंथों में लिखा है कि राधा ने जन्म लेने के बाद भी अपनी आंखें नहीं खोली थीं। भाव यह था कि इन आंखों से कृष्ण के सिवा और किसे देखूं! फिर जब यशोदा मैया राधिका के जन्म की बधाई देने नन्दे कृष्ण को लेकर राधा के घर आईं, तब कृष्ण को देखने के लिए राधा ने अपनी आंखें खोल दीं और कृष्ण ने खेल के बहाने राधिका की आंखों पर हाथ फेर दिया।

अंतर्यात्रा
संकलित

रामकृष्ण परमहंस ने आगे कहा, आप लोगों ने देखा होगा कि इसलिए छोटा बच्चा दूसरों की आंखों पर हाथ फेरता है।

पंडित जी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, कृष्ण आधार हैं, तो राधा स्वयं आधेय हैं।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 02 अप्रैल, 1950

नजरबंदी कानून को सर्वोच्च अदालत में चुनौती

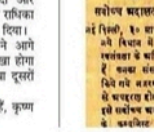

नजरबन्दी कानून को चुनौती

सर्वोच्च अदालत में दुकार

नई दिल्ली, 15 मार्च : भारत के संविधान में जो नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार दिये गये हैं उनका संरक्षण इस्तेमाल किये गये नजरबंदी के कानून से रुकावट होता है या नहीं, इसी सवाल पर बहादत में महान के कार्यवाहक न्यायमूर्ति श्री

सर्वोच्च अदालत में मद्रास (अब चेन्नई) के कम्युनिस्ट नेता गोपालन की ओर से नजरबंदी कानून को चुनौती दी गई है। अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान कई संसद सदस्य और वकील उपस्थित थे।

मिटता जा रहा है ग्राम सभाओं का वजूद

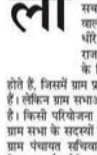

अनेक बार कागजी खानापूरी कर और फर्जी कार्यों का निष्पादन दिखाकर भुगतान होते रहते हैं, जिनकी कानो-कान किसी को खबर नहीं होती।

सुधीर विद्यार्थी

मुद्दा

लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्राथमिक और सबसे बुनियादी इकाई कही जाने वाली ग्राम सभाओं का अस्तित्व धीरे-धीरे खतरे तोता जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के इस प्राथमिक निकाय के लिए पांच वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं, जिसमें ग्राम प्रधान और उसके सदस्य चुने जाते हैं। लेकिन ग्राम सभाओं का दांचा पूरी तरह चरमरा गया है। किसी परियोजना अथवा गांव के विकास के लिए ग्राम सभा के सदस्यों की कोई बैठक नहीं बुलाई जाती। ग्राम पंचायत सचिवालयों/भवनों का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन उनके दरवाजे खुलते नहीं, न ही वहां ग्राम विकास अथवा ग्रामवासियों की किसी समस्या पर विमर्श संभव है। कई ग्राम सभाओं में निर्मित ऐसी इमारतों का ग्राम प्रधान की मनमर्जी से दुरुपयोग हो रहा है। वे ताश और जुआ खेलने के अड्डों अथवा मिठलंबों की बैठक के केंद्रों में तब्दील हो चुके हैं।

ग्राम सभाओं का कार्य गांव के विकास और उसके वाशिंदों के कल्याण के साथ उनकी सुविधाओं को

बढ़ाना और समस्याओं को हल करना है। उनका यह भी दायित्व है कि वे गांव के लोगों के आपसी विवादों का निपटारा सुलह-समझौते के आधार पर करें, जिससे ऐसे मामले पुलिस और अदालतों तक न पहुंचें और गांव का वातावरण सुखद बना रहे। लेकिन गांवों में आपसी विवाद इस कदर बढ़ गए हैं, जिनका समाधान न तो तहसील के राजस्व अनुभाग से संभव है और न ही कोई पुलिस या न्यायालय उनका निपटारा कराने में सक्षम हैं। ग्राम सभाएं नितांत निष्क्रिय और अकर्मण्य हो चुकी हैं।

ग्राम सभाओं पर उन सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी निगरानी की भी जिम्मेदारी है, जिन्हें ग्रामवासियों की उन्नति के लिए बनाया गया है। ग्राम सभा का प्राथमिक प्रबंध ग्राम प्रधान और सरकारी सेवक कहे जाने वाले सचिव के नियंत्रण में होता है। यही कारण है कि ग्राम सभाओं की उन्नति और विकास के लिए आवंटित होने वाली सरकारी धनराशि को खर्च करने में ये दोनों संलग्न रहते हैं। अनेक बार कागजी खानापूरी कर और फर्जी कार्यों का निष्पादन दिखाकर भुगतान होते रहते हैं, जिनकी कानो-कान किसी को खबर नहीं होती।

ग्राम सभा में बड़ी लागत से बना सामुदायिक शौचालय का संचालन ऐसे सुविधासंपन्न व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, जिसे बिना कुछ किए-धरे छह हजार रुपये मासिक मानदेय की प्राप्ति होती है। ये शौचालय कभी-कभार या कम समय के लिए खुलते हैं। अधिकांश शौचालय टूटे पड़े हैं, उनमें पानी और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इनके संचालन और मरम्मत के लिए प्रति माह प्राप्त होने वाली तीन हजार रुपये की धनराशि प्रायः ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और संचालक मिल-जुलकर डकार जाते हैं। यदि इन सामुदायिक शौचालयों को संचालिका कोई महिला हुई, तो उसका पति या परिवार का कोई पुरुष सदस्य ही फर्जी हस्ताक्षरों से बैंक के खातों का भी संचालन करता है, जो पूर्णतया बैंक अधिकारियों के संज्ञान में भी रहता है। गांव के अधिकतर चकरोड और सड़कें टूटी पड़ी रहती हैं, पर ग्राम प्रधान इन सबसे विमुख होकर अपनी संपत्ति के विस्तार में संलग्न रहते हैं। किसी भी प्रधान और पूर्व प्रधानों की धन-संपदा और उनके द्वारा खड़े आलीशान घरों तथा उनके द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि अथवा कस्बों-शहरों में प्लाटों और बनाए गए मकानों की जांच कर ली जाए, तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सभी ग्राम प्रधान क्षेत्रीय विधायक से साठ-गांठ रखते हैं।

ग्राम सभाएं दलीय राजनीति में फंस चुकी हैं और सत्ताधारी दल से जुड़कर ये अपना हित साधती हैं। डेढ़-दो दशक पहले ग्राम सभाओं की स्वतंत्र सत्ता होती थी। अब तो विधायक और सांसद भी इन ग्राम सभाओं से अपना हित साधने में लगे रहते हैं। उनका ध्यान गांव के विकास और उनकी समस्याओं की सुलझान नहीं है। पांच किलो मुफ्त राशन के चलते अधिकांश आबादी ने श्रम से मुंह मोड़ लिया है। अब गांव में कृषि कार्य के लिए मजदूर नहीं मिलते। लंबे समय से चल रही मनरेगा योजना में ग्राम प्रधान की मर्जी के मुताबिक बार-बार चकरोडों पर मिट्टी डालने जैसे गैरजरूरी कार्य रोजगार सेवक से मिलकर संपादित किए जा रहे हैं। सच यह है कि इसमें कम समय के लिए उपस्थित अथवा पूरे समय के लिए फर्जी हाजिरी भरने वाले कामगारों का भुगतान भी हो रहा है। परंपरागत और पूरे समय जलमग्न रहने वाले तालाब खत्म किए जा रहे हैं, जबकि नए तालाब खोद कर ऐसी योजनाओं का पैसा हड़पा जा रहा है।

अब गांव का कोई 'मुखिया' नहीं रहा, जिसका ध्यान गांव के कल्याणार्थ हो, और जिसकी बात का वजन हो। ऐसे में गांव-समाज का ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। एक समय गांव एक सशक्त इकाई थे। उनका अपना प्रबंधन और पंचायती न्याय व्यवस्था भी थी, जो पूरे समाज और उसके हितों को जोड़-संभाल कर रखती थी। अब 'ग्राम सभाएं' सिर्फ नाम भर की हैं।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 16 दिसंबर 2024

नेहरू-सावरकर क्यों?

लोकसभा में संविधान को लेकर हुई दो दिनों की बहस न केवल समकालीन राजनीतिक मुद्दों पर बल्कि लोकतंत्र, समाज और इतिहास से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलग-अलग नजरियों को स्पष्ट कर गई।

आरक्षण पर आमने-सामने | इस बहस का भी एक बड़ा बिंदु आरक्षण ही रहा। जहां विपक्ष ने इन आरोपों को दोहराया कि सत्ता पक्ष मूल रूप से आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है और जब-तब दबे-छुपे ढंग से उसकी यह अंदरूनी इच्छा संघ और पार्टी के छोटे-बड़े नेताओं के बयानों से जाहिर होती रहती है। जवाब में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि आरक्षण की जो व्यवस्था अभी लागू है, उनकी सरकार उस पर आंच नहीं आने देगी, लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोई भी कोशिश वह सफल नहीं होने देगी। जाहिर है, इसमें मतदाताओं की अपने अनुकूल गोलबंदी करने की दोनों पक्षों की कोशिश भी आसानी से देखी और पहचानी जा सकती है।

लोकसभा में संविधान पर बहस

तानाशाही का आरोप | तानाशाही एक और ऐसे बिंदु के रूप में उभरी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप समान ही रहे। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाया कि वह अपनी मनमानी चलाते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाता रहा है। इस मामले में जहां कांग्रेस का फोकस पिछले दस सालों पर केंद्रित रहा, वहीं BJP का पॉइंट यह था कि आजादी के बाद से 55 साल तक सत्ता एक ही परिवार के हाथों में रही। जाहिर है, सबसे ज्यादा नुकसान इसी परिवार ने किया। उनका संकेत गांधी परिवार की ओर था।

संविधान की रक्षा | बहरहाल, बहस का केंद्र यही सवाल रहा कि कौन संविधान और संवैधानिक मूल्यों को लेकर समर्पित है और कौन इस पर दोहरा खेल खेल रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जहां सावरकर के सहारे BJP पर निशाना साधा वहीं पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की गलतियां गिनाईं।

महापुरुषों को बख्शो | पूरी बहस का यही बिंदु ऐसा था जो थोड़ा जायका बिगाड़ने वाला कहा जा सकता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की तू-तू मैं-मैं चलती रहती है, लेकिन इसमें महापुरुषों को घसीटना अब बंद होना चाहिए। हमारे हर महापुरुष ने अपने समय, समाज और समझ की सीमाओं में रहते हुए कुछ ऐसा योगदान किया, जिसके लिए हम कृतज्ञ महसूस करते हैं। इसका मतलब उनके हर विचार से सहमति रखना या उनके हर कृत्य को समर्थन देना नहीं है। लेकिन उनके प्रति समाज की या उसके एक हिस्से की भी भावनाओं का सम्मान हमारी राजनीति को बिना शर्त करना चाहिए।

चक्र-व्यू

चिपचिप करता भात

राहुल पाण्डेय

इधर होटलों या रेस्तरां से लेकर सोशल मीडिया की रील्स में दिख रहा है कि चिपचिपे भात का फैशन बढ़ रहा है। कुछेक जगहों पर तो ऐसा लगता है कि माढ़ का लोदा ही थाली में रख दिया हो। अवध की ओर अगर घर में ऐसा चावल बनता है तो क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि पता नहीं कैसे पानी ज्यादा हो गया! नए चावल को सावधानी से पकाते हैं, क्योंकि वह पानी बहुत छोड़ता है। एक अच्छा रसोइया वही है, जो नए चावल को भी पुलाव की तरह भुरभुरा पका दे। नवाबों ने हमें जो सबसे बड़ी चीजें दी, उनमें से एक भात पकाने का सलीका भी है। कोलकाता वाले जो अपनी बिरयानी का दम भरते हैं, वह भी इसी नवाबी के चलते ही है। दुनिया में कहीं चिपचिपे भात की बिरयानी होती भी है, तो उसे बिरयानी नहीं कह सकते। बिरयानी तो बहुत दूर की बात है, चिपचिपे चावल को तो ठीक से दाल के साथ भी नहीं सान सकते। दाल अलग बची जाती है, भात अलग। और सबसे बड़ी बात कि खाते वक्त हाथ में यह चिपकता बहुत है, तो खाने वाले को भी बड़ा अजीब लगता है। लेकिन फैशन तो फैशन है। अब आ रहा है तो कभी-कभार झेलना ही पड़ जा रहा है।

चिपचिपा भात, यानी स्टिकी राइस पूरब का फैशन है। बल्कि धुर पूरब का है, क्योंकि पूरब में तो अवध भी आ ही जाता है, कोलकाता भी। जापान में जमकर चिपचिपा भात चलता है। वहां इसे और चिपचिपा बनाने के लिए रात भर पानी में भिगोकर रखा जाता है। अपने यहां जैसे दो सीटी में चावल पक जाता है, वे इसे पौन घंटे तक पकाते रहते हैं। थाईलैंड में इसे थाओ निपाई कहते हैं। यह थाप के साथ पकता है और इसमें आम या नारियल भी मिलाया जाता है। वहां से अपने यहां के पूर्वोत्तर की ओर आएं तो यहां अक्सर चिपचिपा भात ही मिलता है। बिहार में राजगीर के एक रोड साइड ढाबे पर जो भात मिला, भले ही वह मोटे चावल का बना था, लेकिन एक-एक दाना अलग था। वहीं, असम में नलबाड़ी से नौगांव तक जितने भी ढाबों में गया, ऐसा नहीं कि ढाबे वालों ने चावल भुरभुरा करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन बना वो चिपचिपा ही था। इसकी जड़ का मुझे तब पता चला, जब काजीरंगा के पास बने एक धान म्यूजियम में गया। उधर, धान की और नहीं तो कम से कम 60 किस्में हैं, जो साल भर उगाई जाती हैं। अपनी ओर का चावल आराम से तीन साल तक खाया जा सकता है, उधर का चावल छह महीने में खाकर खत्म करना होता है, फिर वह खराब हो जाता है। अब नया चावल पकता है तो हर कोई अवधियों जितनी मेहनत करना नहीं चाहता। मुझे लगता है, इसलिए चिपचिपे भात को फैशन बनाया जा रहा है, कम से कम पानी ज्यादा हो जाने की माफी तो नहीं मांगनी पड़ेगी!

एकदा

ग़ुलाम की गोद में

1832 की बात है। मॉस्को के एक गांव में 11 साल का एक बच्चा फेड्या रहता था। एक दिन वाग में बच्चों के साथ छुपम-छुपाई के दौरान वह एक पेड़ के पीछे छुपा था। अचानक उसने एक जोर की आवाज सुनी, 'भेड़िया! भेड़िया!' यह सुनकर फेड्या बुरी तरह से डर गया। वह बाग के बाहर एक खुले मैदान में धूप की ओर तेजी से भागा। भागते-भागते उसने एक आदमी से मदद मांगी, जो वहां हल जोत रहा था। उस आदमी ने तुरंत काम बंद किया और वो फेड्या के पास दौड़ा आया। उसने फेड्या को गोद में उठा लिया और बोला, 'सब ठीक है बेटा। देखो, यहां कोई भेड़िया नहीं है। लगता है कि किसी ने तुम पर कोई चाल चली है।' फेड्या ने अपने आंसू पोछे और घर जाने लगा। जिस व्यक्ति ने उससे इतनी दयालुता से बात की थी, वह उसके पिता के गुलामों में से एक था। अब फेड्या सोचने लगा, क्या गुलामों में अन्य मनुष्यों की तरह ही भावनाएं होती हैं? फेड्या के पिता एक बहुत जालिम जमींदार थे। वह अपने दासों को छोटे-छोटे अपराधों पर भी कोड़े मारते थे। कभी-कभी तो फेड्या की मां ही गुलामों की जान बख्शने के लिए पिता से याचना करती थीं। उस दोपहर फेड्या की गुलाम के साथ मुलाकात से पहले उसे ऐसा कभी लगा ही नहीं था कि मनुष्य को कोड़े मरना क्रूर था। उसने तय कर लिया कि वह पूरा जीवन इस क्रूरता के खिलाफ लड़ेगा। यही फेड्या बड़ा होकर रूस का महान लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की कहलाया, जिसे रूसी जमींदारों की क्रूरता के बारे में लिखने के लिए जेल तक भेजा गया।

संकलन : अर्चना शर्मा

परंपरा के नाम पर सास-बहू के रिश्ते को नए जमाने की बयार से वंचित रखना किसी का भला नहीं करेगा

बदलाव के रिश्तों की महक से बचेगा कल्चर

नमिता जोशी

कहानी शुरू होती है एक हाथी और उसकी Ultra-thin रस्सी से। जब हाथी छोटा था, उसे मोटी जंजीरों में बांधा गया। बेचारे ने बड़ी कोशिश की, लेकिन हर बार हार माननी पड़ी। धीरे-धीरे उसके दिमाग में ठूंस दिया गया कि 'भैया, तुमसे ना हो पाएगा!' अब जब वह हाथी पहलवान बनकर तगड़ा हो गया, तब भी पतली सी रस्सी में बंधा रहता क्योंकि उसके हार्डवेयर में 'ट्राई मत करो' इनस्टॉल हो चुका था। अब इसी हाथी को सास-बहू के रिश्ते पर apply कीजिए। बहू घर आएगी तो सबसे पहले 'परंपरा और संस्कृति' की मोटी जंजीरें उसके गले में लटका दी जाएंगी- बेटा, घर की इज्जत मायके नहीं ले जानी! हमारे खानदान की बहुएं जींस नहीं पहनती हैं। नौकरी? हमारी बहुएं नौकरी नहीं करतीं। तुम्हारी कमाई थोड़े ही खाएंगे! पति ने मारा है तो क्या, प्यार भी तो करता है।

मेंटल रेप की जकड़न | ये सारे तर्क और लेक्चर उस बहू के mental hardware में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। फिर जब वह अपनी रस्सी तोड़ने की कोशिश करती है तो समाज उसे ही गलत ठहराता है। धीरे-धीरे वह पलती सी 'mental rope' से बंध जाती है, जिसका नाम है - 'यह हमारी परंपरा है!'

कर्म और परिवर्तन | अब जरा गीता और वेदांत को बुलाइए, क्योंकि ये हमेशा कर्म और परिवर्तन की बात करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है - *न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति।* (अध्याय 4, श्लोक 38) इसका अर्थ यही है कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। समय के साथ, व्यक्ति जब सही मार्ग पर चलता है तो ज्ञान उसे अज्ञानता से मुक्त करता है। गीता कहती है, अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़ो। अगर सास-बहू का रिश्ता रूढ़ियों और झूठी परंपराओं में उलझा है तो इसे ज्ञान के प्रकाश से ही सुधारा जा सकता है।

नकली रिश्ते क्यों ढोएं | कृष्ण कहते हैं कि बदलाव और ज्ञान ही जीवन की असली कुंजी है। तो जब भगवान श्रीकृष्ण खुद कह रहे हैं कि ज्ञान के आने पर पुरानी जंजीरों को तोड़ो, तो फिर ये quality control में फंसी परंपराएं क्यों हमें रोक रही हैं? क्यों हम बहुओं पर थोपी गई उम्मीदों के इस नकली रिश्ते को ढोए जा रहे हैं?

विकास की राह का रोड़ा | वेदांत भी कहता है कि समाज और संस्कृति को समय के साथ बदलना चाहिए। अगर कोई परंपरा समाज के विकास में बाधा डालती है, तो उसे बदलना ही चाहिए।

क्या कहती है आधुनिकता | अब थोड़ा आधुनिकता लाते हैं और इतिहासकार युवाल नोआ हरारी की बात करते है। अपनी मशहूर किताब 'Sapiens' में हरारी लिखते हैं - Culture is constantly changing. It evolves as humans invent new ideas, technologies, and systems of cooperation. यानी संस्कृति कभी स्थिर नहीं होती। वह हमेशा बदलती है। जब समाज नए विचारों, तकनीकों और विचारधाराओं को अपनाता है तो पुरानी परंपराएं या तो खत्म हो जाती हैं या फिर नए सांचे में ढल जाती हैं।

कल्पित हकीकत | समाज और परंपराएं भी imagined realities पर आधारित होती हैं। जैसे धर्म, राष्ट्र और सामाजिक संरचनाएं। समय के साथ जब ये कल्पित वास्तविकताएं पुरानी हो जाती हैं या समाज के लिए बाधा बनने लगती हैं, तो नए मिथक और नए विचार जन्म लेते हैं। सास-बहू का रिश्ता भी इसी evolution का हिस्सा है। पुरानी सासें, बहुओं को बेटियां बनाने की जगह 'घर की इज्जत का पहरेदार' बना रही हैं, वहीं कुछ तबकों में नई सासें ऐसी भी हैं जो बहुओं के साथ Netflix and Chill कर रही हैं।

गर्म चाय वाली गॉसिप | अब सोचिए, जिन सास-बहू रियलिटी शो वाले घरों में हर सुबह खौंचतान हो रही है, वो आखिर किसकी जीत है? थोपी हुई उम्मीदों वाले इस तरह के सास बहू के नकली रिश्ते में अगर बहुएं हाथी की तरह बैठी रहेंगी तो culture vultures (संस्कृति के गिद्ध) यही कहेंगे – यह तो हमारी महान परंपरा है! हालांकि राहत की बात यह है कि समय बदल रहा है, और सास भी! अब कुछ घरों में सास-बहू के बीच कोल्ड वॉर की जगह 'गर्म चाय वाली गॉसिप' ने ले ली है। कई सासें बहुओं को बेटियों की तरह मान रही हैं और बहुएं भी सासों के साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह बातें शेयर कर रही हैं। आखिरकार, जब दोनों तरफ से कमेंयोग और समझदारी का सूरज निकलेगा, तब रिश्ते की पतली रस्सी टूटेगी और वह मजबूत दोस्ती की डोर बनेगी।

बदलाव की गीता | गीता कहती है – बदलाव आवश्यक है। वेदांत कहता है – पुरानी बेड़ियों को छोड़ो। हरारी कहते हैं – परंपरा को Re-imagine करो तो हम और आप किन परंपराओं से जकड़े रहना चाहते हैं? अब आपको तय करना है कि आप हाथी बनकर रस्सी से बंधे रहेंगे या फिर बदलाव की गीता गाएंगे। सास और बहू के बीच खींचतान को संस्कृति का नाम देने वाले culture vultures को एक चाय पिलाइए और कहिए - संस्कृति आपकी बातों से नहीं, हमारे रिश्तों की खुशबू से जिंदा रहेगी! बदलाव संस्कृति की आत्मा है। सास-बहू के रिश्ते को battlefield नहीं, Bollywood movie बनाइए!

हमेशा साथ रहेगी स्वेटर की स्नेह भरी गर्माहट

साल के 9-10 महीने जब घर की सबसे कम खोली जाने वाली अलमारी के कोने में दुबक कर बिताने हो, तो याददाश्त का कसूर नहीं। सबको उनकी याद अचानक ही आती है। इसमें न उन स्वेटर का कसूर है और न हमारे यहां पड़ने वाली लंबी गर्मियों का। वैसे भी कहा गया है कि जीवन लंबा नहीं बड़ा होना चाहिए, तो हमारा स्वेटर इसी फलसफे पर चलता रहा है। जितने दिन अलमारी के बाहर बीतते हैं उसके, उतने दिन बस उसके ही होते हैं। फिर तो कोई दूसरा कपड़ा चाहे कितना भी महंगा और डिजाइनदार क्यों न हो, अपने आगे चलने नहीं देता। बहुत हुआ, तो शर्ट जरूर कॉलर बाहर निकाल कर मौसम का अंदाजा ले लेती है, वरना तो सर्दियों में सब पर भारी हैं स्वेटर।

हम सभी की बचपन की यादें कई रंगीन तस्वीरों से भरी होती हैं। इनमें कोई न कोई तस्वीर स्वेटर की जरूर होगी। मां, नानी, दादी या किसी और के हाथों में तेजी से चलती सलाइयां और उनके इशारे पर आकार लेता ऊन। लगता कि कोई जादूगर हाथ की सफाई दिखा रहा हो। यही जादू देखा होगा इटली के चित्रकार Tommaso da Modena ने करीब 700 साल पहले अपने बचपन में। और जब वह कूची संभालने लायक हुए तो यादों से वह तस्वीर निकाली और अपनी प्रसिद्ध कृतियों में से एक 'Our Lady Knitting' रच डाली। इस पेंटिंग में बुने जा रहे स्वेटर का लाल रंग आज तक हल्का नहीं पड़ा है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 13वीं सदी के मध्य में स्पेन के शाही परिवारों ने मुस्लिम बुनकर नियुक्त किए थे। इसी वक्त के आसपास के स्पेनिश कैथेड्रल के पुराने सामानों को जब खोला गया, तो उसमें ऊन से बने कुछ कपड़े भी मिले थे। ऐसे ही कपड़े मिले थे स्पेन के राजकुमार Fernando de la Cerda के मकबरे में भी, हाथ से बुने हुए।

AI Image

जीवन आनंद

शैलेंद्र पांडेय

स्वेटर की मुलायम गर्माहट हमें तब से मिलती आ रही है, जब उसे यह नाम भी नहीं मिला था। इस गर्माहट के साथ मिला होता है प्यार, अपनापन, ममता। कहते हैं कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मछुआरे जब समुद्र में निकला करते, तो लहरों के साथ उन्हें ठंडी हवाओं की चुनौती भी झेलनी पड़ती। उनके घर की महिलाओं ने तब स्थानीय भेड़ों के ऊन से मोटे-मोटे स्वेटर बुने, जिन्हें Aran sweaters कहा जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली ऊन को तेल में भिगोया जाता था ताकि उससे बना स्वेटर वॉटरप्रूफ जैसा हो जाए। 19वीं सदी की शुरुआत के इस प्रयोग ने न जाने कितने मछुआरों को ठंड के प्रकोप से बचाया होगा!

यह इतिहास लिपटा है स्वेटर के हर रेशे में। सर्दियों की शुरुआत में जब अलमारी से स्वेटर बाहर निकलते हैं, तो साथ निकलने वाली कपूर की गोलियों की गंध इतिहास की तरह ही अतीत की कई खिड़कियां खोल देती है। स्वेटर सबूत है उन चीजों का, जिन्हें सभ्यता और संस्कृति के परे अपनाया गया। अमेरिकियों ने 19वीं सदी के आखिर में इन्हें अपनाया ऐथलीट्स को गर्म रखने के लिए। सैनिकों ने अपनाया विश्व युद्ध के दौरान और फैशन ने अपनाया 20वीं सदी में। हमारे-आपके बीच ये पहुंचे थे उपनिवेश की निशानी बनकर, लेकिन फिर बिल्कुल देसी बनकर रह गए।

कभी स्वेटर केवल हाथ से ही बुने जाते थे। फिर मशीनें आईं और हाथों से बुनना जरूरत की जगह शौक बन गया। आज यह शौक भी बहुत कम लोगों को लगता है, लेकिन इससे स्वेटर की अहमियत कम नहीं हो जाती। उसकी स्नेह भरी छुअन हमेशा महसूस होती रहेगी, चाहे वह अलमारी में ही बंद क्यों न हो।

शेयर करें अपने अनुभव

जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और सब्जेक्ट में लिखें- 'जीवन आनंद'

रीगनवाद की झलक है ट्रंपवाद में

मृत्युंजय राय

'क्या रीगनवाद में ट्रंपवाद के बीज छिपे थे?' REAGAN: His Life and Legend अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रॉनल्ड रीगन की जीवनी की प्रस्तावना में इसके लेखक मैक्स बूट ने यही सवाल किया है। बूट यह सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि जिस तरह से आज उदारवादी खेमा ट्रंप को पसंद नहीं करता, उसी तरह से वह रीगन को भी पसंद नहीं करता था। रीगन की तरह ट्रंप भी रिपब्लिकन पार्टी के लीडर हैं। रीगन 1981 से 1989 तक लगातार दो टर्म राष्ट्रपति रहे, जबकि ट्रंप का पहला कार्यकाल 2016 से 2020 तक रहा और दूसरा 2025 में 20 जनवरी से शुरू होने जा रहा है।

AI Image

विचार विंडो

दोनों में कई समानताएं है। जिस तरह से ट्रंप वोक कल्चर के खिलाफ हैं और उदारवादियों पर हमला बोलते रहते हैं, उसी तरह से रीगन भी कम्युनिस्टों के खिलाफ थे। दोनों राजनीति में आने से पहले सिलेब्रिटी भी रहे। रीगन जहां हॉलिवुड के अभिनेता थे, वहीं ट्रंप रियलिटी शोज में आ चुके हैं। बूट ने इसमें रीगन के बारे में जो तस्वीर खींची है, उससे ट्रंप और उनके बीच एक और कॉमन चीज सामने आती है। जिस तरह से ट्रंप गलतबयानी करते हैं और विरोधियों के तथ्य पेश करने के बाद भी अपनी बात से पीछे नहीं हटते, कुछ वैसा ही हाल रीगन का भी था। इस बारे में मिसाल देते हुए बूट लिखते हैं कि रीगन को लगता था कि ग्रेनाडा में सोवियत संघ एयर बेस बना रहा है, जबकि इसका कोई सबूत सामने नहीं आया था। फिर भी अपने फितूर में उन्होंने इस द्वीप पर हमले का आदेश दे डाला।

रीगन ने कई सोशल प्रोग्राम के बजट में कटौती की, जिसे लेकर विरोधी उन पर क्रूर और बेदर्द होने का इल्जाम लगाते। विरोधी यह भी ध्यान दिलाते कि रीगन बातें तो राजकोषीय अनुशासन की करते है, लेकिन उनके राज में सरकारी घाटा बढ़ रहा था। विरोधियों को सबसे ज्यादा आशंका इस बात की थी कि वह परमाणु युद्ध छेड़ सकते हैं। बूट लिखते हैं कि भले ही 80 के दशक की तस्वीर ऐसी हो, लेकिन आज रीगन को कई इतिहासकार भावुक होकर याद करते हैं। ये मानते हैं कि रीगन ने कई असरदार कदम उठाए और उसके नतीजे भी अच्छे रहे। बूट बताते हैं कि रीगन यूं तो संघीय सरकार के ताम्झाम के कड़े आलोचक थे, लेकिन उनके राष्ट्रपति काल में इसका विस्तार ही हुआ। यानी इस मामले में उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर था। इसी तरह की एक और मिसाल वह देते हैं कि रीगन यूं तो कंजर्वेटिव लीडर थे, लेकिन जब वह कैलिफोर्निया के गवर्नर थे तब उन्होंने अबॉर्शन लॉ में ढील दी।

किताब में करीब आधा हिस्सा रीगन के जीवन की उस अवधि को दिया गया है, जब वह राष्ट्रपति नहीं बने थे। बूट लिखते हैं कि रीगन के पिता शराबी थे। बार-बार परिवार के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की वजह से रीगन का बचपन तन्हा रहा था। स्कूली शिक्षा के दौरान रीगन के न वॉर्नर ब्रदर्स की फिल्मों में रीगन अक्सर दिखने लगे, लेकिन बूट के मुताबिक, उनमें उतनी अभिनय प्रतिभा नहीं थी। रीगन की अभिनेत्री जेन वायमैन से पहली शादी लंबी नहीं चली। फिर वह ऐक्ट्रेस नैंसी डेविस के करीब आए और दोनों ने मार्च में शादी कर ली। बूट एक अडवाइजर के हवाले से लिखते है, 'नैंसी के बगैर रीगन सफल राजनेता नहीं बन पाते।' किताब में लिखा है कि नैंसी ने अमीर कारोबारियों का नेटवर्क तैयार किया, जिन्होंने रीगन के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमकर डोनेशन दी। कुल मिलाकर, रीगन की इस जीवनी से उनके बारे में तो दिलचस्प जानकारियां मिलती ही हैं, यह भी पता चलता है कि आज अमेरिका जिस हाल में है, वहां तक कैसे पहुंचा और किस तरह से ट्रंपवाद के बीज रीगनवाद ने डाले।

यह तो अंगड़ाई है...

प्रणव प्रियदर्शी

2019 का लोकसभा चुनाव इस मायने में खास रहा कि इतिहास में पहली बार वोट देने के मामले में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ा। उस चुनाव में 67.02% पुरुषों ने मतदान किया था तो 67.18% महिलाओं ने। वोट प्रतिशत का यह अंतर बता रहा था कि आधी दुनिया की लोकतांत्रिक चेतना अंगड़ाई ले रही है और उसे अब परिवार का मुखिया सोच-समझदारी पर अपने कथित एकधिकार या संस्कृति की महानता या परिवार-खानदान की इज्जत – किसी भी हथियार से ज्यादा समय तक नियंत्रित नहीं रख पाएगा। इस बात की पुष्टि आगे के चुनावों में हुई। राजनीतिक दलों की नजरों से यह तथ्य छुपा नहीं रह सका। उन्हें समझ आ गया कि एक वोटर समूह के रूप में महिलाओं की स्वतंत्र चेतना इतनी विकसित हो चुकी है कि उसे सीधे संबोधित किए बगैर काम नहीं चलेगा। इसी हफ्ते दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने भी वही दांव चला जिसके सहारे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सरकार हाथिया विधानसभा चुनावों में कामयाबी के झंडे गाड़े थे। दिल्ली में AAP और सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी सत्ता में वापसी करती है तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत मिलने वाली 1000 रुपये महीने की सहायता को बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। किस्स बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, आज की तारीख में उस राज्य महिलाओं को सीधे रकम हस्तांतरित कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह रकम सालाना 1.8 लाख करोड़ रुपये बैठती है जो इन राज्यों के संयुक्त GSDP का 0.8% और देश के GDP का 0.6% है। करीब 11 करोड़ महिलाएं इनका फायदा ले रही हैं। इसमें दो राय नहीं कि बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं अभी नहीं हैं, लेकिन हाथ में पैसा आना जहां इन महिलाओं को व्यक्तिगत तौर पर आत्मविश्वास दे रहा है वहीं परिवार और समाज में उनकी हैसियत भी बढ़ा रहा है। पितृसत्ता की जंजीरें अगर झंकारी जा रही हैं तो क्या आश्चर्य!

AI Image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ हमें आगे बढ़ाती है शाम

जीवन आनंद कॉलम में प्रकाशित लेख 'अंधेरे से लड़ने का हमें मौका देती है शाम' (9 दिसंबर) ने केवल विचारों की गहराई में ले जाता है, बल्कि जीवन के संघर्ष और समाधान को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा भी देता है। लेखक ने बहुत खूबसूरती से शाम को जीवन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। गुलाबी रोंद की चमक और उसकी कठिनाइयों के माध्यम से जीवन के संघर्षों की बारीकियों को समझाना बेहद प्रभावशाली है। शाम ठहरने का नाम नहीं, आगे बढ़ने का समय है। यह बताता है कि हर अंधेरा हमें उम्मीद और नए अवसरों के लिए तैयार करता है।

सोनिया साहा, भजनपुरा

■ मिली-जुली संस्कृतियां

14 दिसंबर को प्रकाशित सप्ताह का इंटरव्यू 'संस्कृति में आ रहे बदलाव वापस नहीं होंगे' पढ़ा। अमिताव कुमार ने जिस तरह से गिरते हुए पत्ते और गंगा की धाराओं का उदाहरण देकर जीवन और समाज की जटिलताओं को सरल तरीके से समझाया है, वह बेहद प्रभावशाली है। उनका यह कहना कि हमारी जिंदगी मिली-जुली है और सारी धाराएं मिश्रित हैं, न केवल हमारे सामाजिक ताने-बाने को दर्शाता है, बल्कि हमें एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देता है। गंगा और मणिकर्णिका घाट का उनका जिक्र हमें मृत्यु और जीवन के बीच के अटूट संबंध को समझाता है।

अमित यादव, शाहदरा

■ किसानों की अनदेखी

पिछले दिनों जिस तरह से शंभु बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में झड़प हुई है, वह देखकर मन व्यथित है। शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे 17 किसान घायल हो गए। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले किसान पिछले कई वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह किसानों के मुद्दों का शीघ्र समाधान निकाले।

यशपाल सिंह, नरेला

जीवन आनंद

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

अब एयरपोर्ट पर सस्ती चाय-कॉफी-एक खबर

– सस्ती चाय के साथ महंगी फ्लाइट का मजा लीजिए!

राशिद अली

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

ब्रह्मांड का सत्य समझना है तो शिकायतें बंद करें

गोपाल अग्रवाल

हमारी आंखें खुली हैं, फिर भी हम देखते नहीं हैं। हमारे चारों ओर विशाल जीवन है, एक अनंत शो जो लगातार चल रहा है। यह ब्रह्मांड, यह जीवन, इस शो का आनंद ले रहे हैं। मगर क्या हम इस शो का आनंद ले रहे हैं? शायद नहीं। हम शिकायतों, तनावों और उलझनों में इतने घिरे हुए हैं कि हमें इस अद्भुत शो का एहसास ही नहीं होता, जो हमारे सामने चल रहा है। जब तक हम शिकायत करना बंद नहीं करते, यह ब्रह्मांड हमें अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। हमें अपनी नकारात्मकता, अपने संदेहों और अपने भय को पीछे छोड़ना होगा। हमें अपने आप को खोलना होगा, जीवन के साथ संवाद करना होगा, ब्रह्मांड के स्पंदनों के साथ तालमेल बैठाना होगा।

जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो हमें पागल कहलाने के लिए तैयार होना होगा। समाज में जो व्यक्ति अनजाने रास्तों पर चलता है उसे अक्सर पागल ही कहा जाता है। अगर आप सड़क पर चलते-चलते अपने आप से बात करने लगें, तो लोग आपको अजीब नजरों से देखेंगे। वे सोचेंगे कि आप कल्पना कर रहे हैं, वास्तविकता से दूर हैं। सच्चाई यह है कि आप जीवन के साथ गहरी बातचीत कर रहे हैं। हमें सिखाया जाता है कि हमें एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यदि हम उस ढांचे से बाहर निकलकर जीवन के साथ सीधा संवाद करना चाहें, तो क्या गलत है? यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हमारी आत्मा की यात्रा है। जीवन के साथ यह गहन संवाद हमें अपनी आत्मा के गहरे स्तरों तक ले जाता है। यह हमें समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। यह संवाद हमें आत्म-साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जब हम ब्रह्मांड के साथ इस तरह से जुड़ते हैं, तो हमें अहसास होता है कि हम इस विशाल, अनंत चेतना का हिस्सा हैं।

जो भी हम करें या सोचें, हमें समझना होगा कि जीवन का हर कण स्पंदित है। हम भी उसी स्पंदन का हिस्सा हैं। प्रभावशाली, शक्तिशाली, अनंत। और हम है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। यह जान लें कि ब्रह्मांड केवल एक खाली जगह नहीं है। यह ऊर्जा से भरा हुआ है, चेतना से भरा हुआ है। जब हम अपने मन और हृदय को खोलते हैं, तो हम इस ऊर्जा के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं - ये सभी ब्रह्मांड के स्पंदनों के साथ तालमेल बिठा सकती हैं। जब हम सकारात्मकता, प्रेम और आनंद के साथ ब्रह्मांड से संवाद करते हैं, तो वह हमें प्रतिक्रिया देता है। यह प्रतिक्रिया सूक्ष्म हो सकती है, लेकिन गहरी होती है। यह हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है, हमें नए अनुभवों और अवसरों से परिचित कराती है।

शिकायत करना हमारी आदत बन गई है। हम जीवन में जो कुछ भी गलत होता है, शिकायत करते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि यह नकारात्मकता हमें ही नुकसान पहुंचा रही है? जब तक हम शिकायत करते रहेंगे, हम ब्रह्मांड के सकारात्मक स्पंदनों से दूर रहेंगे। हमें स्वीकार करना सीखना होगा। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करें। इससे हम अपने आप को नए अनुभवों के लिए खोल सकेंगे।

[illegible]

8,180 मेगावाट हो गई है देश की कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता। वर्ष 2014 में यह 4,780 मेगावाट थी। परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ और दीर्घकालिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है।

आजकल

ईंधन की जरूरत पूरी करेगी परमाणु ऊर्जा

केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में चार नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। विश्व में जीवाश्म ईंधन के सीमित भंडार तथा उनके उपयोग से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए परमाणु ऊर्जा हमारे भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकती है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी को अधिक से अधिक सुविधाएं देने तथा अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए शहरीकरण के साथ ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना जरूरी है। इसी नजरिये से देश में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है

लंबे समय तक ऊर्जा की आपूर्ति का साधन बन सकते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र। फाइल

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

केंद्र सरकार के उपक्रम परमाणु ऊर्जा निगम ने मध्य प्रदेश में चार नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की मंजूरी दी है। जल्दी ही ये संयंत्र नीमच, देवास, सिवनी और शिवपुरी में लगेंगे। सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। इन संयंत्रों के शुरू हो जाने पर 1200 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली पैदा होगी। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता पिछले 10 साल में करीब दोगुनी हो चुकी है। 2031 तक इसके तीन गुने होने की उम्मीद है।

भारत की जिस तेजी से आबादी और अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके प्रबंधन और सुविधा के लिए शहरीकरण के साथ ऊर्जा की उपलब्धता आवश्यक है। इसी नजरिये से परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन बढ़ाने की दिशा में तेजी से प्रगति हो रही है। विद्युत की कमी पूरी हो और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी न हो, इसके लिए परमाणु ऊर्जा उपयुक्त मानी जाती है। एक बार यदि कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो जाता है तो लंबे समय तक ऊर्जा की आपूर्ति बनी रहती है। ताप विद्युत परियोजनाओं में कोयला जलाया जाता है। इस कारण बड़ी मात्रा में वायु प्रदूषित होती है, जो अनेक बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे अनुमान है कि दुनिया में एक साल में करीब 15 लाख मौतें वायु प्रदूषण से होती हैं। अतः जीवाश्म ईंधन से बिजली पैदा करना मानव आबादी को बीमार बनाए रखना है। जबकि परमाणु ऊर्जा से पैदा बिजली कार्बन मुक्त होने के साथ सस्ती भी होती है। भारत में कुल ऊर्जा के उत्पादन में 80 प्रतिशत बिजली केवल जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला को ताप विद्युत घरों में जलाने से प्राप्त होती है। हालांकि देश में पनबिजली, सौर और पवन ऊर्जा भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने लगी है। जीवाश्म ईंधन के ये बड़े विकल्प बनकर सामने आए हैं, लेकिन सौर और पवन ऊर्जा के उत्सर्जन में मौसम की बड़ी भूमिका रहती है। अतः तेज हवाएं नहीं चलने पर पवन ऊर्जा का निर्माण धीमा पड़ जाता है। इसी तरह बारिश और ठंड के मौसम में सूरज का ताप मंद हो जाने से सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है। परमाणु ऊर्जा के लिए थोरियम की उपलब्धता जरूरी है। यह अच्छी बात है कि भारत में थोरियम केरल और बिहार में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम धातु को वायु में गरम करने पर इससे चिंगारियां फूटती हैं, जो ऊर्जायुक्त होती हैं। भारत में भविष्य के ईंधन के रूप में थोरियम को परमाणु ऊर्जा में बदलने के उपायों पर काम तेजी से चल रहा है। देश में फिलहाल आठ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 23 परमाणु रिएक्टर चालू हैं।

परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने की दृष्टि से लघु परमाणु संयंत्रों के लिए सरकार ने इस साल बड़े बजट का प्रविधान किया है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में यह नया प्रयोग है। इसके तहत पहली बार निजी कंपनियों को लघु परमाणु संयंत्र समूचे देश में स्थापित करने का अवसर दिया गया है। माइयूलर रिएक्टर के आधुनिकीकरण के लिए शोध भी किया जा रहा है। इससे आने वाले दिनों परमाणु ऊर्जा में नई प्रौद्योगिकी का विकास होगा। इसका उद्देश्य देश में स्वच्छ एवं वैकल्पिक बिजली को बढ़ावा देना है। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर निःशुल्क बिजली योजना के तहत छतों पर सौर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इन पर सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट जारी रहेगी। अभी तक इस योजना के लाभ के लिए 1.28 करोड़ परिवार पंजीयन करा चुके हैं और 14 लाख आवेदन विचाराधीन हैं। इस योजना में शामिल लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। छोटे माइयूलर रिएक्टर उन्नत परमाणु संयंत्र माने जाते हैं। इनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति इकाई है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की बिजली उत्पादन क्षमता को तुलना में एक तिहाई है। ये संयंत्र न्यूनतम कार्बन बिजली का उत्पादन करते हैं।

विकसित भारत के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक बड़ी जरूरत है। इसलिए सरकार सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है। इसीलिए सौर और पवन ऊर्जा के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा पर जोर दे रही है। हालांकि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सुरक्षा के सवाल आड़े आते रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सरकार सचेत दिख रही है। इस संबंध में नीतिगत उपाय किए जा रहे हैं। इस नीतिगत उपाय के तहत रोजगार, विकास और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का भी समाधान होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में निकेल, कोबाल्ट, तांबा और लिथियम जैसे धातुओं के उत्पादों के आयात पर शुल्क क्रमशः घटाया जा रहा है। इन उत्पादों का प्रयोग परमाणु और सौर, पवन ऊर्जा आदि के उत्सर्जन से जुड़े उपकरणों में भी होता है। आयात सस्ता होने से इनका निर्माण भारत में करने में आसानी होगी। यही नहीं परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्रों में इस्तेमाल होने वाली 25 धातुओं पर सीमा शुल्क को पूरी तरह खत्म कर दिया है। हाल के वर्षों में कुछ देशों को छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सफलता मिली है। इसी का अनुकरण भारत कर रहा है।

इस साल के आरंभ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के तापी जिले के काकरापार में 22,500 करोड़ रुपये की लागत से बने दो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित किया था। ये देश के पहले स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ये उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त हैं। इनकी बिजली उत्पादन क्षमता 700-700 मेगावाट है। ये संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 10.4 अरब यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन करेंगे। गुजरात में बिजली की आपूर्ति के साथ अन्य प्रांतों को भी बिजली देंगे। ये संयंत्र शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे।

सरकार ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों से भी निवेश आमंत्रित किया है। यह पहल ऐसे स्रोतों से बिजली बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो कार्बनमुक्त हैं। प्रदूषण और तापमान बढ़ाने वाले कार्बन डाईआक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। यह पहली बार है जब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सरकार निजी कंपनियों से पूंजी निवेश की मांग कर रही है। फिलहाल भारत में परमाणु ऊर्जा कुल बिजली उत्पादन की तुलना में महज दो प्रतिशत भी नहीं है। यदि यह निवेश बढ़ता है तो भारत को 2030 तक अपनी स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का 50 प्रतिशत गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग से हासिल करने में सहायता मिलेगी।

भविष्य की जरूरत है स्वच्छ ऊर्जा

देवेंद्रराज सुथार
स्वतंत्र टिप्पणीकार

भारत ने बीते एक दशक में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बड़ी छलांग लगाई है। वर्ष 2014 में जहां देश की कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता 4,780 मेगावाट थी, वह अब बढ़कर 8,180 मेगावाट हो गई है। परमाणु ऊर्जा को स्वच्छ और दीर्घकालिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। जीवाश्म ईंधन के सीमित भंडार और उनके उपयोग से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए परमाणु ऊर्जा हमारे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकती है। सरकार ने 2031-32 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक इसे एक लाख मेगावाट तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है।

इस बढ़ोतरी के पीछे कई महत्वपूर्ण पहल रही हैं। सरकार ने हाल ही में कई नए रिएक्टरों को स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो हमारी ऊर्जा क्षमता को कई गुना बढ़ाएंगे। सर्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम करने से परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास और संचालन में कुशलता आई है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी ने भी इस क्षेत्र को मजबूती दी है। तकनीकी विकास के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत स्माल माइयूलर रिएक्टर और भारत स्माल रिएक्टर जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जो छोटे पैमाने पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी होंगे। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जल्द ही कार्यरत होने की उम्मीद है, जो हमारी परमाणु तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि होगी।

उल्लेखनीय है कि भारत के पास थोरियम के विशाल भंडार हैं, जो दुनिया के कुल थोरियम का लगभग 21 प्रतिशत है। यह परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। 'भवानी' जैसे प्रोजेक्ट के माध्यम से इन भंडारों का उपयोग करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे न केवल ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि आयातित यूरेनियम पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं है। कृषि में इसकी मदद से 70 नई फसली किस्में विकसित की गईं हैं, जो उत्पादन बढ़ाने में मददगार साबित हुई हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैंसर के इलाज के लिए उन्नत रेडियोआइसोटोप विकसित किए गए हैं। वहीं रक्षा के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके हल्की और सस्ती बुलेटप्रूफ जैकेट तैयार की गई है।

परमाणु परियोजनाओं को लागू करने में चुनौतियां भी हैं। भूमि अधिग्रहण, वनों की मंजूरी और उपकरणों की खरीद जैसे मुद्दे इसमें बाधा बनते हैं, लेकिन सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। सरकार की दूरदर्शिता और तकनीकी विकास के बल पर भारत आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा में दुनिया का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। इससे न केवल हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने और सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

खरी-खरी

माननीय के नोट

डा. प्रदीप मिश्र

जैसे ही नोटों की गड्डी मिली, मैं माननीय के पास जा पहुंचा, 'आदरणीय ये नोट आपके तो नहीं?' उन्होंने पूछा, 'कितने हैं?' मैंने कहा, 'एक गड्डी में आखिर कितने होंगे? कुछ हजार ही हैं।' माननीय झल्लाए, 'मुझे हजारिय मान लिया है क्या?'

'फिर कितने नोटों को आप अपना मानेंगे?' सवाल के जवाब में वह बोले, 'देखो मैं अब नोटों की सीमाओं से परे जा चुका हूं।'

'ऐसे में आपको नोट-आधारित सीमाओं का मूल्यांकन कैसे होगा?' इस सवाल से वह गंभीर हुए, 'ऐसा है मित्र कि जो वोट के आराधक होते हैं, उन्हें नोटों के प्रति वीतराग उत्पन्न हो जाता है। मैं अब उसी अवस्था में पहुंच चुका हूं।' उन्होंने नोटों के प्रति निर्लिप्तता दिखाते हुए कहा।

'तो क्या किसी ने आपको बदनाम करने के लिए नोट रखे थे?'

'पहली बात तो यह है कि नोट मिलने से अब किसी की कोई बदनामी नहीं होती। फिर दूसरी बात यह कि नोट किसके पास से पाए जा रहे हैं? पूंजीपति के पास से नोटों की दो-चार गड्डियां मिलें तो कोई विश्वास नहीं करता कि इतने कम नोट उसके होंगे। और वही तुम्हारे जैसे किसी टुटपुंजिए के पास से मिल जाएं तो उसे चौर ठहराने वालों का तांता लग जाता है।'

'नोट आपके किसी जान-पहचान वाले के तो नहीं हैं?'

'जैसा मेरा स्टेटस है और मैं जिस सेक्सवादी में रहता हूं, उसमें मेरे दोस्तों हो नहीं, विरोधियों में भी ऐसा कोई नहीं है, जिसके दिल में नोट पाने की चाहत बची हो। सभी वोट-साधन में संलग्न हैं और नोटों की आकर्षण-परिधि से बाहर जा चुके हैं। हमारे नेटों ने अब सत्ता, शेयर, स्विस, संपत्ति, बहुचर्च...जैसे रूप गढ़ लिए हैं। अब हम नोटों को उनके इन्हीं रूपों में स्वीकार करते हैं। मुझे तो याद नहीं नोटों को मैंने कब स्पर्श किया था?'

'सरकार तो कह रही है कि मामले की जांच करवाएगी?'

'फिर जांच करने वालों की सांच की जांच कौन करेगा?' उनके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभरी और वह वोट-रक्षा अभियान का नेतृत्व करने चले गए।

पोस्ट

जब राहुल गांधी संसद में वीर सावरकर का अपमान कर रहे थे, तब शिवसेना-यूबीटी के सदस्य चुप क्यों थे? क्या महाराष्ट्र ने उन्हें महापुरुषों का अपमान झेलने के लिए संसद भेजा है?
संजय निरुपम@sanjaynirupam

ट्रेविस हेड भारत के लिए फिर सिरदर्द बने। वह सहवाग के लेंथ हेडेड रूप लग रहे हैं। लेथ जल्दी भागना, वही बैट स्पीड एवं वही निडरता। छब्बूटीसी के लिए भारत की इस टेस्ट में जीत जरूरी है।
सुशील दोशी@RealSushilDoshi

अगर रोहित शर्मा कहते हैं कि मोहम्मद शमी के घुटनों में सूजन की समस्या है तो फिर वह क्यों सैयद मुश्ताक अली ट्राफी में खेलते रहे। कोई इस गुत्थी को सुलझा सकता है क्या?
मदनर वेंगणकर@wmakarand

एकलव्य-द्रोणाचार्य की कहानी। 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन। जो अध्यक्ष बनेगा, उसे पीएम बनना था। कांग्रेस की सभी 15 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल का नाम फाइनल किया, मगर गांधी ने वर्किंग कमेटी को आगे रख नेहरू को मनोनीत करवा दिया। एकलव्य का अंगूठा कट गया।
दिलीप मंडल@Profdilipmandal

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या हर्षित राणा और अश्विन की जगह आकाश दीप और रवींद्र जडेजा के वनडे का फैसला सही है?

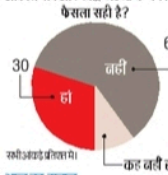

सभी 5 वोटों में प्रतिशत में।

आज तक सवाल

क्या वीर सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी शिवसेना-यूबीटी की मुश्किलें बढ़ाएगी?

परिणाम जागरण फ्रंटपेज संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

दिखलाते हैं रोज वे संविधान ले हाथ,
किंतुन कर पाते कभी संविधान की बात।
संविधान की बात चाहते क्या है कहना,
समझो अपनी बात स्वयं व उनकी बहना।
रहे अढ़ाई साल आम वर्षों से गाते,
लेकर लाल किताब हर जगह हैं दिखलाते।
- ओमप्रकाश तिवारी

हरिशंकर मिश्र
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला महाकुंभ

महाकुंभ...तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ...महात्मय और वैभव का बखान शब्दों में संभव नहीं, बस अनुभूति की जा सकती है और उसे भी अभिव्यक्त करना मुश्किल। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम तट, लहराती धर्मध्वजाएं, अखाड़ों का विचित्र संसार और मंदिरों और धर्म शिविरों से गूंजती वेदों की ऋचाएं एवं संतों के प्रवचन। इस तीर्थराज ने माघ माह में अपनी संपूर्ण आभा के साथ आलोकित होने लहरी तंबुओं में बसी धर्मनगरी के लिए पूरी दुनिया को आमंत्रण दे दिया है-'माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथपतिहिं आव सब कोई। देव दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनीं।' अर्थात माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तो देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य सभी तीर्थराज प्रयाग आ जाते हैं और त्रिवेणी में स्नान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाकुंभ के लिए कुंभाभिषेक करके सभी को आमंत्रित कर दिया है। उन्होंने त्रिवेणी तट पर संगम का नमन कर हर किसी के कल्याण की कामना ही नहीं की, देश की ओर से मुख्य मेजबान होने के अपने कर्तव्य का निर्वहन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह आयोजन महायज्ञ है और इसकी सफलता में वह कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते।

महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक मेला ही नहीं, देश-दुनिया को विश्व कल्याण का संदेश देने का मंच है और इस बार इसकी आभा और भी चमत्कृत करने वाली है। प्रधानमंत्री यहां 13 दिसंबर को लगभग 5500 करोड़ रुपये की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण कर चुके हैं और जाने कितनी और योजनाएं अभी एक माह में पूरी हो जाएंगी। देश का संभवत यह पहला जनपद होगा, जहां एक साथ पांच कारिडोर बनकर तैयार हैं। अक्षयवट, सरस्वती कूप, हनुमान मंदिर, मार्तंड भरद्वाज एवं शृंगवेरपुर धाम कारिडोर के रूप में यहां आने वाले श्रद्धालुओं को अभिनव अनुभूति होगी।

महाकुंभ से पहले प्रयागराज की आभा को और भी चमत्कृत करने का होता प्रयास। फाइल

13 जनवरी को महाकुंभ शुरू होने के पहले ही यहां छह और कारिडोर बन जाएंगे जो यहां के मंदिरों को नया स्वरूप देंगे। देश का यह पहला जनपद होगा, जहां धार्मिक स्थलों को केंद्र में रखकर 11 कारिडोर बनाए जा रहे हैं। प्रयाग की धार्मिक पहचान में अब इनकी भी उपस्थिति विशिष्ट होगी और श्रद्धालुओं को संगम के साथ ही अन्य स्थलों पर जाने का अवसर भी मिलेगा। प्रयागराज को आत्मसात करते हुए पीएम मोदी ने भी कहा कि प्रयागराज एक भौगोलिक भूखंड नहीं है। यह आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों सुलभ हैं, वह प्रयाग है।

प्रयागराज धार्मिकता, ऐतिहासिकता और सांस्कृतिक धरोहर की त्रिवेणी है। यहां त्रेता युग में श्रीराम से जुड़े पौराणिक स्थल हैं तो महाभारतकालीन स्थल भी हैं। पिछले साल 2019 का महाकुंभ लोगों के लिए सुखद अनुभूति प्रदान करने वाला रहा था। स्वच्छता के जो मानदंड उस मेले में स्थापित हुए थे, उसकी गूंज पूरे विश्व में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छताकर्मियों का पैर धोकर सामाजिक समरसता के संदेश को आगे बढ़ाया था। इस बार इसका विस्तार होगा। महाकुंभ के पहले अपने आगमन में उन्होंने आयोजन को सफल बनाने के लिए परिश्रमरत कर्मियों, श्रमिकों और सफाईकर्मियों का अभिनंदन किया है। श्रीराम के वनवास में शृंगवेरपुरधाम एक बड़ा पड़ाव है, जहां केवट ने अपने प्रभु को सामने पाकर उनके पैर पखारे और नदी पार कराई। योगी सरकार ने इस क्षेत्र का चहुंदिक विकास कराया है और यहां श्रीराम और निषादराज की प्रतिमा समता और समरसता का संदेश पूरे देश को देगी। अक्षय वट के दरबाले भी श्रद्धालुओं के लिए खिलेंगे जो उस अमर चेतना का प्रतीक है जो ज्ञान, विज्ञान एवं अध्यात्म के रूप में यहां प्रवाहित है।

प्रयागराज को गंगा मैया का वरदान हासिल है। यह हर छह साल के बाद अर्धकुंभ और फिर कुंभ के माध्यम से विकास कार्यों में फलित होता है। इस बार के महाकुंभ ने प्रयागराज की कनेक्टिविटी को बढ़ाया है। यात्री सुविधाओं के लिए रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट के साथ आरओबी एवं फ्लाईओवर, सड़कों का चौड़ीकरण, सुंदरीकरण और सौंदर्यीकरण की प्रमुख परियोजनाएं साकार रूप में आ रही हैं। प्रयागराज उस त्रिवेणी का अब एक प्रमुख हिस्सा है, जिसकी लहरें काशी और अयोध्या से प्रवाहित होती हैं। इन धर्म केंद्रों से प्रयागराज की कनेक्टिविटी भी ठीक हुई है। इस बार के मेले में आधुनिकता का संगम दिखाई देगा। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए पैटबाट है जो देश की 11 भाषाओं में श्रद्धालुओं को जानकारी उपलब्ध कराएगा। महाकुंभ का ध्येय वाक्य है-सर्वसिद्धिप्रदः कुंभ...अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला और सभी सिद्धियों को प्रदान करनेवाला। यह ध्येय वाक्य ही करोड़ों श्रद्धालुओं की आध्यात्मिक ऊर्जा है।

मंथन

वोटबैंक बनने से बचते मुस्लिम

कौसर जहां
चेयरपर्सन, दिल्ली हज कमेटी

मुसलमान हर चुनाव में भाजपा विरोधी दलों के लिए चुनावी चर्चा के लिहाज से खास हो जाते हैं। उनके दुख-दर्द की बात होती है। उनके लिए वादे होते हैं। समुदाय के धार्मिक नेताओं का सहयोग लेकर वोट हासिल करने का प्रयास होता है। कहीं-कहीं पर बहुसंख्यक मतदाता नाराज न हो जाएं इसलिए गुपचुप कवायद होती है, जैसा आजकल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करती दिख जाएंगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ा सवाल सियासत से ज्यादा उनकी बेहतरी का है। देश के मुसलमान शायद यह समझने भी लगे हैं इसलिए अब उनके लिए भी विकास कोर मुद्दा है। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसी जरूरतें औरों से अलग कैसे हो सकती हैं? जब जरूरतें समान हैं तो वोट का पैमाना भी अब अलग नहीं हो सकता। यही वजह है महाराष्ट्र में मुसलमानों ने एक रास्ता दिखाया है। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि उनको भी अपनी जेब में पैसा चाहिए। खर्च करने की सामर्थ्य चाहिए। बच्चों को अच्छे स्कूलों में तालीम चाहिए। बीमार हों तो अच्छा इलाज चाहिए। अब उन्हें कोरे वादे नहीं ठोस काम चाहिए। उन्हें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और उनके सहयोगियों का तुष्टीकरण माडल नहीं, बल्कि मोदी सरकार और भाजपा-एनडीए के काम वाला संतुष्टीकरण का माडल पसंद आ रहा है। यकीन मानिए यह बदलाव का दौर है।

कांग्रेस की सरकारों ने लंबे समय तक देश पर शासन किया, लेकिन मुस्लिम समुदाय की शिक्षा और रोजगार पर कभी ध्यान नहीं दिया। बस मुसलमानों को डर दिखाकर उन्हें अलग-थलग रखा गया। मुसलमानों की बदहाली की सही मायने में जिम्मेदार कांग्रेस और छद्म सेक्युलरवादी दल हैं। शाह बाने केस में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले को पलटकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं किया गया होता तो आज तीन तलाक खत्म करने के लिए मोदी सरकार को कानून नहीं बनाना पड़ता, लेकिन कट्टरपंथियों को ही कांग्रेस ने आम मुसलमान मान लिया। पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मुस्लिम समुदाय के सशक्तीकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। जबकि कांग्रेस और आप ने केवल प्रतीकात्मक कदम उठाकर उनकी स्थिति को बदतर बनाए रखा।

मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन (पीएम विकास) योजना के तहत 3.59 लाख से अधिक अल्पसंख्यक लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमिता और नेतृत्व कार्यक्रम प्रदान करने के लिए 1,210 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2022 तक निर्मित 2.31 करोड़ मकानों में से 31 प्रतिशत मकान महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में आवंटित किए गए। यूपीए शासन के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के लिए 11,208.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। वहीं मोदी सरकार ने इसे 2019 तक बढ़ाकर 17,715 करोड़ रुपये और 2023 तक 18,539.16 करोड़ रुपये किया। मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार ने 2019 में ट्रिपल तलाक (तलाक-ए-बिद्दा) को समाप्त कर, इसे अपराध घोषित किया। मोदी सरकार ने 'नई रोशनी योजना' के तहत अल्पसंख्यक समुदायों की लगभग 4.35 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया है और उन्हें रोजगार के अवसरों में सहायता प्रदान की। नई मंजिल कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले या मदरसा-शिक्षित व्यक्तियों की शिक्षा का समर्थन करना है। इस योजना के तहत जुलाई 2023 तक 98,712 लोगों ने प्रशिक्षण पूरा किया। वर्ष 2014 से पहले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों में से 5 प्रतिशत से भी कम अल्पसंख्यक आबादी से थे। 2022 तक यह आंकड़ा बढ़कर 10 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गया। जनवरी 2021 तक अल्पसंख्यक समुदायों के 11 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है। मोदी सरकार ने पहली बार मुस्लिम महिलाओं को बिना किसी पुरुष साथी के हज यात्रा की अनुमति दी है।

महाराष्ट्र के मुस्लिम मतदाताओं ने छद्म सेक्युलरवादी दलों को दिखाया आईना। फाइल

आज जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, देश का मुसलमान उनका बिना किसी भेदभाव के सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। आज मुसलमानों को अलग-अलग बहाने लेकर गुमराह करने की कोशिश तेज हो गई हैं। वक्फ के नाम पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दल घोटालों को प्रश्रय देते रहे। वक्फ कानून को लेकर जेपीसी में और समाज में व्यापक चर्चा हो रही है। मुसलमान अब किसी खास एजेंडे से गुमराह नहीं होगा। उसे विकास में अपना हिस्सा चाहिए। रोजगार चाहिए। हुनर चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक चाहिए। उन्हें भी लखपति दीदी बनना है। उनको भी घर के मुखिया के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाना है। घर के लिए मुफ्त राशन और सब्सिडी वाले सिलेंडर से उनको भी वही लाभ पहुंचा है, जो देश की अन्य करोड़ों महिलाओं को। इसलिए अब मुसलमान को वोटबैंक के तौर पर इस्तेमाल करने वालों पर चोट करने का वक्त है।

****

हाँ 63% नहीं 27% — क्या एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था चुनावी राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाएगी?

हाँ 82% नहीं 18% — क्या केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होने से देश में विकास की रफ्तार तेज होगी?

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

एक देश, एक चुनाव

कितनी जरूरत कितनी जहमत

कहा जाता है कि भारत में नेता और राजनीतिक दल हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। इसकी वजह भी है। यहां कभी लोकसभा चुनाव, कभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव और कभी स्थानीय निकायों के चुनाव चलते रहते हैं। लेकिन अब यह बदलने वाला है। अब देश में केंद्र और राज्य सरकारों के चुनाव एक साथ होंगे। इसका मतलब है कि चुनावी खबरों का एक तय मौसम होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने गत गुरुवार को ही एक देश, एक चुनाव से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इन विधेयकों को मौजूदा सत्र में ही संसद में पेश करने का संकेत दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने पहले कार्यकाल से ही एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था अपनाने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं। उनका सोच है कि नेताओं को चार वर्ष तक शासन व्यवस्था और नीतियों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और एक वर्ष राजनीति करनी चाहिए। इससे न सिर्फ सरकारी नीतियों को तेजी से प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा बल्कि व्यवस्था से जुड़े सुधारों को आगे बढ़ाने में भी सहूलियत होगी। एक देश, एक चुनाव मौजूदा राजनीति और देश को किस तरह से प्रभावित करेगा, इसकी पड़ताल ही आज का मुद्दा है...

क्या है एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था

भारत में एक देश-एक चुनाव का मतलब है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी हो। इसके पीछे विचार है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं।

1967 तक एक साथ होते रहे सभी चुनाव

आजादी के बाद वर्ष 1950 में देश गणतंत्र बना। वर्ष 1951-52 से 1967 के बीच लोकसभा के साथ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव पांच वर्ष में होते रहे। वर्ष 1952, 1957, 1962 और 1967 में ये चुनाव हुए। इसके बाद कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य बनाए गए। इसके अलावा लोकसभा को भी समय से पहले भंग किया गया। इसके कारण एक साथ चुनाव का चक्र टूट गया और तब से अलग-अलग चुनाव होने लगे।

महंगे चुनाव : 2024 में राजनीतिक दलों का चुनाव पर खर्च पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब दोगुना हो गया है।

एक साथ चुनाव के आर्थिक प्रभाव

- **+1.5% जीडीपी ग्रोथ**
  - 4.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ेगा सकल घरेलू उत्पाद का आकार
  - यह स्वास्थ्य पर आधे खर्च के बराबर
- **+1.28% राजकोषीय घाटा**
  बढ़ेगा एक साथ चुनावों के दो वर्ष पहले और बाद में
- **+17.67% सरकारी खर्च**
- **-0.5% महंगाई**
- **+0.5% निवेश**

स्रोत: भारत में एक साथ चुनाव पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट, 2024

बढ़ जाएगी जीडीपी की ग्रोथ रेट

कोविन्द कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि सभी चुनाव एक साथ होने पर भारत की राष्ट्रीय रियल जीडीपी ग्रोथ अगले वर्ष 1.5 प्रतिशत बढ़ जाएगी। जीडीपी का 1.5 प्रतिशत वित्त वर्ष 2023-24 में 4.5 लाख करोड़ रुपये के बराबर था। यह रकम भारत के स्वास्थ्य पर कुल सार्वजनिक खर्च का आधा और शिक्षा पर खर्च का एक तिहाई है।

बढ़ेगा सार्वजनिक खर्च

केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होने पर सार्वजनिक खर्च 17.67 प्रतिशत बढ़ जाएगा। अहम बात यह सार्वजनिक खर्च में राजस्व के बजाए पूंजीगत खर्च अधिक होगा। सामान्य तौर पर पूंजीगत खर्च बढ़ने से जीडीपी ग्रोथ को मजबूती मिलती है।

बढ़ेगा राजकोषीय घाटा

चुनावों के बाद सार्वजनिक खर्च बढ़ने का मतलब है कि एक साथ चुनाव के बाद अलग अलग चुनावों की तुलना में ग्रोथ रेट बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव के दो वर्ष पहले और दो वर्ष बाद राजकोषीय घाटा 1.28 प्रतिशत तक बढ़ सकता है।

निवेश पर असर

देश में चुनावों का चक्र लगातार चलते रहने से निवेश को लेकर अनिश्चितता का माहौल बनता है। सभी चुनाव एक साथ होने से जीडीपी के लिए नेशनल ग्रास फिक्स्ड कैपिटल फार्मेशन (निवेश) का अनुमान करीब 0.5 प्रतिशत बढ़ जाएगा।

महंगाई में गिरावट

एक साथ चुनाव होने और अलग अलग चुनाव होने दोनों परिदृश्य में महंगाई कम होती है। लेकिन एक साथ चुनाव होने के परिदृश्य में महंगाई में अधिक गिरावट आती है। यह अंतर करीब 1.1 प्रतिशत का हो सकता है।

अमेरिका में एक साथ होता है चुनाव

जहां तक दूसरे देशों में एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था की बात है, तो इस सूची में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा आदि शामिल है। अमेरिका में हर चार वर्ष में एक निश्चित तारीख को ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। इसके लिए संघीय कानून का सहारा लिया जाता है।

सकारात्मक राजनीति की ओर बढ़ेगा देश

हर्षवर्धन त्रिपाठी
राजनीतिक विश्लेषक

लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से उत्तर- दक्षिण और पूरब- पश्चिम के आधार पर विभाजनकारी मुद्दों को हवा देना राजनीतिक दलों को भारी पड़ सकता है। इससे उनको सकारात्मक राजनीति की ओर रुख करना पड़ेगा और सांप्रदायिक राजनीति पर भी अंकुश लगेगा

भारत सरकार एक देश, एक चुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर दिख रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली समिति ने मार्च में ही सुझाव दे दिए थे। अब कैबिनेट ने उसे स्वीकृति देकर और संसद में प्रस्तुत करने की मंशा के साथ यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार एक देश एक चुनाव पर आगे बढ़ चुकी है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इससे राजनीति किस तरह से बदलने वाली है। मेरा मानना है कि व्यावहारिक तौर पर इसे लागू करने में बहुत मुश्किलों के बावजूद अगर इसे लागू कर लिया गया तो कई तरह की समस्याओं से देश को मुक्ति मिल सकती है और अमृतकाल में भारत के अगले 25 वर्षों की विकास यात्रा का प्रवाह बेहतर हो सकेगा। राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है, लेकिन विधानसभा चुनावों में स्थानीय मुद्दे प्रभावी हो जाते हैं। स्थानीय मुद्दों का लोकसभा चुनावों में भी प्रभावी होना ही चाहिए, लेकिन स्थानीय मुद्दों को हवा देकर राज्य विशेष में राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले मुद्दों को भी हवा दी जाती है। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने से राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दों पर भी जनता मत डालेगी, लेकिन देश के भीतर ही उत्तर-दक्षिण-पूरब-पश्चिम का भेद कराकर किसी राज्य विशेष में चुनाव जीतने का प्रयास राजनीतिक दलों पर भारी पड़ सकता है। एक साथ चुनाव होने से जातीय और क्षेत्रीय भेद को भी हवा देने से राजनीतिक दल बचेंगे। इसको ऐसे भी माना जा सकता है कि राजनीतिक दल और राजनेता सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ने के लिए बाध्य हो सकते हैं। हिंदू-मुसलमान या कहें कि सांप्रदायिक राजनीति से भी देश को बहुत हद तक राहत मिल सकती है। चुनावों के समय राहत इंदौरी की यह पंक्तियां खूब कही जाती हैं, 'सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? पता तो करो चुनाव है क्या?' यह सिर्फ सरहदों के लिए ही नहीं है। देश में भी चुनाव के समय अतिरिक्त तनाव होता है। एक साथ लोकसभा-विधानसभा के चुनाव हो जाने और 100 दिन के भीतर निकायों के भी चुनाव हो जाने से तनाव भी बहुत तक कम हो सकता है। एक देश, एक चुनाव से राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ होने की बात कहकर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध करती हैं, लेकिन सच यह है कि यह नुकसान उन्हीं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को होगा, जो जातीय भेद के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने का एक बड़ा लाभ यह भी हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों की दलबदलू प्रवृत्ति पर भी कुछ रोक लगे। एक देश, एक चुनाव में सरकारें गिराने पर बचे हुए समय के लिए ही सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे एक दल से चुनाव जीतकर दूसरे दल में शामिल होने की प्रवृत्ति पर कुछ अंकुश लग सकता है। एक साथ चुनाव होने से चुनाव में धनबल के दुरुपयोग को भी बहुत हद तक रोका जा सकता है। राज्यों के चुनाव से ठीक पहले उसी राज्य में विकास परियोजनाओं के ऐलान का पिटारा खुल जाता है। इस विसंगति से भी मुक्ति मिलेगी। विकास के मामले में हर राज्य की जरूरतें एक सी ही होती हैं। राज्यों के बीच विकास के मोर्चे पर भारी असमानता है विकसित भारत के रास्ते पर आगे बढ़ने में हम पिछड़ गए। पिछले दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के हर राज्य में विकास का प्रवाह एक समान करने की कोशिश की है, लेकिन चुनावी राज्यों में परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इस सरकार में भी अलग से स्पष्ट दिखता रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि एक देश, एक चुनाव से भारत की राजनीति 'हम भारत के लोग' के लिए होगी।

आपकी आवाज

एक साथ चुनाव की व्यवस्था से अर्थतंत्र और लोकतंत्र दोनों होंगे मजबूत

एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था की ओर देश आगे बढ़ चुका है। इसके लिए कानून में कुछ बदलाव करने होंगे। सरकार इसके लिए जरूरी कदम उठा रही है। आइये इस बात को समझते हैं कि एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था से देश को क्या लाभ हो सकते हैं।

आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा एक बड़ी बचत के रूप में होगा। एक दिन में पूरे देश में चुनाव कराने से पोलिंग पार्टियों और सुरक्षाकर्मियों के आवागमन पर आने वाला खर्च कम होगा। इसके अलावा मतगणना के लिए तैयार किए जाने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर की लागत भी कम होगी। इस रकम का इस्तेमाल और सड़कें, पुल बनाने व बिजली की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जा सकता है। सरकारी खर्च कम होने के अलावा, सभी चुनाव एक साथ होने से राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों का खर्च भी कम होगा। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनावी चंदे के लिए अमीर लोगों और कारपोरेट के पास नहीं जाना होगा। इस तरह वे ज्यादा स्वतंत्र होकर लोगों के हित में काम कर सकेंगे। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। एक साथ चुनाव होने से सरकारें लंबी अवधि के नजरिये से सोच सकेंगी। इससे वे चुनावी वर्ष को छोड़ कर बाकी समय सरकारी अधिकारियों को ज्यादा प्रभावी तरीके से नियंत्रित कर सकेंगी और पूरा ध्यान सरकारी मशीनरी के काम व निगरानी पर लगा सकेंगी। इसके अलावा नागरिक सेवाओं के अधिकारी भी ज्यादा स्वतंत्रता के साथ काम कर सकेंगे। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने का एक और फायदा यह होगा कि मतदाता देश और राज्य दोनों के मुद्दों के बारे में बेहतर समझ विकसित कर पाएंगे। वर्तमान में जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार सिर्फ राज्य के मुद्दों की बात करते हैं। एक साथ चुनाव होने से मतदाताओं को राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार करने का मौका मिलेगा। इससे वे ज्यादा जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। एक साथ चुनाव होने से न्यायपालिका भी नियमित मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी। अलग अलग चुनाव होने से चुनावी याचिकाओं की बाढ़ आ जाती है इससे सामान्य मामलों के निस्तारण में बाधा आती है। एक साथ चुनाव होने से चुनाव से जुड़ी याचिकाएं चुनाव के वर्ष ही आएंगी। इससे अदालतों पर काम का बोझ कम होगा।

लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होने से समय समय पर लागू होने वाली आचार संहिता से काम कम प्रभावित होगा। नीतियां बनाने और फैसले लेने के काम में देरी सिर्फ चुनाव के वर्ष होगी, शेष चार वर्षों में प्रशासनिक काम सुगमता से हो सकेगा। इससे विधायकों और सांसदों को लाचल देकर अपने पाले में लाने के मामलों पर भी अंकुश लगेगा क्योंकि इस तरह से बनने वाली सरकारें सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए ही सत्ता में रह पाएंगी। दलबदलू नेताओं को यह बात हतोत्साहित करेगी। देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने भी लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की जरूरत पर जोर दिया है। उनका मानना है कि अलग-अलग वर्षों में चुनाव होने से अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ता है और बड़े पैमाने पर पैसा खर्च होता है।

योगेंद्र नारायण
पूर्व महासचिव, राज्यसभा

एक देश, एक चुनाव की व्यवस्था से मतदाताओं को राज्य के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर राय बनाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इससे सरकारें लंबी अवधि की योजनाओं पर काम कर सकेंगी। इससे अर्थव्यवस्था के साथ लोकतंत्र को भी मजबूती मिलेगी।

राष्ट्रीय फलक

डिजिटल क्रांति से पूरी दुनिया में हिंदी भाषा का महत्व बढ़ा : ओम बिरला

जागरण संवाददाता, इटावा

- हिंदी सेवा निधि के वार्षिक अधिवेशन और सारस्वत सम्मान समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने व्यक्त की राय
- लोकसभा अध्यक्ष बिरला बोले, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का मान बढ़ाया

इटावा हिंदी सेवा निधि के वार्षिक अधिवेशन में उत्कर्ष अग्निहोत्री को सम्मानित करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। बाएं से दूसरे) व सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत सुलिया (दाएं)। जागरण

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि डिजिटल क्रांति के युग में भाष्यांतर-रूपांतरण से पूरी दुनिया में हिंदी भाषा का महत्व बढ़ा है। भारतीय धर्म, अध्यात्म व संस्कृति के प्रसार में हिंदी अहम भूमिका निभा रही है। बहुभाषी और विविध संस्कृति वाले भारत को हिंदी जोड़ती है। हिंदी विविधता में एकता की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए हिंदी भाषा पर सभी को अभिमान होना चाहिए। एक समय था, जब उच्चतम न्यायालय में एक ही भाषा में फैसले सामने आते थे। आज अधिकतर भारतीय भाषाओं में न सिर्फ उच्चतम न्यायालय के फैसले बल्कि संसद में भी 22 भारतीय भाषाओं में पत्राचार हो रहा है। वह रविवार को इस्लामिया इंटर कालेज में इटावा हिंदी सेवा निधि के 32वें वार्षिक अधिवेशन व सारस्वत सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। बिरला ने साहित्यकारों और विविध क्षेत्रों में हिंदी सेवा में उत्कृष्ट योगदान करने वाले 19 हिंदी सेवियों को सम्मानित किया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि डिजिटल की रुचि बढ़ी है। साहित्यकारों, कवियों ने हिंदी के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त कर जन संवाद स्थापित किया। दुनिया में द्विपक्षीय वार्ताओं में अधिकतर देश अपनी भाषा में बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी भाषा में बात करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदी का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने हिंदी को भारत का आत्मा और पहचान बताते हुए कहा कि संविधान निर्माण के समय भी हिंदी के महत्व को स्वीकारते हुए उसे अनेकता में एकता का प्रतीक माना का स्मरण करते हुए कहा कि उनके द्वारा संस्थापित इटावा हिंदी सेवा निधि हिंदी के प्रसार और सम्मान में अविस्मरणीय भूमिका निभा रही है। उन्होंने हिंदी में चार हजार से अधिक फैसले तब लिखे, जब न्यायालयों में हिंदी में कार्य कम होता था।

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यांशु सुलिया ने सुझाव दिया कि हिंदी तभी बढ़ेगी, जब यह सरलता की राह पर होगी। संसद के एक 'कंठस्थ' से अनुवाद अनुसुची की 22 भाषाओं में व सुप्रीम कोर्ट के एप 'सुवास' के माध्यम से

जामा मस्जिद मामले में एएसआइ को जवाब दाखिल करने को मोहलत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने व इसके आसपास का अतिक्रमण हटाने के मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने और समय देने की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) की मांग को स्वीकार लिया। एएसआइ ने न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह व न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ से कहा कि परिसर का मुआयना कर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कुछ समय और दिया जाए। इस पर पीठ ने एएसआइ को 22 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले में याचिकाकर्ता सुहैल अहमद खान और अजय गौतम ने याचिका दाखिल कर जामा मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी के शाही इमाम उपाधि के इस्तेमाल और उनके बेटे को नायब इमाम के रूप में नियुक्त करने पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने और आसपास का सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है। अदालत ने परिसर निरीक्षण के समय एएसआइ संग वक्फ बोर्ड के सदस्य व याचिकाकर्ता प्रतिनिधि के तौर पर अधिवक्ता के

रंगदारी के लिए धमकी देने का ट्रेंड बदला, अब ज्यादा खतरनाक

विनय त्रिवेदी • जागरण

गुरुग्राम : पूर्व जिला पार्षद परमजीत ठाकरान और उनके भाई सुजीत ठाकरान को फरवरी 2022 को रंगदारी के मामले में अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई गिरोह का नाम पहली बार सामने आया था। इससे पहले रंगदारी के मामलों में कौशल चौधरी का नाम आता था। कौशल गिरोह के फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाने का ट्रेंड लारेंस बिश्नोई गिरोह ने भी अपनाया। किंतु अब लारेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ गिरोह का तरीका इससे ज्यादा खतरनाक हो गया है। एक के बाद एक क्लबों के बाहर देसी बम से दहशत पहली बार सामने आई है।

चंडीगढ़ में 26 नवंबर को दो क्लबों के बाहर देसी बम से धमाका किया गया था। इसके 15 दिन बाद 10 दिसंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित दो क्लबों के बाहर भी देसी बम से धमाके किए गए। विदेश में बैठकर गिरोह चला रहे गैंगस्टर रोहित गोदारा की तरफ से 12 दिसंबर को पोस्ट डालकर ली गई। स्वयं ही रंगदारी के लिए धमकी भी दी गई। रोहित लारेंस बिश्नोई व गोल्डी बराड़ के

बम हमले के सूत्रधार की तलाश में छापेमारी

सेक्टर-29 स्थित दलबो के बाहर बम से हमले के मामले में गुरुग्राम पुलिस ने अब तक चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें मेरठ के सचिन व छुर गांव के सचिन, अंकित, मुजफ्फरनगर के सरनावली के विनीत मलिक और सोनीपत के गन्नौर के पांचों के विकास को पकड़ा था। इनसे रिमांड के दौरान पूछताछ चल रही है तो दूसरी ओर इनको बम हमले की जिम्मेदारी देने वाले आरोपित की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। गुरुग्राम पुलिस की एक टीम वेस्ट यूपी के इलाकों में कार्रवाई कर रही है तो एक टीम हरियाणा के अलग-अलग जिलों में तलाशी अभियान चला रही है।

में यह पहली बार हुआ जब रंगदारी के लिए बम से हमले किए गए हों। इससे पहले इन गिरोहों की तरफ से फायरिंग कर दहशत फैलाई जाती थी। किंतु बम से हमला ज्यादा खतरनाक है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गोलीबारी में एक या दो लोग ही निशाना बनते हैं, लेकिन बम से हमले में कई

जेडएसआइ के विज्ञानियों ने खोजीं परजीवी ततैया की पांच नई प्रजातियां

राज्य ब्यूरो, जागरण कोलकाता : भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआइ) के विज्ञानियों ने परजीवी ततैया की पांच नई प्रजातियों की खोज की है। एक अधिकारी ने बताया कि जेडएसआइ के विज्ञानियों ने नगालैंड में परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति 'सेरापाग इनीशियम' की पहचान की है। इसके अलावा जेडएसआइ की एक अन्य टीम ने पश्चिमी घाट में चार अन्य नई प्रजातियों की खोज की है।

परजीवी ततैया एक ऐसा कीट होता है, जो हानिकारक कीटों पर या उनके अंदर अपने अंडे देता है। ततैया प्राकृतिक कीट नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण माने जाता है। यह बागवानी में लाभदायक होता है। जेडएसआइ की निदेशक धृति बनर्जी ने कहा कि परजीवी ततैया की नई प्रजातियों की खोज करना पारिस्थितिक स्थिरता बनाए रखने में इन छोटे जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करता है। जेडएसआइ की निदेशक ने कहा कि यह खोज भारत में प्रचुर जैव विविधता का प्रमाण है और हमारी प्रकृति में जांच और अध्ययन की आवश्यकता पर जोर देती है। यह खोज भारत में कीट प्रजातियों की विविधता तथा हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में इन प्रजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका का